रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D.(D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1983/माघ 23, 1904

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1983/MAGHA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1983

का० आ० 852—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के मुख्य सचिव श्री जगदीश सागर को एतद्द्वारा 1981 की जनगणना के लिए अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में पदेन क्षमता में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

[सं० 11/98/79-प्रशा०-1]

पी० पद्मनाभा, भारत के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 28th January, 1983

S.O. 852.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 of the Census Act, 1948 (No 37 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Jagdish Sagar, Chief Secretary to the Andaman and Nicobar Islands Administration, as ex-officio Director of Census Operations, Andaman and Nicobar Islands, for the 1981 Census.

[No. 11/98/79-Ad. I]

P. PADMANABHA, Registrar General, India

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी 1983

स्टाम्प

का० आ० 853—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 34/82-स्टाम्प, फा० संख्या 33/1/82-बि० क० (स० का० आ० 3775) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में, स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनार्थ उस सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विदेशी

मुद्रा को भारतीय मुद्रा में सम्परिवर्तित करने के लिए, विनिमय की दर निर्धारित करती है :—

सारणी

क्रम संख्या	विदेशी मुद्रा	100 रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर
(1)	(2)	(3)
1	आस्ट्रियन शिलिंग	170 40
2	आस्ट्रेलियन डालर	10 40
3	बेल्जियन फ्रैंक	469. 50
4	कनाडियन डालर	12. 495
5	डेनिश क्रोनर	85. 30
6	डूचे मार्क	24. 18
7	डच गिल्डर	26. 45
8	फ्रेंच फ्रैंक	68. 40
9	हांगकांग डालर	66. 15
10	इतालवी लीरा	13957
11	जापानी येन	2379
12	मलेशियन डालर	23. 70
13	नार्वेनियन क्रोनर	71. 75
14	पौंड स्टर्लिंग	6. 3430
15	स्वीडिश क्रोनर	74. 25
16	स्विस फ्रैंक	20. 29
17	अमरीकी डालर	10. 255
18	सिंगापुर डालर	21. 53

[संख्या 2/83-स्टाम्प-फा० संख्या 33/2/83-वि० क०]
भगवान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th January, 1983

STAMPS

S. O. 853.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34/82-Stamps F. No. 33/1/82-ST (No. S.O. 3775), dated the 25th October, 1982, the Central Government hereby prescribes in column (3) of the Table below, the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corresponding entry in column (2) thereof into the currency of India for the purposes of calculating stamp-duty.

TABLE

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
(1)	(2)	(3)
1.	Austrian Schillings	170.40
2.	Australian Dollaras	10.40
3.	Belgian Francs	469.50
4.	Canadian Dollars	12.495
5.	Danish Kroners	85.30
6.	Deutsche Marks	24.18
7.	Dutch guilders	26.45
8.	French Francs	68.40
9.	Hong Kong Dollars	66.15
10.	Italian Lire	13957
11.	Japanese Yen	2379
12.	Malayasian Dollars	23.70
13.	Norwegian Kroners	71.75
14.	Pound Sterling	6.3430
15.	Swedish Kroners	74.25
16.	Swiss Francs	20.29
17.	U.S.A. Dollars	10.255
18.	Singapore Dollars	21.53

[No. 2/83-Stamps F. No. 33/2/83-ST]
BHAGWAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1983

का० आ० 854.—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विधि सेवा के अधिकारी और भारत सरकार के विधि कार्य विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री पी० बी० वेंकटसुब्रह्मण्यन को समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं० 3/83/फा० सं० 22/22/82-प्रशा० 1(ग)]
सी० एल० खन्ना, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd February, 1983

S.O. 854.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri P. B. Venkatasubramanian, an officer of the Indian Legal Service and formerly Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs, as Chairman, Appellate Tribunal for Forfeited Property.

[No. 3|83|F. No. 22|22|82-Ad. I(C)]
C. L. KHANNA, Desk Officer

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1983

का० आ० 855:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग के का० आ० संख्या 51(ई), 52(ई) और 53 (ई) (संख्या एफ० 1-30/80-आर० आर० बी० (1) एफ० 1 30/82-आर० आर० बी० (ii) और एफ० 1-30/80-आर० आर० बी० (iii) दिनांक 25-1-1982 की अधिसूचना द्वारा स्थापित कार्यी एन० सी० ग्रामीण बैंक का नाम लंगपी देहंगी ग्रामीण बैंक होगा ।

[संख्या एफ० 1-30/80 -आर० आर० बी०]
दिनेश चन्द्र, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Divisions)

New Delhi, the 12th January, 1983

S.O. 855.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (3) of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby notifies that the name of Karbi N. C. Rural Bank established vide Notifications of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Economic Affairs Banking Division S.O. Nos. 51(E), 52(E), and 53(E) (Nos. F. 1-30/80-RRB(I), F. 1-30/80-RRB(I) and F. 1-30/80-RRB(III) dated the 25-1-1982) shall stand changed to Langpi Dehangi Rural Bank.

[No. F. 1-30/80-RRB]
DINESH CHANDRA, Director

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1983

का० आ० 856.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि—(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) और (ii) के उपबंध, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबंध इसके अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक पर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, के निदेशक बनने पर प्रतिबंध लगाते हैं और (ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंध इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के वास्ते उपर्युक्त बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक ये उपबंध भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड में इसके शेयरों की धारिता पर प्रतिबंध लगाते हैं।

[संख्या 15/31/82-बी० ओ०-3]
एल० आर० कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O. 856.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares—(a) that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply for a period of one year from the date of the notification to Allahabad Bank insofar as the said provisions prohibit its Chairman and Managing Director from being the Director of the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd., being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and (b) that the provisions of sub-section (3) of Section 19 of the said Act shall not apply for a period of one year from the date of the notification to the above bank insofar as the said provisions prohibit it from holding shares in the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.

[No. 15/31/82-B. O. III]
L. R. KATARIA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1983

सं. 18/83-सीमाशुल्क

का. आ. 857.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में हिरेहाली औद्योगिक क्षेत्र को भाण्डागारण केन्द्र के रूप में घोषित करता है।

[फा. सं. 473/22/82-सीमाशुल्क-7]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 12th February, 1983

NO. 18/83-CUSTOMS

S.O. 857.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Hirehalli Industrial Area, District Tumkur in the State of Karnataka to be a warehousing station.

[F. No. 473/22/83-Cus-VII]

सं. 19/83-सीमाशुल्क

का. आ. 858.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगना जिले में नईहारी को भाण्डागारण केन्द्र के रूप में घोषित करता है।

[फा. सं. 473/36/83-सी. शुल्क-7]
एन. के. कपूर, अवर सचिव

No. 19/83-CUSTOMS

S.O. 858.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Naihati in 24-Parganas District in the State of West Bengal to be a warehousing station.

[F. No. 473/36/83-CUS.VII]
N. K. KAPUR, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयः मध्यप्रदेश

अधिसूचना सं० 16/82

इंदौर, 24 जनवरी, 1983

का० आ० 859.—मध्य प्रदेश समाहर्तालय, इंदौर के सर्वश्री एच० एस० माहत्मे एवं बी० आर०, काने, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ब' निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर 31-12-82 के अपराह्न से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[फ०सं० II(3)9-गोप/82/121]

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE : M. P.

NOTIFICATION No. 16/82

Indore, the 24th January, 1983

S.O. 859.—S/Shri H. S. Mahatme and B. R. Kane, Superintendents, Central Excise, Group 'B' of Madhya Pradesh Collectorate, Indore, having attained the age of superannuation have retired from Government service in the afternoon of 31st December, 1982.

[C. No. II(3)9-Con/82/719]

अधिसूचना सं० 17/82

का० आ० 860.—अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ब' के पद पर पदोन्नति होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

(प० श्रे०) ने उनके नाम के आगे दर्शाई तिथियों को अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	यू० एस० भट्ट	अधीक्षक (लेखा परीक्षा) कें०उ०शु०मुख्या० इंदौर	29-11-82 (अपराह्न)
2.	एन०एस० कोल्हे	अधीक्षक कें०उ०शु०दमोह 1, दमोह रेंज	22-11-82 (पूर्वाह्न)
3.	वी०टी० लुकाचन	अधीक्षक, के०उ०शु० रेंज-4, सागर	29-11-82 (पूर्वाह्न)
4.	एच०जी० शेंडे	अधीक्षक (निवारक) कें०उ०शु०रायपुर, प्र भाग रायपुर	6-1-83 (पूर्वाह्न)
5.	जी०एस० शर्मा	अधीक्षक, के०उ०शु०, रेंज-1 जबलपुर	31-12-82 (पूर्वाह्न)

[प०सं० II(3)9-गोप/82/122]
एस० के० धर, समाहर्ता

NOTIFICATION NO. 17/82

S.O. 860.—Consequent upon their promotion as Superintendent, Central Excise, Group 'B' the following Inspectors of Central Excise (S.G.), have assumed their charges as Superintendent, Central Excise, Group 'B' with effect from the dates as shown against them.

Sl. No.	Name of the Officer	Place of Posting	Date of assumption of charge
	S/Shri		
1.	U.S.Bhatt	Superintendent (Audit), C. Ex. Hqrs. Office, Indore.	29-11-82 (A.N.).
2.	N.S. Kolhe	Superintendent, C. Ex. Range-I, Damoh.	22-1-82 (F.N.)
3.	V.T. Lukachan	Superintendent, C. Ex. Range-IV, Sagar.	29-11-82 (F.N.)
4.	H.G. Shende	Superintendent (Prev)., C. Ex. Divisional Office, Raipur.	6-1-83 (F.N.)
5.	G.S. Sharma	Superintendent, C. Ex. Range-I, Jabalpur.	31-12-82 (F.N.)

[C. No. II(3)9-Con/82/718]

S.K. DHAR, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1983

का० आ० 861.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० का० आ० 74 में संशोधन करते हुए, कु० रोमा मजुमदार, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), नई दिल्ली, के स्थान पर श्री मणि नारायणस्वामी, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को 15 जनवरी, 1983 से निर्यात निरीक्षण परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है।

[फाईल नं० 3(94)/75-ई० आई० एण्ड ई० पी०]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th January, 1983

S.O. 861.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with Rules 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government in modification of Notification S. O. 74 dated 1st anuary, 1983 hereby appoints Shri Mani Narayanswami, Additional Secretary, Ministry of Commerce as Member of the Export Inspection Council with effect from the 15th January, 1983 vice Kum. Roma Majumdar, Additional Secretary, Ministry of Commerce, (Deptt. of Commerce) New Delhi.

[F. No. 3(94)/75-EI&EP]

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1983

का० आ० 862.—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 455 तारीख 5 फरवरी, 1977 को उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है को अधिक्रान्त करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए डिब्बाबंद मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम, 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2288 तारीख 26 जून, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 जून, 1982 में प्रकाशित किए गए थे;

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 जुलाई, 1982 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है :

अतः केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, इसके द्वारा :—

(1) अधिसूचित करती है कि डिब्बाबंद मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा;

(2) डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1982 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों को लागू होगा;

(3) इस आदेश के उपाबंध में दिए गए विनिर्देशों को डिब्बाबंद मछली तथा मछली उत्पादों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है,

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी भी अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पाद मानक विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात योग्य है,

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि समुद्र या या वायु मार्ग द्वारा निर्यात किए गए डिब्बाबंद मछली तथा मछली उत्पादों के ऐसे नमूनों को लागू नहीं होगी जिसका मूल्य किसी भी समय 1000/- रुपए नमूनों के प्रति परेषण से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पाद से वायुरुद्ध सीलबंद डिब्बों में पैक निम्नलिखित मछली उत्पाद अभिप्रेत है, अर्थात् —

(1) लवण-जल में या अन्तर्राष्ट्रीय रूप में अनुमोदित अन्य किसी माध्यम से या किसी पैक में डिब्बा-बंद किए गए सभी प्रकार के झींगे/श्रिम्प।

(2) केकड़ा जैसे साइलसेरेटा, पोर्टोनस पालाजिकस, नैप्टूनस, पालिजिकस तथा नैप्टूनस सैंग्विनोलेंटस से प्राप्त लवण में या अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से डिब्बा-बंद किया गया केकड़े का मांस।

[सं० 6(4)/80-ई० आई० एण्ड ई० पी०)]

Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India hereby—

(1) notifies that Canned Fish and Fishery Products shall be subjected to Quality Control and Inspection prior to export;

(2) specifies the type of Quality Control and Inspection in accordance with the export of Canned Fish and Fishery products (Quality Control and Inspection) Rules, 1983 as the type of inspection which shall be applied to such Canned Fish and Fishery products prior to their export;

(3) recognises the specifications as set out in the Annexure to this order as the standard specifications for Canned Fish and Fishery Products;

(4) prohibits the export in the course of international trade of such Canned Fish and Fishery Products unless the same are accompanied by certificate of inspection issued by an Agency established or recognised by the Central Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such Canned Fish and Fishery Products conform to the standard specifications and are exportworthy;

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of samples of Canned Fish and Fishery Products to prospective buyers, the value of which does not exceed Rs. 1000 per consignment of samples at any time.

3. In this order Canned Fish and Fishery Products shall mean the following fishery products packed in the hermetically sealed containers, namely ;

(1) All types of prawns/shrimps canned either in brine or any other internationally approved medium or any pack.

(2) Crab meat canned either in brine or any other internationally approved medium, the meat having been obtained from crabs like Scylla serrata, Portunus pelagicus, Neptunus pelagicus and Neptunus sanguinolentus.

[No. 6(4)/80-EI&EP]

ORDER

New Delhi, the 12th February, 1983

S.O. 862.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Canned Fish and fishery products to Quality Control and Inspection prior to export, in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 455 dated the 5th February, 1977, except in respect of things done or ommitted to be done, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India Part II—section 3—sub-section (ii), dated the 19th June, 1982 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2288, dated the 26th June, 1982;

And whereas objections and suggestions were invited within 45 days from the date of publication of the said Order from the persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th July, 1982;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection)

का० आ० 363.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 456, तारीख 5 फरवरी, 1977 में उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है,

(ग) 'डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों' से अभिप्रेत है,--

1. लवण जल में या अन्तराष्ट्रीय रूप से अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से डिब्बा-बंद की गई या शुष्क पैकेजों में सभी प्रकार के झींगे/प्रिम्प ।

2. केकड़ा जैसे माइलासेरेटा, पोटेनिस पेलजिकस तथा नैप्टनस पलाजिकस सैम्निनोलेन्टस से प्राप्त लवण जल में या अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से डिब्बा-बंद किया गया केकड़े का मांस ।

3. क्वालिटी नियंत्रण : निर्यात के लिए आशयित डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों का क्वालिटी नियंत्रण इस दृष्टि से किया जाएगा कि क्या वे प्रसंस्करण विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रण के स्तरों के साथ जैसे इन नियमों से संलग्न अनुसूची-1 में दिए गए हैं निम्नलिखित 3.1 और 3.2 की अपेक्षाओं को प्रभावी करते हुए, अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

3.1 प्रसंस्करण यूनिटों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं : वातावरण, सन्निर्माण और अभिन्यास : डिब्बा-बंदशालाएं और आसपास के क्षेत्र ऐसे होने चाहिएं कि उन्हें आपत्तिजनक गंध, धुएं, धूल, और अन्य संदूषणों से मुक्त रखा जा सके डिब्बा बंद करने वाले यूनिटों के आसपास कोई दलदल, कूड़े का ढेर या पशुओं के रखने के लिए स्थान नहीं होने चाहिए जिससे कोई स्वच्छता संबंधी समस्या उत्पन्न हो। प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी निकटतम पहुंच मार्गों पर जो प्रसंस्करणकर्ता के वास्तविक नियंत्रण में हैं, इस रीति से कंकरीट, तारकोल बिछाया जाना चाहिए या घास उगाई जानी चाहिए कि वायु से धूल न उड़े और अन्य संदूषण न हों। इमारत, उपस्करों या कर्मचारियों की भीड़ न होने देने के लिए पर्याप्त आकार की होनी चाहिए उसकी/उनकी संरचना अच्छी होनी चाहिए जिससे कि कीटों, पक्षियों या अन्य प्रकार के पीड़क जन्तुओं के प्रवेश को रोका जा सके तथा सफाई अच्छी प्रकार और आसानी से की जा सके। कच्ची सामग्री भण्डार गृह क्षेत्र में प्रवेश के लिए नायलॉन या तार की जाली वाले दोहरे द्वार होने चाहिए प्रसंस्करण यूनिट किसी स्थायी भवन में होगा, जहां हवा से उड़कर आने वाली धूल और वर्षा जैसे जलवायु संबंधी सामान्य संकटों से पर्याप्त संरक्षण रहे। विभिन्न अनुभागों का अभिन्यास इस ढंग से किया जाएगा कि कार्य सुचारु रूप से चल सके और प्रसंस्करण पूर्व अनुभाग से संभव संदूषण का रोकना सुकर हो। वह क्षेत्र जहां कच्ची सामग्री प्राप्त और भण्डारित की जाती है उस क्षेत्र से पृथक रखा जाएगा जहां उत्पाद अन्तिम रूप से तैयार किया जाता है या पैक किया जाता है जिससे परिरुपित तैयार उत्पाद को जीवाणु संदूषणों से बचाया जा सके। खाद्य उत्पादों के भण्डारकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्र और कक्ष उन क्षेत्रों से पृथक और सुभिन्न होंगे जिनमें अखाद्य सामग्री रखी जाती है। जिस क्षेत्र में खाद्य सामग्री को उठाया-धरा जाता है वह क्षेत्र, निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से पूर्णतः पृथक होगा। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पैर धोने के लिए न्यूनतम 1.5 मीटर + 1.2 मीटर धुलाई गत रोगाणुनाशक जल सहित तथा और हाथ धोने के लिए रोगाणुरोधक घोल सहित एक धावन-पात्र होना चाहिए।

छत, दीवार और फर्श : छत का डिजाइन और बनावट ऐसी होनी चाहिए कि गंदगी के इकट्ठा होने, वाष्प के संघनन और कवकों को आश्रय मिलना रोका जा सके तथा उसकी आसानी से सफाई की जा सके। छत की ऊंचाई कम से कम 4 मीटर (13 फुट) होनी चाहिए उसमें दरारें और खुले जोड़ नहीं होने चाहिए तथा वह चिकनी जलसह और हल्के रंग की फिनिश वाली होनी चाहिए। डिब्बा बंदशाला (कैनरी) की भीतरी दीवारें चिकनी, जलसह, गड्ढों और दरारों से मुक्त हल्के रंग वाली होंगी, जिन्हें कम से कम 1.3 मीटर ऊंचाई तक आसानी से धोया जा सके। दीवार से दीवार के और दीवार से फर्श के जोड़ों में ऐसी गोलाई होनी चाहिए कि सफाई आसानी से की जा सके। दीवार में कोई निकला हुआ भाग होना चाहिए तथा सभी पाइप और केबिल, जहां कहीं आवश्यक हों, अच्छी प्रकार से ढके होने चाहिए। फर्श मजबूत, जलसह, अविशोषक अवयवों और असंक्षारणीय सामग्री से बनाए जाएंगे जिन्हें आसानी से साफ और विसंक्रमित किया जा सके। वे फिसलन तथा दरारों से मुक्त होंगे और उनकी ढलान समतल और पानी बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

मक्खीसह करना, पीड़क जन्तुओं और पशुओं पर नियंत्रण : प्रसंस्करण क्षेत्र में मक्खीसह करने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था की जाएगी और प्रसंस्करण क्षेत्र में अन्य कीटों, कृन्तकों, पक्षियों, बिल्लियों, कुत्तों आदि के प्रवेश को रोकने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। प्रवेश तथा निकास द्वारों पर नायलॉन या तार की जाली लगी होगी तथा उनमें अधिमानतः दोहरे द्वार होंगे। सभी खिड़कियों पर धूल और मक्खियों को रोकने के लिए नायलॉन या तार की जाली लगी होगी।

प्रकाश और संवातन : सभी कार्य-क्षेत्रों में अच्छा प्रकाश होगा। प्रसंस्करण मेज के ऊपर या उत्पाद की तैयारी के किसी भी प्रक्रम पर बल्ब तथा फिक्सचर सीधे नहीं लटकाए जाएंगे। वे ऐसे सुरक्षित प्रकार के होंगे कि टूटने पर संदूषण से बचा जा सके। अत्यधिक ऊष्मा संघनन और घृणाजनक गंधा धूल, वाष्प या धुएं के संदूषण को रोकने के लिए परिसर पर्याप्त रूप से संवातित होंगे। अत्यधिक ऊष्मा, वाष्प धुआजनक धूम, वाष्प या संदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरणों तथा क्षेत्रों में प्राकृतिक या यांत्रिक संवातन व्यवस्था द्वारा संवातन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संवातन द्वारों में परदा लगा होना चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो उचित वायु फिल्टर लगे होने चाहिए। खिड़कियों पर भी, जो संवातन के प्रयोजनों के लिए खोली जाती है, परदे लगे होने चाहिए। परदे ऐसे होने चाहिए जो सफाई के लिए आसानी से उतारे जा सकें और वे संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से बने होने चाहिएं।

कार्य करने के लिए मेजें और बर्तन : डिब्बा-बंद मछली उत्पादों के प्रसंस्करण के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी मेजें, कार्य सतह, पात्र, ट्रे, टैंक या अन्य बर्तन, चिकने अप्रवेश्य अविशोषक सामग्री के होंगे, जो जंगरोधी होंगे तथा इस प्रकार की बनावट के होंगे कि जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी स्तरों से बचाया जा सके और उन्हें आसानी से अच्छी तरह साफ किया जा सके। खाद्य वस्तुओं के सम्पर्क में आने वाली सभी सतह चिकनी होंगी तथा गढ्ढों, दरारों, मनुष्य के लिए हानिकारक पदार्थों से मुक्त होंगी और ऐसी होंगी कि उनकी बारबार सफाई की जा सके और उन्हें विसंक्रमित किया जा सके। मछली उत्पादों को रखने के लिए प्रयोग किए गए पात्र अधिमानतः प्लास्टिक या जंगरोधी सामग्री के बने होंगे। प्रसंस्करण क्षेत्रों में लकड़ी की टोकरियां, खपची से बनी टोकरियों और इनेमल किए हुए बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेज की सतह स्टेनलेस इस्पात या एल्यूमिनियम की होंगी और चिकनी तथा गढ्ढों और दरारों से मुक्त होंगी। कार्य मेजों का व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कार्य सुगमता से किया जा सके और उनके नीचे तथा आसपास सफाई आसानी से की जा सके। प्रसंस्करण हाल में जंग वाली किसी मद का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

सामग्री धोने वाली टैंकों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि पानी उनसे सभी स्थानों पर जा सके और पानी को लगातार बदला जा सके तथा उनमें जल निस्सारण और आसानी से सफाई करने की व्यवस्था हो। अखाद्य तथा संदूषित सामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तनों की पहचान उन्हें विनिर्दिष्ट रंग से पेंट करके की जाएगी और उनका खाद्य वस्तुओं की उठाई-धराई के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रसंस्करण क्रिया के दौरान कार्य क्षेत्रों से अपशिष्ट सामग्री बारबार हटाने के लिए पर्याप्त पात्रों की व्यवस्था की जाएगी।

उपस्कर और मशीनें : मशीनों और उपस्करों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि जिससे उन्हें रोगाणुनाशी करने के लिए तथा उनकी अच्छी

तरह से साफ करने और विसंक्रमित करने के लिए आसानी से खोला जा सके । स्थिर उपस्कर ऐसी रीति से लगाए जाएंगे कि उन तक आसान से पहुंच हो सके और उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जा सके तथा उन्हें विसंक्रमित किया जा सके । प्रत्येक डिब्बा-बंद शाला में निम्नलिखित उपस्कर और मशीनें पर्याप्त मात्रा में लगाई जाएंगी :-

(क) अच्छी कारगर दशा में रखी गई स्वचालित या अर्धस्वचालित प्रकार की दोहरी सीमन मशीनें या सीमन मशीन ,

(ख) (क) थर्मामीटर (ख) दाबमेज (ग) संघातन वाल्व और

(घ) सुरक्षा वाल्व से सुसज्जित रिटॉर्ट

(ग) संवातक पद्धति सहित निकास कक्ष, या कोई अन्य उपयुक्त वैकल्पिक इंतजाम,

(घ) मानक तौलन मशीनें और बाट

(ङ) टैंक तथा इस्पात से बने सम्बद्ध बर्तन ;

(च) एक लाइन में कम से कम 5 अंक उत्तीर्ण करने की क्षमता वाली कोड उत्कीर्ण मशीनें ;

(छ) धौतलत टैंक ;

(ज) एक ही समय में सभी सामान्य क्रियाओं के लिए वाष्प प्रदाय करने वाले उपयुक्त प्रकार और क्षमता के बायलर तथा उपसाधन : तथा वाष्प ले जाने वाली सभी पाइप उपयुक्ततः ऊष्मा रोधी /सुरक्षित होंगी ।

(झ) सीवन दोष, पी एच, क्षारापन , नियॉन ,उपलब्ध क्लोरीन आदि का नेमी परीक्षण करने के लिए परीक्षण सुविधाएं और ;

(ट) तैयार डिब्बों को रखने वाली केटों को उठाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, यांत्रिक उत्थापक उपस्कर होंगे ।

भण्डारकरण और भण्डारगारण :

डिब्बे :—बंद करने वाली यूनिटों के पास डिब्बा-बंद उत्पादों के पृथक रूप से भण्डारकरण के लिए सुविधाएं होंगी । भण्डागार पर्याप्त क्षमता वाले होंगे और ऐसे होंगे कि भण्डारित उत्पाद को शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाकर रखा जा सके । इसे नमी से पर्याप्त रूप से बचाया जाएगा और बहुत साफ और स्वस्थ्यकर रूप में रखा जाएगा ।

सभी अपमार्जक और निसंक्रामक अलग-अलग भण्डारित किए जाएंगे पैकिंग सामग्री, अग्निशामक उपस्करों को छोड़कर विषाक्त पदार्थ जैसे कृन्तकनाशी, धूमक कीटनाशी या अन्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के भण्डार करने के लिए अलग से सुविधाएं होंगी। ये सभी पदार्थ और उपस्कर केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही प्रयोग में लाए जाएंगे ।

जल और बर्फ :

सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी को कम करने के लिए जल में अवशिष्ट क्लोरीन अंश को परिवर्तित करने के लिए क्लोरीनीकरण पद्धति का प्रयोग करते हुए, पेय जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा । यदि प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल पेय के संरक्षित स्त्रोतों से भिन्न स्रोतों से है तो उसके पेय होने के बारे में प्रमाण-पत्र, अभिकरण या अभिकरण द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से प्रस्तुत किया जाएगा । यदि बायलर या अन्य सहायक सेवाओं के लिए पीने के अयोग्य जल का प्रदाय किया जाता है तो सहायक जल वितरण पद्धति और पेय जल वाहन पद्धति के बीच कोई क्रास संबंधन नहीं होगा । यदि भण्डारण टंकी का पानी प्रयोग में लाया जाता है तो टंकी पर्याप्त क्षमता वाली होगी और उसे बाहरी संदूषणों से संरक्षित किया जाएगा । भण्डारण टंकी एक मास में कम से कम एक बार अच्छी तरह साफ की जाएगी । प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल में क्लोरिन का अंश कम से कम 3 पी० पी० एम० स्तर पर रखा जाएगा । बर्फ पेय जल से बनाई जाएगी और उसका विनिर्माण, उठाई-धराई तथा भंडारण इस प्रकार किया जाएगा कि उसे संदूषणों से बचाया जा सके । यदि बाहर की बनी हुई बर्फ का प्रयोग किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह पेय जल से बनी हुई है और संदूषित नहीं है । बर्फ तोड़ने की मशीन का यदि प्रयोग किया जाता है तो उसे अच्छी साफ हालत में रखा जाएगा । बर्फ को संदूषण और अधिक पिघलने से बचाने के लिए एक विशेष कक्ष या अन्य उपयुक्त भंडार की सुविधा उपलब्ध होगी ।

सफाई संबंधी सुविधाएं और नियंत्रण :

प्रत्येक डिब्बे का, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया जाएगा कि वह टूटा नहीं है और उस में कोई कमी नहीं है । डिब्बे मछली उत्पाद पैक करने के लिए प्रयुक्त किए जाने से पूर्व 10 पी० पी० एम० उपलब्ध क्लोरीन अंश युक्त पेय जल से अच्छी तरह साफ किए जाएंगे ।

कार्य मेज़ों, ट्रे, बर्तनों और उपस्करों की धुलाई तथा विसंक्रामण .

प्रसंस्करण के दौरान प्रयुक्त कार्य मेज़ों, ट्रे, बर्तनों, कटिंग बोर्डों डिब्बों, उपस्करों और कार्य उपकरणों के विसंक्रामण तथा सफाई के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी बर्तन, ट्रे और मेज की सतह, जो पैक न किए हुए माल के सम्पर्क में आती है, प्रारंभ में साफ करने वाले उपयुक्त पदार्थ से साफ की जाएगी और अन्त में उपलब्ध 50 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले जल से साफ की जाएगी । ऐसी सफाई और धुलाई आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाएगी ।

फर्श की धुलाई :

प्रसंस्करण हाल, दिन का कार्य आरम्भ करने से पहले एक बार साफ किया जाएगा और फिर प्रत्येक पारी के अंत में साफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सफाई और धुलाई आवश्यकता अनुसार बारम्बार की जाएगी।

वहित मल तथा अपशिष्ट का निपटान :

तरल और अर्ध तरल अपशिष्ट को हटाने के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त जल निकास सुविधाएं होंगी । वहां फर्श का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां पानी इकट्ठा हो जाए और रुक जाए । नालियां चिकनी और अप्रवेश्य सामग्री से बनी होंगी तथा उनका डिजाइन इस प्रकार का होगा कि उनमें से तरल पदार्थ बह सके और उनमें अधिप्रवाह न हो और न वह नालियों के बाहर जा सके । खुली नालियों के सिवाए अपशिष्ट ले जाने वाली नालियां उचित रूप से संवातित होंगी और यदि अपेक्षित हो तो ठोस अपशिष्ट सामग्री के हटाने के लिए कैचबेसिन तक ले जाई जाएंगी। ऐसा बेसिन प्रसंस्करण क्षेत्र से बाहर स्थित होना चाहिए । और वह जल सह कंकरीट या अन्य उसी प्रकार की सामग्री का बना होना चाहिए। खुली नालियों के जो दीवारों में से होकर जाती हैं मुखों पर कृन्तकों के प्रवेश को रोकने के लिए धातु की जालियां लगाई जाएंगी। वाहित मल अपशिष्ट जल और कूड़े करकट के व्ययन के लिए यथाशीघ्र प्रबंध किया जाएगा और वह ऐसा होगा कि वह पड़ौस के लिए कोई सफाई संबंधी समस्या उत्पन्न न कर दें। शौच-स्थल के मल को इस ढंग से हटाया जाएगा कि उसमें मक्खियां न पहुंच सकें और यूनिटों के जल प्रदाय को प्रदूषित न करे । किसी भी दशा में परिसर में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट या जल एकत्रित नहीं होना चाहिए ।

कारखाना परिसर से कुत्तों और पशुओं का अपवर्जन :

कुत्तों, बिल्लियों तथा अन्य पशुओं को जिनसे रोग पैदा हो सकते है प्रसंस्करण परिसर में न तो प्रवेश करने दिया जाएगा और न उन्हें उसमें या उसके आसपास रहने दिया जाएगा ।

शौच सुविधाएं :

साफ प्रकार की पर्याप्त शौच सुविधाएं दी जाएंगी । शौच स्थल में अपने आप बंद होने वाले द्वार और हाथ धोने का बेसिन और साबुन होगें । धुलाई के प्रयोजनों के लिए पेयजल प्रयुक्त किया जाएगा।

वैयक्तिक स्वास्थ्य और सफाई : संयंत्र का प्रबन्धतंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वह संक्रामक रोग का वाहक है या उससे पीड़ित है उसे एकक के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। ऐसे रोग का पता आसानी से लगाने के लिए प्रबंधक उन कर्मचारियों का जो एकक के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा।

डिब्बा—बंदीशाला में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी कार्य करते समय अत्यधिक वैयक्तिक सफाई रखेंगे तथा मछली उत्पादों को अन्य पदार्थ के संदूषण से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरतेंगे। प्रबन्धतंत्र सभी कर्मचारियों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार साफ एप्रेन तथा सिर का पहनावा देगा। मछली उत्पादों की उठाई-धराई में प्रयुक्त दस्ताने साफ तथा स्वास्थ्यकर ढंग से रखे जाएंगे तथा अपारगम्य सामग्री के बने होंगे किन्तु उस दशा में नहीं जब इनका प्रयोग कार्य की मात्रा को देखते हुए अपूर्ण हो। कर्मचारी प्रत्येक दिन का कार्य आरम्भ करने से पूर्व और शौचालय जाने के पश्चात् प्रत्येक बार और कार्य पुनः आरम्भ करने से पूर्व तथा अन्य अवसरों पर भी, जो आवश्यक हों, अपने हाथ साबुन या किसी अन्य प्रक्षालक वस्तु और गर्म जल से धोएंगे। कर्मचारी प्रसंस्करण से प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् अपने पैर भी पेय जल से धोएंगे। उठाई-धराई तथा प्रसंस्करण के किसी भी क्षेत्र में खाना, धूम्रपान करना, तम्बाकू या कोई अन्य सामग्री चबाना, थूकना या उठाई-धराई तथा प्रसंस्करण के दौरान कोई अन्य आदत जो उत्पाद को संदूषित कर सकता है या जिससे उत्पाद के संदूषित होने की संभावना हो सकती है, कठोरता पूर्वक प्रतिषिद्ध होगी। जहां स्त्री और पुरुष दोनों नियोजित हों वहां पृथक-पृथक शौचागार, कपड़े बदलने का कक्ष और विश्राम कक्षों की सुविधाएं अलग-अलग होंगी। कार्य के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले कपड़े और जूते प्रसंस्करण क्षेत्र में नहीं रखे जाएंगे।

परिवहन सुविधाएं —

जहां तक संभव हो कच्ची सामग्री केवल विद्युतरोधी/प्रशीतित वाहनों में लाई जाएगी। किन्तु, यदि कच्ची सामग्री को साधारण ट्रकों में ही लाया जाता है तो वह बंद वाहन में लाया जाएगा और कच्ची सामग्री को पर्याप्त बर्फ में रखा जाएगा। ऐसे वाहनों को उपयोग के तुरन्त पश्चात् साफ और विसंक्रमित किया जाएगा तथा इस तरह से रखा जाएगा कि वे उत्पाद को संदूषित करने का एक स्रोत न हो जाएं।

आवश्यक पात्रों तथा उपकरणों सहित वाहनों की सफाई नियमित रूप से की जाएगी। वाहनों की होजिंग, रगड़ाई और सफाई ऐसे समुद्री जल या पेय जल से की जाएगी जिसमें उचित अपमार्जक या विसंक्रामक मिलाए गए हों।

अभिलेखों का रखा जाना :

डिब्बा-बन्द मछली तथा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण कर्ता समय-समय पर विहित आवश्यक रजिस्टर और अभिलेख रखना और वे अभिकरण के अधिकारियों को, जब कभी अपेक्षित हों; उपलब्ध कराए जाएंगे। गेज, थर्मोमीटर, भार मापी वोल्ट मीटर भार आदि जैसे मापने वाले और अभिलेखन यंत्रों के अंश-शोधन के लिए तीन मास के कालिक अन्तराल पर विशेष अभिलेख रखे जाएंगे।

3.2 प्रसंस्करण एकक ऊपर खंड 3.1 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त अपने प्रसंस्करण एकक में निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं का भी प्रबंध कर सकता है

(क) प्रसंस्करण एकक में निर्यात के लिए आशयित डिब्बा बंद मछली तथा मछली उत्पादों का और जैवतात्विक मूल्यांकन करने के लिए तथा रसायन कारणों और जीवाणु विज्ञान के लिए परीक्षण करने के लिए प्रसंस्करण पूर्व तथा प्रसंस्करण सक्रियाओं के पर्यवेक्षण के लिए सक्षम और अर्हित कर्मचारी होंगे।

(ख) ऐसे कर्मचारियों के पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए :

(1) किसी विश्वविद्यालय के अधीन किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मत्स्य विज्ञान/प्रसंस्करण में उपाधि/डिप्लोमा, या

(2) मछली तथा मछली उत्पादों के परीक्षण और विश्लेषण के कम से कम दो वर्ष के अनुभव के साथ विज्ञान में उपाधि।

(ग) एकक के पास, निर्यात के लिए आशयित डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक उपस्करों तथा रसायनों सहित अपनी प्रयोगशाला होगी।

(घ) एकक के पास प्रसंस्करण के लिए जो कच्ची सामग्री प्राप्त करने से आरम्भ होकर पैकिंग तक, अपना अनन्य और पृथक क्षेत्र होगा।

3.3 प्रसंस्करण एककों का अनुमोदन.

3.3.1. निर्यात के लिए डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों का प्रसंस्करण करने का इच्छुक प्रसंस्करणकर्ता, अपने ऐसा करने के आशय की लिखित रूप में सूचना अभिकरण के निकटतम कार्यालय को परिषद् द्वारा विहित प्ररूप में देगा। ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर अभिकरण अधिकारी प्रसंस्करण एकक में उपलब्ध प्रसंस्करण सुविधाओं का अधिनिर्णय करने के लिए जाएंगे। यदि यह पाया जाता है कि एकक में वे न्यूनतम सुविधाएं जो इन नियमों में विहित हैं, विद्यमान है तो परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों का पैनल एकक में सुविधाओं की पर्याप्तता के विषय में अधिनिर्णय करेगा और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए वह अपने अनुमोदन या अननुमोदन की अभिकरण से सिफारिश करेगा। पैनल की सिफारिश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर अभिकरण या तो एकक को अनुमोदित करेगा और निर्यात के लिए डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों का प्रसंस्करण करने की अनुज्ञा दे देगा या उसे अनुमोदित नहीं करेगा और प्रसंस्करण कर्ता को, निर्यात के लिए डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण को अनुज्ञा नहीं देगा। अनुमोदन करने के पश्चात् अभिकरण अधिकारी ऐसे एकक में नियमित अन्तरालों पर यह सुनिश्चित करने के लिए जाएगा कि उसमें पैनल द्वारा अनुमोदित प्रबंध किए गए हैं। अभिकरण अधिकारी एकक में जीवाणु परीक्षण और प्रयोगशाला में जैवतात्विक परीक्षणों के लिए उन एककों से नमूने लेंगे जिनमें ऊपर स्तम्भ 3.2 के अन्तर्गत दिए गए प्रबंध हैं।

3.3.2. अनुमोदन.

यदि एकक को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो पैनल अपने द्वारा अभिनिश्चित कमियों को बताते हुए, उसकी सूचना प्रसंस्करण कर्ता को लिखित रूप में देगा। पैनल द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के पश्चात् प्रसंस्करणकर्ता उन कमियों को दूर करने के बारे में ब्यौरेवार रिपोर्ट सहित एक नया आवेदन अभिकरण को प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन की प्राप्ति पर अभिकरण ऊपर 3.3.1 में बताए गए कदम उठाएगा।

3.3.3. प्रसंस्करण एकक को किसी समय दिया गया अनुमोदन, अभिकरण के अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त 3.2 के अधीन एककों की दशा में की गयी कालिक जांचों के दौरान लिए गए नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट और इन कालिक जांचों के दौरान रिपोर्टों के आधार पर, प्रसंस्करण कर्ता द्वारा सूचना प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के पश्चात् सम्बंधित प्रसंस्करण-कर्ता को निम्नलिखित किसी भी कमी के लिए सूचना देते हुए वापस ले लिया जाएगा परन्तु यह तब जब कि प्रसंस्करण कर्ता ने इन 7 दिन के भीतर कोई उपचारी कदम न उठाए हों।

यदि प्रसंस्करण उपस्कर, मशीनरी और भंडारकरण सुविधाएं अच्छी कार्यकारी दशाओं में नहीं है,

यदि एकक की स्वच्छता और सफाई संबंधी दशाएं संतोषजनक नहीं है,

यदि प्रति जांच के लिए, लिए गए नमूने अधिकथित मानकों के अनुसार नहीं हैं;

यदि प्रसंस्करणकर्ता ने अधिसूचना के उपबंधों या समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया है या जानबूझकर उल्लंघन करने का प्रयत्न किया है। प्रसंस्करणकर्ता को ऊपर 3.2 की अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन दिया गया अनुमोदन किसी भी समय निम्नलिखित कारणों से वापस ले लिया जाएगा;

यदि ऊपर उल्लिखित त्रुटियों में से कोई त्रुटि पाई जाती है,

यदि प्रसंस्करणकर्ता द्वारा निर्यात की गई डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पाद की क्वालिटी के विषय में विदेशी क्रेता से शिकायत प्राप्त होती है और जांच पड़ताल करने पर वह सही पायी जाती है,

यदि आयातकर्ता देश द्वारा डिब्बाबंद मछली तथा मछली उत्पाद के 2 परेषण निरंतर अस्वीकृत कर दिए जाते है। अनुमोदन को ऐसे वापस लिए जाने की सूचना प्रसंस्करणकर्ता को लिखित रूप में दी जाएगी।

3.4 पुनः अनुमोदन

जिस एकक का अनुमोदन वापिस ले लिया गया है वह कमियों को दूर करने के पश्चात् नये अनुमोदन के लिए अभिकरण को नये सिरे से आवेदन कर सकेगा। यदि किसी भी समय उपर्युक्त 3.3.3 में दिए गए कारणों से उत्पाद की अनुरूपता को विनिर्देशों के अनुरूप बनाए रखने में कठिनाई होती है या निर्यात के लिए उत्पादन निलंबित करने के अभिकरण द्वारा निर्देश दिए जाते है तो प्रसंस्करणकर्ता अभिकरण को सूचित करते हुए निर्यात के लिए उत्पादन निलंबित कर देगा। निर्यात के लिए प्रसंस्करण तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब उसके लिए अभिकरण लिखित रूप में अनुमोदन दे देता है।

3.5. प्रसंस्करण

प्रसंस्करणकर्ता सक्षम तकनीकी कार्मिकों के पर्यवेक्षण में केवल अनुमोदित एककों ही प्रसंस्करण करेगा। प्रसंस्करण के लिए केवल ऐसी कच्ची सामग्री स्वीकृत की जाएगी जो ताजी, स्वच्छ, स्वास्थ्य प्रद, विशिष्ट आकृति, सुगंध, रंग तथा बनावट वाली होगी।

4 निरीक्षण :

निर्यात के लिए आशयित डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों का निरीक्षण इससे उपाबद्ध अनुसूची–II के अनुसार जहां कहीं आवश्यक हों, परेषण का परीक्षण और जांच करने के लिए उसमें से नमूने लेकर इस दृष्टि से किया जाएगा कि क्या परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

5 निरीक्षण का आधार

निर्यात के लिए आशयित डिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि क्या वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, या तो,

(क) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 2 में विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण स्त्रों का प्रयोग किया गया है,

या

(ख) नियम 3 के उप-नियम 3.2 को छोड़कर नियम 3 और 4 के अनुसार किए गए निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा,

या

(ग) दोनों के द्वारा किया जाएगा।

6. निरीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया :

6.1 डिब्बा-बन्द मछली तथा मछली उत्पादों को निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता निर्यात करने की सूचना विहित प्ररूप में, (परिशिष्ट 1 देखिए) निर्यात किए जाने वाले परेषण की विशिष्टियां देते हुए अभिकरण के निकटतम कार्यालय को देगा।

6.2 निरीक्षण के लिए क्रमशः नियम 5(क) तथा 5(ख) के अधीन दिए गए परेषणों की दशा में ऐसी प्रत्येक सूचना अभिकरण के कार्यालय में निर्यात-कर्ता के परिसर से भेजे जाने की प्रत्याशित तारीख से कम से कम 4 दिन और 15 दिन पूर्व पहुंच जाएगी।

6.3 नियम 6.1 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण, नियम 5 के अधीन उपबंधित निरीक्षण और इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के यदि कोई हो, आधार पर अपना यह समाधान हो जाने पर कि परेषण का उसे लागू मानक विनिर्देश के अनुसार प्रसंस्करण किया गया है और उसे पैक किया गया है यह घोषणा करते हुए, यथास्थिति, चार दिन या पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगा कि डिब्बा बंद मछली तथा मछली उत्पादों का परेषण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, वहां वह, यथास्थिति, 4 दिन या 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की संसूचना, उसके कारणों सहित, निर्यात-कर्ता को देगा।

6.4. उच्च निरीक्षण :

प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को भंडार में, परिवहन में या पत्तन में के परेषण की क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा यदि यह पाया जाता है कि परेषण इनमें से किसी भी प्रक्रम पर मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो मूलतः दिया गया प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

6.5 विधिमान्यता :

जारी किया गया प्रमाणपत्र लॉट के अनुमोदन की तारीख से 90 दिन के लिए विधि मान्य होगा। यदि भिन्न-भिन्न दिनों को अनुमोदित एक लॉट से अधिक लॉट एक आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किए जाते है तो प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अनुमोदन की सबसे पहली तारीख से संगठित की जाएगी।

यदि परेषण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की अवधि के भीतर जहाज पर लादा नहीं जाता है तो निर्यात कर्ता का परेषण पुनः विधिमान्यता के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित दरों पर निरीक्षण फीस प्रभारित की जाएगी और परेषण का इन्द्रियग्राही निरीक्षण के लिए परिषद् द्वारा इस निमित्त विहित नमूना माप मान के अनुसार नमूने लेकर परीक्षण किया जाएगा। ऐसे मामलों में विधि मान्यता निरीक्षण की समाप्ति की तारीख से 30 दिन की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। 6.5 में उल्लिखित विधि मान्यता की अवधि के भीतर पोत पर न लादे जाने वाले परेषण के लिए यदि आवश्यक समझा जाए, तो 15 दिन से अनधिक की अवधि के लिए विधि मान्यता की अवधि बढ़ाया जाना अभिकरण द्वारा मंजूर किया जा सकेगा।

7. निरीक्षण का स्थान :

इन नियमों के प्रयोजन के लिए डिब्बा बंद मछली तथा मछली उत्पादों का निरीक्षण प्रसंस्करणकर्ता के परिसर पर और/या निर्यात निरीक्षण अभिकरण की प्रयोगशाला में किया जाएगा। प्रसंस्करणकर्ता अभिकरण को, सभी आवश्यक सुविधाएं देगा ताकि वह ऐसा निरीक्षण कर सके।

8. निरीक्षण फीस

(i) जब निरीक्षण नियम 5(क) तथा (ग) के आधार पर किया जाता है तो प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए आठ पैसे; और (ii) यदि निरीक्षण नियम 5(ख) के आधार पर किया जाता है तो प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए 15 पैसे की दर से फीस निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।

9. अपील.

9.1 नियम 6 के अधीन निर्यात-योग्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने से अभिकरण के इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को जिसमें कम से कम तीन किन्तु अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकता है।

9.2. विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य अशासकीय सदस्य होंगे।

9.3 पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

9.4. अपील उसके प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

(क) लवण जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित माध्यम में या शुष्क पैक डिब्बा बंद झींगा मछली (शिम्प) के लिए विनिर्देश :

1. कच्ची सामग्री.

1.1. लवण जल में डिब्बा बंद झींगा मछली/शिम्प के तैयार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री ताजी, निरोग, स्वास्थ्यप्रद, उचित रूप से साफ की गई और विकृति मुक्त होगी।

1.2. भा०मा० 594 1962 के अनुरूप केवल शुद्ध नमक का प्रयोग किया जाएगा।

2. डिब्बे :

2.1. सामग्री अन्दर से उपयुक्त और एकसमान लेकर किए गए डिब्बों में पैक की जाएगी। डिब्बों पर क्रेता तथा प्रसंस्करणकर्ता के बीच हुए करार के अधीन रहते हुए बाहर भी लेकर किया जा सकेगा। उसमें प्रयुक्त किया गया लेकर ऐसा होगा कि उसके डिब्बे में रखी अन्तर्वस्तु में कोई बाह्य अप्रिय स्वाद और गंध नहीं आए और वह प्रसंस्करण तथा भंडारकरण के दौरान उतरेगा नहीं। लेकर किसी भी सीमा तक लवणजल में विलयशील नहीं होगा। डिब्बे का बाहरी हिस्सा अड़े गड्ढों, जंग, छिद्रों और जोड़ों की विकृतियों से मुक्त होगा।

3. लवण जल :

3.1. यदि लवण जल का प्रयोग किया जाता है तो वह साफ होगा और विवर्णित नहीं होगा।

4. पैकिंग और लेबल लगाना.

4.1. एक डिब्बे में एक ही प्रकार की सामग्री पैक की जाएगी।

4.2. लेबल, यदि प्रयोग किए जाते हैं तो वे उसी देश के जहां सामग्री निर्यात की जाती है नियमों और विनियमों के अनुसार होंगे।

5. जलोत्सारित भार और आकार श्रेणी :

5.1. अन्तर्वस्तु का कुल जलोत्सारित भार घोषित भार से कम नहीं होगा।

5.2. आकार काउंट (प्रति एकक भार के टुकड़ों की संख्या) डिब्बे पर घोषित आकार श्रेणी के अनुसार होगा।

6. इन्द्रियग्राही क्वालिटी :

6.2. डिब्बे को खोलने पर अन्तर्वस्तु अच्छे रूप में होगी और कोई विशेष विघटन प्रदर्शित नहीं करेगी। टुकड़े जिनके भाग अलग हो जाते हैं उन्हें विघटित झींगा समझा जाएगा।

6.2 छूने पर झींगा मछली की सतह चिकनी नहीं प्रतीत होगी। मांस नरम किन्तु सुदृढ़ होगा तथा उंगलियों के बीच दबाए जाने पर टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाएगा।

6.3. झींगा मछली के टुकड़े परस्पर बंधे हुए प्रतीत नहीं होंगे और टुकड़ों को आसानी से अलग-अलग करना संभव होगा। टुकड़े एक ही आकार के होंगे और साफ होंगे तथा उसमें मांस के ढीले लटकते हुए टुकड़े नहीं होंगे।

6.4. सामग्री में ताजी पकाई हुई झींगा मछली के मांस का स्वाद और सुगंध होगी और वह सीखे/कड़वे या अन्य किसी आपत्तिजनक सुगंध से मुक्त होगी।

6.5 सामग्री, प्रसंस्करण पूर्व विकृति दर्शाने वाली हरापन लिए या पीले पुट वाले विरंजित वर्ण से मुक्त होगी। सामग्री काले रंग के विवर्ण से भी मुक्त होगी।

6.6. सामग्री रेत, धूल, कीटाणु, बाल, या अन्य किसी बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी। यह शिरा, शेल कणों और उपांगों के टुकड़ों से मुक्त होगी।

6.7. सामग्री किसी विषैले और हानिकारक तत्वों से मुक्त होगी।

6.8. डिब्बों को खोलने पर कोई जीवाणु दूषण की गंध नहीं आएगी, अन्तर्वस्तु में द्रवणता और फूलापन प्रकट नहीं होगा।

6.9. उत्पाद निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा।

क्रम सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण की पद्धति भा०मा० 2236 1968** में परिशिष्ट के संदर्भ में	भा०मा० 2168 1962* में परिशिष्ट के संदर्भ में
1	2	3	4	5
(i)	डिब्बे का निर्यात, न्यूनतम, मि०मी० में।	100	क	--
(ii)	डिब्बे का मुख मि०मी० में।	5.0 से 7.5	--	ख
(iii)	डिब्बे की अन्तर्वस्तु का जलोत्सारित भार, जैसे डिब्बे में पानी की क्षमता और भार की प्रतिशतता न्यूनतम।	64	ख	--
(iv)	लवण जल में सोडियम क्लोराइड, प्रतिशत (डब्ल्यू/वी) अधिकतम।	3.5	ग	--

1	2	3	4	5
(v)	लवण जल में साइट्रिक अम्ल जैसी अम्लता (निर्जल) प्रतिशत (डब्ल्यू/वी)	0.06 से 0.20	ख	--
(vi)	आर्सेनिक, प्रति दस लाख में टुकड़े अधिकतम।	1	--	ग
(vii)	सीसा, प्रति दस लाख मे टुकड़े, अधिकतम।	5	--	घ
(viii)	तांबा, प्रति दस लाख में टुकड़े, अधिकतम।	10	--	ङ
(ix)	जस्ता प्रति दस लाख में टुकड़े अधिकतम।	50	--	च
(x)	टिन, प्रति दस लाख मे टुकड़े, अधिकतम।	250	--	छ

* डिब्बे मे तेल में बन्द पामफिट के लिए विनिर्देश।

** डिब्बे में लवण जल में बन्द झींगा मछली/श्रिम्पों के लिए विनिर्देश (प्रथमा पुनरीक्षण)।

7 जीवाणु संबंधी अपेक्षाएं :

7.1 नमूना डिब्बो का प्रारम्भिक उष्मायन 37° सेंटीग्रेड पर सात दिन के लिए किया जाएगा। इस उष्मायन के पश्चात् तरल भाग की आवश्यक मात्रा नलिका द्वारा निकाल दिया जाता है और थियोग्लाइ-कोल्लेट सिस्टीन ब्रोथ में सरोपण और 48 घंटों के लिए 37° सेंटीग्रेड पर उष्मायित किया जाएगा। उष्मायित ब्रोथ में जीवाणु वृद्धि नहीं होगी।

8. संकेतन

8.1 डिब्बों पर आकार श्रेणी, जलोत्सारित भार, विनिर्माता का नाम या उसका कारखाना कोड, विनिर्माण का वर्ष, मास, बैच समुदभूत किए जाएंगे। संक्षिप्त रूप मे संकेन समुदभूत करने के लिए एक दृष्टान्त नीचे दिया गया है .

टी 5 ×

1 बी 05

टी 5 से जलोत्सारित भार 5 ग्रौस में पैक किया गया, टाइनी अभिप्रेत है। '×' से विनिर्माता का संक्षिप्त रूप में नाम या कारखाना कोड अभिप्रेत है, '1' से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है, और इस दृष्टांत मे, यह 1981 वर्ष सूचित करता है 'बी' से विनिर्माण का मास अभिप्रेत है (यहां यह फरवरी मास को सूचित करता है) और 05 से मास के दौरान विनिर्माण की तारीख अभिप्रेत है। यदि डिब्बाबंदी के लिए पी० यू० डी० सामग्री प्रयोग की जाती है तो आकार श्रेणी चिन्हाँकित करने से पहले 'यू' भार समुदभूत किया जाएगा। आकार श्रेणी और जलोत्सारित भार का द्योतन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पद्धति का अनु-सरण किया जाएगा .

(क) आकार श्रेणी*

नाम	काउंट/100 ग्राम	संक्षेपाक्षर
कोलासल/सुप्रीम जम्बो	8 से कम	सी/एस जे
जम्बो	9 से 13	जे
बड़ा	14 से 22	एल
मध्यम	23 से 36	एम
छोटा	37 से 63	एस
टाइनी	64 से 102	टी
काकटेल/मिनी/सलाद	103 से ऊपर	सी टी/एम आई एस डी
टूटा हुआ/साबुत और टूटा हुआ	कोई सीमा नहीं	बी/डब्ल्यू बी

*जिस डिब्बे में कुल टुकड़ों की संख्या पर ध्यान दिये बिना, भार के आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक टूटे हुए टुकड़े होंगे उसे 'टूटा हुआ' माना जाएगा। किसी भी टुकड़े मे 4 से कम खंड होने पर उसे टूटा हुआ माना जाएगा।

(ख) भार

4.5 ग्रौस वाले पैक को छोड़कर जो मानक पैक समझा जाता है, उस डिब्बों पर वास्तविक जलोत्सारित भार ग्रौस में समुदभुत किया जाएगा।

(ग) विनिर्माण का मास निम्न रूप मे अभिहित किया जाएगा, अर्थात्—

मास	संक्षेपाक्षर	मास	संक्षेपाक्षर
जनवरी	क	जुलाई	छ
फरवरी	ख	अगस्त	ज
मार्च	ग	सितम्बर	झ
अप्रैल	घ	अक्तूबर	ट
मई	ङ	नवम्बर	ठ
जून	च	दिसम्बर	ड

(ख) लवण जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित माध्यम में डिब्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए विनिर्देश।

1. कच्ची सामग्री

1.1 डिब्बा बन्दी के लिए प्रयुक्त मांस स्वस्थ, ताजे पकड़े हुए और साइलासेरेटा, पोर्टोनस पेजाजिकस, नैप्ट्यूनस, पालाजिकस और नैपट्यूनस सैंगिनौलिटस जैसी जातियों के केकड़ों से प्राप्त किया जाएगा।

2. डिब्बे

2.1 सामग्री आन्तरिक रूप से और एक समान लेकर किए गए डिब्बो में पैक की जाएगी। क्रेता और प्रसंस्करणकर्ता के बीच हुए करार के अधीन रहते हुए, डिब्बों को बाहर से भी लेकर किया जा सकेगा। प्रयुक्त किया गया लेकर इस प्रकार का होगा कि वह डिब्बे की अन्तर्वस्तु में किसी भी प्रकार का बाह्य अस्वाद उत्पन्न न करे और प्रसंस्करण तथा भण्डारकरण के दौरान उतरे नहीं। लेकिन किसी भी सीमा तक लवण जल में विलयशील नहीं होगा। डिब्बों का आन्तरिक भाग बड़-बड़े गड्ढों, जंग छिद्रों और जोड़ो की विकृतियों से मुक्त होगा।

2.2 डिब्बों को वायु रुद्ध बन्द करने के पश्चात् उसमें कोई रिसाव पैनलिंग या उभार दिखाई नहीं देंगे। खोलने पर डिब्बों के भीतर कोई दृश्यमान काला, विवर्ण जंग या गड्ढे नहीं होंगे और आन्तरिक लेकर अच्छी दशा में होगा।

3. लवण-जल

3.1 भारतीय मानक 594–1962 के अनुरूप निर्वात द्वारा सुखाया गया नमक या साधारण नमक, लवण जल तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। लवण-जल का सोडियम क्लोराइड अंश यदि प्रयुक्त किया जाता है तो वह अधिकतम 0.2 डब्ल्यू/वी से अधिक नहीं होगा।

3.2 साइट्रिक अम्ल के जैसे लवण जल (निर्जल) की अम्लीयता का कुल अधिकतम 0.20 प्रतिशत डब्ल्यू/वी होगी।

4 पैक करना और लेबल लगाना

4.1 केकड़े का मांस पोर्चमेंट कागज में पैक किया जाएगा।

4.2 केकड़े के धड़ और पंजे का मांस क्रेता और विक्रेता के बीच तय पाई गई संविदा की शर्तों के अनुसार पैक किया जाएगा। संविदात्मक

विनिर्देशों के न होने पर, पंजे का माँस स्पष्टतया अलग तहों में सबसे ऊपर और सबसे नीचे पैक किया जाएगा।

4.3 एक डिब्बे में एक ही प्रजाति के केकड़ों का मास पैक किया जाएगा। अप्रवाही जल और समुद्र से पकड़े गए केकड़ों के मांस को किसी एक डिब्बे में मिलाया या पैक नहीं किया जाएगा।

4.4 डिब्बे पर "भारत का उत्पाद" शब्द समुदभुत किया जाएगा।

5. जलोत्सारित

5.1 डिब्बे में पानी की कुल क्षमता आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

5.2 माँस का जलोत्सारित भार घोषित भार से कम नहीं होगा।

6. तैयार उत्पादों के लिए अपेक्षाएं

6.1 डिब्बों को खोलने पर उनकी अन्तर्वस्तु में केकड़े के मास का विशिष्ट रंग और गंध होगी तथा उनसे कोई अन्य बाहय गंध नहीं आएगी।

6.2 सामग्री किसी भी झुलसी हुई कड़वी या आपत्तिजनक गंध से मुक्त होगी।

6.3 सामग्री किसी धब्बे, धूल, कीट, बाल या किसी अन्य बाहय पदार्थ से मुक्त होगी। वह शिरा, झिल्ली, शेल उपागों के अंशों और टुकड़ों से मुक्त होगी।

6.4 माँस का रंग नीलापन लिए हुए नहीं होगा।

6.5 सामग्री विषैले और हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी।

6.6 लवण-जल में डिब्बा बंद केकड़े का माँस निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा:

सारणी—I लवणजल में डिब्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए अपेक्षाएं :

क्रम सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण की पद्धति *भा० मा० 7143—1973 के परिशिष्ट के सदर्भ में	परीक्षण की पद्धति **भा०मा० 2236—1968 के परिशिष्ट के संदर्भ मे
	(2)	(3)	(4)	(5)
	डिब्बे में निर्वात मि० मीटरो में, न्यूनतम ।	150	—	क
	लवण जल में सोडियम क्लोराइड भार के आधार पर तिशत अधिकतम ।	2%	—	ग
	पाइट्रिक अम्ल (निर्जल) जैसे वण जल में अम्लीयता शत (डब्ल्यू/वी) अधिक- ।	0.2%	—	घ
	'अविलयशील अम्ल, भार धार पर प्रतिशत, अधिक-	2	क	—

-जल में डिब्बा-बन्द केकड़े के माँस के लिए विनिर्देश।

जल में डिब्बा बद झींगे/श्रिम्प के लिए विनिर्देश (प्रथम आवृत्ति)

सारणी—II लवण-जल में डिब्बा-बन्द केकड़े के माँस में धातुक अशुद्धताओं की सीमाएं।

क्रम स०	विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण की पद्धति भा० मा० 2168—1971* के परिशिष्ट के सदर्भ में
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	आर्सेनिक, पी०पी०एम० अधिकतम	1	ख
(ii)	सीसा, पी०पी०एम०, अधिकतम	5	ग
(iii)	तांबा, पी०पी०एम०, अधिकतम	10	घ
(iv)	जस्ता, पी०पी०एम० अधिकतम	10	ङ
(v)	टिन, पी०पी०एम० अधिकतम	250	च

*तेल में डिब्बा-बन्द पार्मफिट के लिए विनिर्देश (प्रथम पुनरीक्षण)।

7 जीवाणु-विषयक अपेक्षाएं:

नमूना लिए गए डिब्बो का प्रारम्भिक उष्मायन 37° सें०ग्रेड पर सात दिन के लिए किया जाएगा। इस प्रारम्भिक उष्मायन के पश्चात्, डिब्बों में भरा लवण-जल थियोग्लाइकोलेट सिस्टीन ब्रॉथ में निवेशन पर और 48 घंटों के लिए 37° सें०ग्रे० के उष्मायन पर कोई जीवाणु उत्पत्ति नहीं होगी।

8 संकेतन :

8.1 डिब्बो पर जलोत्सारित भार का चिन्ह, विनिर्माता का नाम उसके कारखाने का चिन्ह और निर्माण का वर्ष मास तथा तारीख समुदभूत किए जाएँगे। संकेत चिन्ह का समुदभूत चिन्ह को समुदभूत करने के लिए एक संक्षिप्त दृष्टांत नीचे दिया गया है :

सी०बी० 5 X

1 बी 0 5

उपर्युक्त दृष्टांत में, "सी०बी०" से लवण-जल में डिब्बा-बन्द केकड़े का माँस अभिप्रेत है, '5' से जलोत्सारित भार अभिप्रेत है और इस दृष्टांत में यह 5 औंस जलोत्सारित भार सूचित करता है, 'X' से संक्षिप्त रूप में विनिर्माता का नाम या उसके कारखाने का संकेत अभिप्रेत है। '1' से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है और इस दृष्टांत में यह वर्ष 1981 सूचित करता है, 'बी' से विनिर्माण का मास अभिप्रेत है और इस दृष्टांत में वह फरवरी मास सूचित करता है, "05" से मास के दौरान विनिर्माण की तारीख अभिप्रेत है। विनिर्माण के मास निम्न रूप में 'X' अभिलिखित किए जाएँगे, अर्थात् :

मास	संक्षेपाक्षर
जनवरी	क
फरवरी	ख
मार्च	ग
अप्रैल	घ
मई	ङ
जून	च
जुलाई	छ
अगस्त	ज
सितम्बर	झ
अक्तूबर	ट
नवम्बर	ठ
दिसम्बर	ड

8.2 जलोत्सारित भार :

4 5 औंस वाले पैक को छोड़कर जो मानक पैक समझा जाता है डिब्बों पर वास्तविक जलोत्सारित भार औंस में समुदभूत किया जाए,

विनिर्देशों के न होने पर, पंजे का मॉस स्पष्टतया अलग नहीं में सबसे ऊपर और सबसे नीचे पैक किया जाएगा।

4.3 एक डिब्बे में एक ही प्रजाति के केकड़ों का मांस पैक किया जाएगा। अप्रवाही जल और समुद्र से पकड़े गए केकड़ों के मास को किसी एक डिब्बे में मिलाया या पैक नहीं किया जाएगा।

4.4 डिब्बे पर "भारत का उत्पाद" शब्द समुदभुत किया जाएगा।

5. जलोत्सारित

5 1 डिब्बे में पानी की कुल क्षमता आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

5.2 मॉस का जलोत्सारित भार घोषित भार से कम नहीं होगा।

6. तैयार उत्पादों के लिए अपेक्षाएं

6 1 डिब्बों को खोलने पर उनकी अन्तर्वस्तु में केकड़े के मास का विशिष्ट रंग और गंध होगी तथा उनसे कोई अन्य बाह्य गंध नहीं आएगी।

6 2 सामग्री किसी भी झुलसी हुई कडवी या आपत्तिजनक गंध से मुक्त होगी।

6.3 सामग्री किसी धब्बे, धूल, कीट, बाल या किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी। वह शिरा, झिल्ली, शेल उपागों के अंशों और टुकड़ों से मुक्त होगी।

6.4 मॉस का रंग नीलापन लिए हुए नहीं होगा।

6.5 सामग्री विषैले और हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी।

6.6 लवण-जल में डिब्बा बंद केकड़े का मॉस निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा:

सारणी—I लवणजल में डिब्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए अपेक्षाएं :

क्रम सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण की पद्धति *भा० मा० 7143—1973 के परिशिष्ट के संदर्भ में	परीक्षण की पद्धति **भा०मा० 2236—1968 के परिशिष्ट के सदर्भ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)	डिब्बे में निर्वात मि० मीटरों में, न्यूनतम ।	150	—	क
(ii)	लवण जल में सोडियम क्लोराइड भार के आधार पर प्रतिशत अधिकतम।	2%	—	ग
(iii)	साइट्रिक अम्ल (निर्जल) जैसे लवण जल में अम्लीयता प्रतिशत (इक्ल्यू/बी) अधिकतम।	0 2%	—	घ
(iv)	राख अविलयशील अम्ल, भार के आधार पर प्रतिशत, अधिकतम।	2	क	—

* लवण-जल में डिब्बा-बन्द केकड़े के मॉस के लिए विनिर्देश।

** लवण-जल में डिब्बा बंद झींगें/श्रिम्प के लिए विनिर्देश (प्रथम आवृत्ति)

सारणी—II लवण-जल में डिब्बा-बन्द केकड़े के मॉस में धातुक अशुद्धताओं की सीमाएं।

क्रम सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण की पद्धति भा० मा० 2168—1971* के परिशिष्ट के सदर्भ में
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	आर्सेनिक, पी०पी०एम० अधिकतम	1	ख
(ii)	सीसा, पी०पी०एम०, अधिकतम	5	ग
(iii)	तांबा, पी०पी०एम०, अधिकतम	10	घ
(iv)	जस्ता, पी०पी०एम० अधिकतम	10	ङ
(v)	टिन, पी०पी०एम० अधिकतम	250	च

*तेल में डिब्बा-बन्द पामफ्रिट के लिए विनिर्देश (प्रथम पुनरीक्षण)।

7 जीवाणु-विषयक अपेक्षाएं :

नमूना लिए गए डिब्बों का प्रारम्भिक उष्मायन 37° से०ग्रेड पर सात दिन के लिए किया जाएगा। इस प्रारम्भिक उष्मायन के पश्चात्, डिब्बों में भरा लवण-जल थियोग्लाइकोल्लेट सिस्टीन ब्रोथ में निवेशन पर और 48 घंटों के लिए 37° सें०गे० के उष्मायन पर कोई जीवाणु उत्पत्ति नहीं होगी।

8 संकेतन.

8 1 डिब्बा पर जलोत्सारित भार का चिन्ह, विनिर्माता का नाम उसके कारखाने का चिन्ह और निर्माण का वर्ष, मास तथा तारीख समुदभूत किए जाएंगे। संकेत चिन्ह को समुदभूत चिन्ह को समुदभूत करने के लिए एक संक्षिप्त दृष्टांत नीचे दिया गया है :

सी०बी० 5 X

1 बी 0 5

उपर्युक्त दृष्टांत में, "सी०बी०" से लवण-जल में डिब्बा-बन्द केकड़े का मॉस अभिप्रेत है, '5' से जलोत्सारित भार अभिप्रेत है और इस दृष्टांत में यह 5 औंस जलोत्सारित भार सूचित करता है, 'X' से संक्षिप्त रूप में विनिर्माता का नाम या उसके कारखाने का संकेत अभिप्रेत है। '1' से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है और इस दृष्टांत में यह वर्ष 1981 सूचित करता है, 'बी' से विनिर्माण का मास अभिप्रेत है और इस दृष्टांत में वह फरवरी मास सूचित करता है, "05" से मास के दौरान विनिर्माण की तारीख अभिप्रेत है। विनिर्माण के मास निम्न रूप में 'X' अभिलिखित किए जाएंगे, अर्थात्:

मास	संक्षेपाक्षर
जनवरी	व
फरवरी	ख
मार्च	ग
अप्रैल	घ
मई	ङ
जून	च
जुलाई	छ
अगस्त	ज
सितम्बर	झ
अक्तूबर	ट
नवम्बर	ठ
दिसम्बर	ड

8 2 जलोत्सारित भार

4 5 औंस वाले पैक को छोड़कर जो मानक पैक समझा जाता है डिब्बों पर वास्तविक जलोत्सारित भार औंस में समुदभूत किया जाए।

अनुसूची—1

नियंत्रण के स्तर

(नियम 3 देखिए)

क्रम सं०	परीक्षण या निरीक्षण विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की मात्रा/सं०	लॉट आकार/आवृत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	सामग्री				
1.1	जल	3.5 पी०पी०एम० उपलब्ध क्लोरीन सहित पेय क्वालिटी, उसमें 100 मि०ली० में 10 से अनधिक और कालीफार्मोज मिलि लीटर में 100 से अनधिक टी० पी० सी० नहीं होंगे	250 मि०ली०	प्रतिदिन	
1.2	कच्ची सामग्री :				
	तापमान	10 सें०ग्रे० अधिकतम	1 किलोग्राम	प्रत्येक 250 ग्राम या उसके भाग के लिए यथोक्त	
	विवर्णन, गंध कालेधब्बे, बाह्य पदार्थ शिथिल शेल एनडोला आदि जीवाणु परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	1 किलोग्राम		
	जीवाणु विषयक जांच	इ० कोलाई के लिए जांच सुविधाएं जांच अधिकतम 20 प्रति ग्राम	50 किलोग्राम	एक दिन की कुल प्राप्ति	खंड 3.2 के अनुसार नियंत्रण रखने वाली यूनिटों के लिए
1.3	बर्फ	रंग रहित होगा, प्रति 100 मि० लिटर में 10 से अनधिक कालीफार्मोज और प्रति मि० लीटर में 100 से अनधिक टी०पी०सी० नहीं होंगे।	एक नमूना 25 ग्राम से कम नहीं होगा	एक दिन की कुल प्राप्ति	
1.4	डिब्बे, अंग तथा विकृति	मानक विनिर्देशों के अनुसार	100%	प्रत्येक बैच	
1.5	गत्ते के बक्स	निर्यातकर्ता की अपेक्षानुसार	1%	प्रत्येक बैच	
1.6	रसायन	शुद्ध रसायन प्रयोग किए जाने चाहिए		माल प्रेषण	
2	प्रसंस्करण				
2.1	धुलाई	3 बार न्यूनतम	100%	प्रत्येक लॉट	
2.2	विवर्ण करना। माध्यम की सान्द्रता को डिप करने की अवधि माध्यम का तापमान	प्रसंस्करणकर्ता की अपेक्षानुसार	—	प्रत्येक बैच	
2.3	श्रेणीकरण/काऊन्ट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	5%	प्रत्येक संकलन	
2.4	भराव भार	मानक विनिर्देशों के अनुसार	—	यथोक्त	
2.5	भराव माध्यम				
	सान्द्रता	—यथोक्त—		प्रत्येक मिश्रण	
	आयतन	डिब्बे की क्षमता के 35% से कम नहीं	5%	प्रत्येक बैच	
2.6	रेचन समय तापमान	प्रसंस्करणकर्ता की अपेक्षानुसार	यथोक्त	यथोक्त	
2.7	सीवन				
	रिसाव	यथोक्त	5%	यथोक्त	
	सीवन माप	यथोक्त	2 नग	यथोक्त	

1	2	3	4	5	6
2.8	विसंक्रमण तापमान दाब अवधि	प्रसंस्करण कर्ता की अपेक्षानुसार	—	प्रत्येक बैच	
2.9	पकाने के लिए जल : क्लोरीन अन्तर्वस्तु	यथोक्त	2.5 पी०पी०एम०	प्रत्येक घंटा	
3.	उत्पाद :				
3.1	जलोत्सारित भार	घोषितभार के अनुसार			
3.2	एर्स्टानी, टागें, नसें इत्यादि	एक डिब्बे में 5 नग, अधिकतम			
3.3	बाह्य पदार्थ	शून्य			
3.4	टूटे टुकड़ों की प्रतिशतता	10% अधिकतम			
3.5	श्रेणी	घोषित श्रेणी	अनुसूची II के अनुसार	संकेत II की प्रत्येक श्रेणी	
3.6	प्रकट रूप	विशेष			
3.7	मांस का रंग	यथोक्त			
3.8	मांस की गंध	यथोक्त			
3.9	मांस की सुवास	यथोक्त			
3.10	मांस की तन्तु	विशेष			
3.11	मांस का विवर्ण	शून्य			
3.12	नमक की प्रतिशतता	3.5% अधिकतम डिब्बा-बन्द शिम्प के लिए डब्ल्यू/वी; 2% अधिकतम केकड़े के मांस के लिए डब्ल्यू/वी	अनुसूची II के अनुसार	किसी संकेत की प्रत्येक श्रेणी	
3.13	अम्लीयता की प्रतिशतता	0.2% डब्ल्यू/वी			
3.14	निर्वात	150 मि०मी०			
3.15	मुक्त स्थान	5 से 7.5 मि०मी०			
3.16	डिब्बे का बाह्य भाग और अंदर का भाग	संतोषजनक			
3.17	लवण—जल	स्पष्ट	यथोक्त	उन एककों के लिए जिनमें निरीक्षण, खंड 3.2 के अनुसार	
3.18	जीवाणु संवर्धी परीक्षण	थियोग्लाइकोलेट ब्रॉथ में कोई उत्पत्ति नहीं			
4.	पैक करना और लेबिल लगाना .				
4.1	जंग रोधी प्रयोग	निर्यातकर्ता की अपेक्षानुसार	100%	प्रत्येक दिन का उत्पादन	
4.2	लेबल लगाना	यथोक्त	1%	यथोक्त	
4.3	गत्ते के बक्सों में पैक करना	यथोक्त	1%	यथोक्त	
4.4	पात परीक्षण	*	गत्ते के 3 बक्सों का पैक	यथोक्त	
4.5	जल फुहार परीक्षण	**	यथोक्त	यथोक्त	
5.	उपकरण नियंत्रण .				
क.	ताप संकेतक				
ख.	दबाव संकेतक				
ग	समय संकेतक	शुद्धता	प्रत्येक	पूर्वनिश्चित आवधिक आवृत्ति पर	प्रत्येक के लिए कुल कार्ड बनाया जा सकेगा
घ.	तराजू				
ङ	अन्य कोई मापक यंत्र				

* गत्ते के बक्सों को 150 से०मी० की ऊंचाई से गिराने पर न तो वे और न ही उनकी अन्तर्वस्तु को किसी प्रकार की हानि पहुंचेगी ।

** गत्ते के बक्सों को 24 घंटे के लिए नम वायु का छिड़काव करके विशेषतः नमक छिड़काव कक्ष में खुला रखा जाना चाहिए और 24 घंटे समाप्त होने के पश्चात् अंर्तवस्तु में बाह्य संक्षारण या कोई चिन्ह दर्शित नहीं होना चाहिए ।

अनुसूची II

(नियम 4 देखिए)

लॉट में गत्ते के बक्सों की संख्या (प्रत्येक में 24 डिब्बे होंगे)	चयन किए जाने वाले गत्ते के बक्सों की संख्या
12 तक	2*
13 से 24 तक	3*
25 से 40 तक	4*
41 से 80 तक	5
81 से 120 तक	6
121 से 180 तक	7
181 से 250 तक	8
251 से 350 तक	10
351 से 500 तक	12
501 से 750 तक	14
751 से 1000 तक	18
1001 से 1300 तक	22
1301 और अधिक	25

टिप्पण :

(1) इस प्रकार चयन किए गए प्रत्येक गत्ते के बक्स में से नमूने के रूप में एक डिब्बा निकाला जाएगा।

(2) जब पेटी में 24 डिब्बों से अधिक डिब्बे हों तो 24 डिब्बों वाली पेटी, इस सारणी का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए मानक पेटियां समझी जाएंगी।

(3) *एक लॉट में से लिए जाने वाले डिब्बों की न्यूनतम संख्या, लॉट में रखे गत्ते के बक्सों पर ध्यान दिए बिना 5 होगी।

प्रेषक

सेवा में,

निर्यात निरीक्षण अभिकरण,
कोचीन/कलकत्ता/बम्बई/मद्रास
महोदय,

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन तथा अपेक्षित निरीक्षण का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए परेषण का, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं कृपया निरीक्षण करें।

हम इस परेषण की निरीक्षण फीस के लिए एक---------- पर लिखा गया---------- ----------रुपये का चैक/ड्राफ्ट संख्या----------तारीख---------- को भेज रहे हैं।

*हम परेषण के लिए----------रुपए की निरीक्षण फीस हमारे जमा खाता पास बुक संख्या----------जो संलग्न है, में से विकलित कर दी जाए :—

1 निर्यातकर्ता का नाम और पता :

2 विनिर्माता का नाम और पता :

3 क्रेता का आदेश सं०/निर्यात संविदा सं० :

4 परेषण का विवरण :

(क) वस्तु का नाम :

(ख) ब्रांड नाम, यदि कोई है :

(ग) श्रेणी, आकार आदि :

(घ) मात्रा :

(ङ) पैकेजों की संख्या :

(च) मूल्य (पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य/सी०आई०एफ०) :

(छ) पोत विवरण :

5. उस स्थान का सही पता जहां माल निरीक्षण के लिए रखा गया है :

6. निर्यात संविदा में तथा अनुबंधित विनिर्देशों सहित तकनीकी की अपेक्षाएं :

7. पोत लदान का विवरण :

(क) पोत में लादने की संभावित तारीख :

(ख) पोत का नाम :

(ग) प्रस्थान की तारीख :

(घ) पोत लदान का पत्तन :

8. मील का विवरण, यदि कोई है :

9. कोई अन्य सुसंगत जानकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित परेषण, मछली तथा मछली उत्पादन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1981 में वर्णित नियंत्रण स्तरों के अनुसार विनिर्मित/प्रसंस्कृत किया गया है।

** यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त परेषण उपर्युक्त नियमों के पैरा 3.3.2 के अनुसार अनुमोदित लॉट में से है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी क्रेता द्वारा स्तम्भ में वर्णित अपेक्षाओं से भिन्न किसी अतिरिक्त तकनीकी या क्वालिटी अपेक्षा का अनुबन्ध नहीं किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी क्रेता द्वारा स्तम्भ 6 में वर्णित से भिन्न किसी अतिरिक्त तकनीकी या क्वालिटी अपेक्षा की मांग नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर :

पदनाम :

स्थान : निर्यातकर्ता की मोहर :

तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**नया आई०पी०क्यू०सी० प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादित परेषण के मामले में काट दें।

[सं० 6(4)/80 ई०आई० एण्ड ई०पी०]

S.O. 863.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 456, dated the 5th February, 1977, except in respect of things done or omitted to be done, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Export of Canned Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires —

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963),

(b) 'Agency' means any one of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Act,

(c) 'Canned Fish and Fishery Products' means—

I. All types of prawns (Shrimps) canned either in brine or in any other internationally approved medium or dry packed

II. Crab Meat Canned either in brine or any other internationally approved medium from meat of crabs like Scylla serrata, Portunus pelagicus, Neptunus pelagicus and Neptunus sanguinolentus.

3. Quality Control : The Quality Control of Canned Fish and Fishery Products intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act by effecting the requirements at 3.1 and 3.2 below together with the levels of control at different stages of processing as given in the Schedule I to these rules annexed hereto.

3.1 Minimum requirements for processing units :—Surroundings, Construction and lay out : Canneries surroundings area should be such as can be kept reasonably free of objectionable odours, soots, dust or other contamination. The surroundings of canning units shall not have any swamps, dumps or animal housing or unsatisfactory urinals which might pose any sanitary problem All the immediate approaches of the processing area which are under the physical control of the processor shall be concreted, tarred or turfed in a manner that there shall not be any room for wind blown dust and other contamination. The buildings should be adequate in size to avoid crowding of equipments or personnel, well constructed as to protect against the entry and harbourage of insects, birds or other vermin and to permit easy and adequate cleaning. The entry to the raw material storage area should be provided with nylon of wire meshed double doors.

The processing unit shall be housed in a building of permanent nature affording sufficient protection from normal climatic hazards like wind blown dust and rain. The lay out of different sections shall be such as to facilitate the smooth flow of work and to prevent possible contamination from pre-processing section.

The area in which the raw material is received and stored shall be separated from the area where the final product is prepared for packed in such a manner as to eliminate bacterial contamination of the finished product Areas and compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for the storage of inedible materials. The food handling area shall be completely separated from the area used for residential purposes. At each door of entry a foot washing pit of minimum 1.5 metre x 1.2 metre with antiseptic water and a hand washing pot with antiseptic solution shall be provided.

Ceiling wall and Floor : Ceiling should be designed and constructed to prevent accumulations of dirt, condensations of steam, harbourage of rodents and should be easy to clean. The ceiling should be at least 4 metres (13 ft.) in height, free of cracks and open joints and should be of a smooth, waterproof and light coloured finish. Internal walls of the cannery should be smooth, waterproof, free of pits and cracks, light, coloured and easily washable upto a minimum height of 1.3 meters. Wall to wall and wall to floor junctions may be rounded to facilitate cleaning. Walls should be free from projection and all pipes and cables should be neatly covered wherever necessary The floors should be constructed of durable waterproof, non-toxic, non-absorbant and non- corroding material which is easy to clean and disinfect. They should be nonslip and without crevices and should slope evenly and sufficiently to drain off water.

Fly-Proofing, Vermin and Animal controls : The processing area shall be provided with effective fly-proofing arrangements, and other suitable steps shall also be taken to prevent entry of other insects, rodents, birds cats, dogs etc. into the processing areas. The doors of entry and exist shall have nylon or wire mesh and shall be preferably of double door system. All the windows shall have nylon or wire mesh to prevent dust and fly.

Lighting and Ventilation : All the working areas shall be well lighted. Light bulbs and fixtures shall not be directly suspended over the processing table, or at any stage of the preparation of the product. These shall be of safety type to prevent contamination in the event of breakages. The premises should be well ventilated to prevent excessive heat, condensation and contamination with obnoxious odours, dust vapour or smoke. Special attention should be given to the venting of areas and equipment producing excessive heat, steam, obnoxious fumes, vapours or contamination by providing natural or mechanical ventilation Ventilation openings should be screened and if required, equipped with proper air filters. Windows which open for ventilation purposes should also be screened. The screens should be made removable for cleaning and should be made from suitable corrosion-resistant material.

Working tables and Utensils : All working tables, work surface, containers, trays, tanks or other utensils used during the processing of canned fishery products shall be of smooth, impervious, non-toxic material which shall be corrosion-resitant and shall be so designed and constructed as to prevent hygienic hazards and permit easy and thorough cleaning All food contact surfaces should be smooth, free from pits, crevices, substances harmful to man, and they should be capable of withstanding repeated cleaning and disinfection. Containers used for hoiding fishery products shall preferably be made of plastic or corrosion-resistant material. Bamboo baskets, wicker baskets and enamelled utensils shall not be used in the processing areas. The table top shall be of stainless steel or aluminium and shall be smooth and free from pits and crevices Working tables shall be so arranged as to permit smooth flow of work and easy cleaning of the area underneath and around them. No item with rust on it shall be in use in the processing hall.

Material washing tanks shall be so designed as to provide a constant change of water with good circulation and to have provisions for drainage and easy cleaning. Utensils used for inedible or contaminated materials should be identified by specific coloured painting and should not be used for handling edible products Adequate waste receptacles shall be provided for the frequent removal of waste material from the working areas during processing operations.

Equipments and machinery : Machineries and equipments shall be so designed as they can be easily dismantled to facilitate through cleaning and disinfection. Stationary equipments shall be installed in such a manner as will permit easy access litate through cleaning and disinfection. Stationary equipments and thorough cleaning and disinfection. Every cannery shall be equipped with the following equipments and machinery in sufficient numbers :

(a) Seaming machines or double seaming machines of semi-automatic or automatic type maintained in good working condition;

(b) Retorts equipped with (a) Thermometer, (b) Pressure gauge, (c) venting valves and (d) safety valves;

(c) Exhausting chamber with conveyor system; or any other suitable alternative arrangements;

(d) Standard weighing machines and weights;

(e) Blanching tanks and related utensils made of stainless steel;

(f) Code embossing machines capable of embossing a minimum of 5 digits in a line;

(g) Cooling tanks;

(h) Boiler and accessories of suitable type and capacity to supply steam for all normal operations at a time; and all steam-carrying pipes properly insulated/protected.

(i) Testing facilities to conduct routine tests such as seaming defects, pH, salinity vacuum, available chlorine etc. and ;

(j) Mechanical lifting equipments to handle crates containing processed cans wherever necessary.

Storage and Warehousing : The canning units shall have facilities for warehousing the canned products separately. The warehouse shall be of adequate capacity and shall be such that the stored products can be kept dry and non-exposed to extermes of temperatures. This shall also be sufficiently protected from dampness and maintained at a high level of sanitation and hygiene.

All detergents and disinfectants shall be stored separately There shall be separate facility for storing packing materials toxic substances such as rodenticides, fumigants, insecticides or other substances injurious to health except the fire fighting equipments. All these materials and equipments shall be handled by experienced personnel only.

Water and Ice : There shall be plantiful supply of potable water with suitable chlorination system allowing the residual chlorine content of the water to be varied at will in order to reduce multiplication of micro-organisms. If the water used for processing is from sources other than protected water supplies, a certificate of potablility of the same from the Agency or institutions approved by the Agency shall be produced if non-potable water is supplied for boiler and other auxiliary services, there shall no cross-connection between the auxiliary water system and the system carrying potable water. If the water is used from a storage tank, the tank shall be of sufficient capacity and shall be protected from extraneous contamination. The storage tank shall be cleaned at least once in a month. The minimum available chlorine content in water used for processing shall be maintained at 3.5 ppm level. Ice shall be made from potable water and shall be so manufactured, handled and stored as to protect it from contamination. If ice used is from external sources, it shall be ensured that the same is made from potable water and is not contaminated. Ice crushing machine, if used, shall be kept in good sanitary conditions. A special room or other suitable storage facilities should be provided to protect the ice from contamination and excessive meltage.

Sanitary facilities and Control : Each and every containers must be inspected carefully to ensure that it is undamaged and without feasible flaws. These containers shall also be cleaned thoroughly using potable water containing 10 ppm available chlorine before they are used for packing fishery products.

Washing and disinfection of working tables, trays, utensils and equipments : Necessary facilities shall be provided for for cleaning and disinfection of working tables, trays, utenils cutting boards, containers equipments and working implements which are used during processing. Utensils, trays and table tops which come in contact with unpacked material shall be washed initially with a suitable cleaning agent and finally with water containing 50 ppm available chlorine. Such cleaning and washing should be done as often as necessary.

Washing of the floor : The processing Hall shall be cleaned before the day's work starts and then at the end of each working shift. In addition, the cleaning and washing shall be done as frequently as necessary.

Sewage and waste disposal : There shall be suitable and adequate drainage facilities for the removal of liquid or semi-liquid wastes from the plant. There shall not be any floor area where water may collect and stagnate. Drains should be constructed of smooth and impervious material and should be designed to cope with the maximum flow of liquid without any overflowing and overflooding. The drainage lines carrying water affluent except for open drain should be properly vented and if required run to a catchbasin for removal of the solid waste material. Such a basin should be located outside the proctssing area and should be constructed of waterproof concrete or other similar material. The openings of open drains, if any, which pass through walls shall be fitted with metal grills to prevent the entry of rodents The arrangements for disposal of sewage waste water and offal shall be done as quickly as possible and shall be such that it shall not cause any sanitary problems to the neighbourhood The sewage from the toilet shall be disposed of in such a manner that the same shall not be accessible to flies and shall not contaminate the units water supply On no account shall there be accumulation of waste or water of any kind in the premises. Exclusion of dogs and animals from factory premises The dogs, cats and other animals being potential carriers of disease shall nto be allowed to enter or to live in or nearly the processing premises.

Toilet facility : Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided. The toilets shall be provided with self-closing doors, and with wash basins and soap. Potable water shall be used for washing purposes.

Personal health and hygiene : Plant management shall take care to ensure that no person who is either carrier of or known to be affected with a communicable disease is permitted to work in any area of the unit. In order to facilitate the detection of such disease, the management shall conduct at least yearly medical examination of personnel working in any areas of the unit.

All persons working in a cannery shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty and shall take all precautions to prevent contamiation of fishery products with any foreign substance. The management shall provide clean aprons and headgears to all employees according to the nature of their work. Gloves used in handling of fishery products shall be maintained in clean and sanitised condition and shall be made of impermeable material except where their use would be incomplete with the work involved.

Workers shall wash their hands thoroughly with soap or other cleaning agent and warm water before commencing each day's work and on every occasion after visiting a toilet and before resuming work, and also on other occasion, wherevery necessary. Workers shall also wash their feet with potable water after each absence from the processing hall. Eating, smoking, chewing of tobacco or other materials spitting and any such other habit which may or is likely to contaminate the product during handling and processing shall be strictly prohibited in any part of the handling and processing area Where workers of both sex are employed, separate toilet facilities changing rooms and rest room shall be provided.

Clothing and footwear not worn during working hours shall not be ketp in any processing area.

Transportation facilities : As far as possible, raw material shall be transported in a insulated/refrigerated conveyance. However, if raw material is transported in ordinary trucks, it shall be done in closed-body-vehicle and the raw material shall be adequately iced. Such conveyances should be cleaned and disinfected immediately after use and should be so maintained as not to constitute a source of contamination of the product.

Cleaning of the conveyances together with the necessary receptacles and equipments, shall be done on a routine basis. Hosing, scrubbing and cleaning of the convevance with potable water or clean sea water to which a suitable detergent or disinfectant has been added shall be done

Maintenance of records : Necessary registers and records as prescribed in this regard from time to time, shall be maintained by the processor in order to ensure effective control on the processing of canned fish and fishery products and these shall be made available to the Agency officers as and when required. Specific records shall be maintained at a periodic intervals of three months about the calibration of measuring and recording instruments like pressure gauge, ammeters, volt meters weighing scales, weights etc.

3.2 In addition to the requirements mentioned at caluse 3.1 above a processing unit may also arrange for the following additional facilities in their processing unit :

(a) The processing unit shall have competent and qualified personnel to supervise pre-processing and processing operations to conduct physical and organoleptic evaluation and to test for chemical factors and bacteriology of canned fish and fishery products meant for export.

(b) Such personnel should possess any one of the following qualifications :

I. A degree/Diploma in Fishery Science/Processing from a recognistd institute under a University; or

II. A degree in Science with at least two years experience in the analysis and testing of fish and fishery products.

(c) The unit shall have its own laboratory with all necessary equipments and chemicals to carry out analysis and testing of canned fish and fishery products meants for export.

(d) The unit shall have its own exclusive and separate area for processing, starting from rectiving or raw material to packing.

3.3 Approval of processing units :

3.3.1 A processor intending to process canned fish and fishery products for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Council, to the nearest office of the Agency. On receipt of such intimation, the Agency officers shall visit the processing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit. If the unit is found to have the minimum facilities as prescribed in these rules, a panel of experts constituted for this purpose by the Council shall adjudge the adequacy of the facilities in the unit and recommend its approval or disapproval to the Agency for further necessary action. Within fifteen days of receiving the recommendation of the Panel, the Agency shall either approve the unit and permit it to carry out processing of canned fish and fishery products for export, or not approve the same and shall not allow the processor to process canned fish and fishery products for export. After granting the approval the Agency Officer shall conduct periodic visit at regular intervals to such unit to ensure the maintenance of Pannel approved arrangemets. The Agecy Officers also shall draw samples from units having arrangements under clause 3.2 above for Bacteriological tests in the Laboratory and organoleptic examination at the unit

3.3.2 Non-approval : In case the unit is not approved, it shall be communicated to the processor in writing pointing out the deficiencies recorded by the Pannel.

A processor, after rectifying such deficiencies as pointed out by the Panel, shall submit a fresh application to the Agency along with a detailed report of rectifications of the deficiencies carried out by him. On receipt of this application, the Agency shall take the steps detailed in 3.3.1 above.

3.3.3 The approval accorded at any time to a processing unit shall be withdrawn on the basis of reports received on the periodic visits and test reports on samples drawn during these periodic visits in the case of units under 3.2 above conducted by the Agency officers by giving a notice to the concerned processor after 7 days from the date of receipt of the notice by the processor for any of the following deficiencies provided no remedial measures are taken by the processor within these 7 days.

If the processing equipments, machinery and storage facilities are not in good working conditions;

If the sanitary and hygienic conditions of the unit are not satisfactory;

If samples drawn for counter-checks fail to meet the laid down standards;

If the processor has violated or deliberately attempted to violate the provisions of the notification or instructions issued from time to time.

In the case of approval accorded to the processor, under the additional requirements at 3.2 above, it shall be withdrawn at any time provided that;

If any of the deficiencies mentioned above is noticed;

If complaints are received from foreign buyers regarding the quality of canned fish and fishery products exported by the processor and on investigation the same were found genuine;

If 2 consecutive consignments of canned fish and fishery products have been rejected by the importing country.

Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

3.4 Re-approval :

A unit whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects, make a fresh application to the Agency for getting fresh approval

For reasons given at 3.3.3 above, if at any time, there is any difficulty in maintaining conformity of the products to the specifications, or if directed by the Agency to suspend production for export, the processor shall suspend production for export under intimation to the Agency. The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing.

3.5 Processing :

The processor shall carry out processing only in approved units under the supervision of competent technical personnel. Only such raw material, which are fresh, clean, wholesome, having the characteristic appearance, odour, colour and texture of species, shall be accepted for processing.

4. Inspection :

The inspection of canned fish and fishery products meant for export shall be done by drawing samples, wherever necessary, as per schedule II annexed hereto from the consignment for carrying out examination and testing of the same with a view to seeing that the consignment conforms to the standard specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act

5. Basis of inspections :

Inspection of canned fish and fishery products intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

Either

(a) By ensuring that during the process of manufacture the quality control drills as specified in Rule 2 has been exercised;

OR

(b) on the basis of inspection carried out in accordance with Rule 3 and 4 except sub-rule 3.2 of Rule 3.

OR

(c) by both.

6. Procedure of Inspection and Certification :

6.1 An exporter intending to export canned fish and fishery products shall submit an intimation in prescribed proforma (see Appendix I), giving particulars of consignment intended to be exported, to the nearest office of the Agency.

6.2 Every such intimations shall reach the office of the Agency not later than 4 days and 15 days in the case of consignments offered for inspection under Rule 5 (a) and 5(b) respectively before the anticipated date of despatch of the consignments from the exproters premises.

6.3 On receipt of the intimation under Rule 6.1 the Agency on satisfying itself on the basis of inspection carried out as provided for under Rule 5 and the instructions, if any, issued in this respect that the consignment has been processed and packed according to the standard specifications applicable to it, shall issue a certificate declaring the consignment of canned fish and fishery products as export-worthy within 4 days or 15 days as the case may be :

Provided that where the Agency is not so stisfied it shall within the period of 4 days or 15 days as the case may be, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

6.4 Super Inspection :

Subsequent to certification, the Agency shall have the right to re-assess the quality of the consignment in the storage, in transit or at the ports. In the event of consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate originally issued shal be withdrawn.

6.5 Validity :

The certificate issued shall be valid for 90 days from the date of approval of the lot. If more than one lot approved

on different days are presented in one application, the validity of the certificate shall be reckoned from the earliest date of approval.

If the consignments are not shipped within the period of validity of the certificate, the exporter shall be permitted to present he consignment for revalidation. For this purpose the inspection fee at the notified rates shall be charges and the consignments shall be examined by drawing samples as per the sampling scale prescribed by the Council in this behalf, for organoleptic inspection only. In such cases, the validity shall be extended for a further period of 30 days from the date of completion of inspection.

For a consignment not shipped within the validity period mentioned in 6.5, an ad hoc extension of validity for a period not more than 15 days may be granted by the Agency, if found necessary.

7. Place of ispection :

The inspection of canned fish and fishery products for the purpose of these Rules, shall be carried out at the premises of the processor and/or at the laboratory of Export Inspection Agency. The processor shall provide all necessary facilities to the Agency to enable them to carry out such inspection.

8. Inspection Fee :

A fee at the rate of (i) eight paise per kg. or part thereof when the inspection is carried out on the basis of Rule 5(a) and (c); and (ii) fifteen paise per kg. or part thereof when the inspection is carried out on the basis of Rule 5(b) shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee.

9. Appeal :

9.1 Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate of exportworthiness under Rule 6, may, within 10 days of receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of Experts consisting of not less than three, but not more than 7 persons, appointed for the purpose by the Central Government.

9.2 At least two-thirds of the total membership of the panel of Experts shall consist of non-official.

9.3 The quorum of the Panel shall be three.

9.4 The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

A. SPECIFICATION FOR PRAWNS (SHRIMPS) CANNED IN BRINE OR IN ANY OTHER INTERNATIONALY APPROVED MEDIUM OR DRY PACK.

1. Raw Material :

1.1 The raw material used for preparation of prawns/shrimps canned in brine shall be fresh, sound, wholesome, properly cleaned and free from entrails.

1.2 Only refined salt conforming to IS : 594-1962 shall be used.

2. Cans :

2.1 The material shall be packed in suitable internally and uniformly lacquerred cans. The cans may also be lacquered externally subject to agreement between the purchaser and the processor. The lacquer used shall be such that it does not impart any foreign unpleasant taste and smell to the contents of the can and does not peel off during processing and storage. The lacquer shall not be soluble in brine to any extent. The can exterior shall be free from major dents, rust, perforations and seam distortions.

2.2 The cans after sealing hermetically shall not show leaking, panelling or swell. The interior of the can on opening shall not show any visible black discolouration, rust or pitting and the inside lacquer shall be in good condition.

3. Brine :

3.1 The brine, if used, shall be clear and shall not be discoloured.

4. Packing Labelling

4.1 Only material of the same species shall be packed in a can.

4.2 The labels, if used, shall be in accordance with the rules and regulations of the country to which the material is to be exported.

5. Drained weight and size grade :

5.1 The net drained weight of contents shall not be less than the declared weight.

5.2 The size count (Number of pieces per unit weight) shall conform to the size grade declared on the can.

6. Organoleptic quality :

6.1 The contents of the can on opening shall present a good appearance and shall not display any appreciable disintegration. Pieces from which portions have separated out would be treated as disintegrated shrimps.

6.2 The surface of the prawns shall not appear slimy to the touch. The meat shall be soft but firm and shall not crumble to granular forms when pressed between fingers.

6.3 The prawns pieces shall not appear to be pressed together and it should be possible to separate the pieces easily. The pieces shall be of uniform size and shall be clean and free from loose hanging pieces of meat.

6.4 The material shall have the odour and flavour of fresh and cooked prawn meat and shall be free from scorched, bitter or any other objectionable flavour.

6.5 The material shall be free from pale bleached colour with a greenish yellow tint indicative of pre-processed spoilage. The material shall also be free from any black discolouration.

6.6 The material shall be free from sand, dirt, insect, hair or any other extraneous matter. It shall be reasonably free from bits of veins, shall particles and pieces of appendages.

6.7 The material shall be free from any poisonous and deleterious substances.

6.8 The cans on opening shall not give any odour indicative of bacterial spoilage, shall not show liquefaction of contents and shall not show blackening.

6.9 The product shall also conform to the following requirements :

Sl. No.	Characteristics	Requirements	Methods of test Ref. to Appendix in IS: 2236—1968**	Appendix in IS: 2168-1962*
(i)	Vacuum of the can in mm., Min.	100	A	—
(ii)	Head space of the can in mm.	5.0 to 7.5	—	B
(iii)	Drained weight of the contents of the can, as percentage by weight of the water capacity of the can, min.	64	B	—

1	2	3	4	
(iv)	Sodium chloride in brine percent (W/V) Max.	3.5	C	—
(v)	Acidity of brine as citric acid (anhydrous) percent (W/V)	0.05 to 0.20	D	—
(vi)	Arsenic, parts per million, max.	1	—	C
(vii)	Lead, Parts per million, max.	5	—	D
(viii)	Copper, parts per million, max.	10	—	E
(ix)	Zinc, parts per million, max.	50	—	F
(x)	Tin, parts per million, max.	250	—	G

*Specification for pomfret canned in oil.

**Specification for prawns/shrimps canned in Brine (First Revision).

7. Bacteriological Requiremets :

7.1 The initial incubation of the sampled cans shall be done at 37°C for seven days. After this incubation, necessary quantity of the liquid portion is acceptically pipetted out and inoculated into thioglycollate cystine broth and incubated at 37°C for 48 hours. The incubated broth shall not show bacterial growth.

8. Coding :

8.1 The cans shall be embossed with the markings of size-grade, drained weight, name of the manufacturer or his factory code, year, month, and batch of manufacture. An illustration for embossing the code in the abbreviated form is given below :—

T 5 X

1 B05

T5 stands for 'Tiny' packed with 5Oz. drained weight. 'X' stands for the name of the manufacturer in the abbreviated form or the factory code, '1' stands for the year of manufacture, and in this illustrations, it signifies the year 1981. 'B' stands for the month of manufacture (here it signifies the month of February) and '05' stands for the date of manufacture during the month. In case PUD material is used for canning, the letter 'U' shall be embossed prior to the marking for size grade. For the purpose of denoting the size grade and the drained weight, the following nomenclature shall be followed.

(A) Size-Grade*

Nomenclature	Count/100 gms	Abbreviation
Colossel/Supreme Jumbo	Below 8	C/SJ
Jumbo	9 to 13	J
Large	14 to 22	L
Medium	23 to 36	M
Small	37 to 63	S
Tiny	64 to 102	T
Cocktail/Mini/Salad	103 to above	CT/MI/SD
Broken/whole & Broken	No limit	B/WB

*Pack having more than 10% broken pieces by weight irrespective of the total number of pieces in the can shall be treated as 'Broken'. Any pieces showing less than 4 segments shall be treated as broken.

(B) Drained Weight:

Except in the case of 4.5 oz. pack, which being the standard pack, the actual drained weight shall be embossed in oz. on the cans.

(C) The month of manufacture shall be designated as—

Month	Abbreviation	Month	Abbreviation
January	A	July	G
February	B	August	H
March	C	September	J
April	D	October	K
May	E	November	L
June	F	December	M

B. SPECIFICATION FOR CRAB MEAT CANNED IN BRINE OR ANY OTHER INTERNATIONALLY APPROVED MEDIUM

1. Raw Material:

1.1 The meat used for canning shall be obtained from healthy, freshly caught, crabs of the species as scylla serrata, Portunus pelagicus, Neptunus pelagicus and Neptunus Sanguinolentus.

2. Cans :

2.1 The material shall be packed in suitable internally and uniformly lacqered cans. The cans may also be lacquered externally subject to agreement between the purchaser and the processor. The lacquer used shall be such that it does not impart any foreign unpleasant taste to the contents of the can and does not peel off during processing and storage. The lacquer shall not be soluble in brine to any extent. The can interior shall be free from major dents, rust, perforations and seam distortions.

2.2 The cans after sealing hermetically shall not show leaking, panelling or swell. The interior of the can on opening shall not show any visible black discolouration, rusting or pitting and the inside lacquer shall be in good condition.

3. BRINE

3.1 Vacuum dried salt or common salt conforming to IS : 594-1962 shall be used for preparing brine. The sodium chloride content of the brine, if used, shall not exceed 2% W/V, Max.

3.2 Acidity of brine as citric acid (Anhydrous) shall be 0.20% W/V, Max.

4. Packing and labelling :

4.1 Crab Meat shall be packed using parchment paper lining.

4.2 The body meat and claw meat of the crab shall be packed according to the terms of contract agreed upon between the buyer and the seller.

In the absence of contractual specifications, the claw meat shall be packed on the top and at the bottom in distinctly separate layers.

4.3 Only the meat of one species of crab shall be packed in a particular can. The meat obtained from crabs caught from back waters and sea shall not be mixed or packed in a particular can.

4.4 Word 'Produce of India' should be embossed on the tin.

5. Drained Weight :

5.1 The net water capacity of the can shall be as per the requirements of the importing country :

5.2 The drained weight of the meat shall not be less than the declared weight.

6. Requirements for finished products :

6.1 The contents of the can on opening shall present a characteristic colour and odour of crab meat and shall not give any foreign odour.

6.2 The material shall be free from scorched, bitter or any objectionable flavour.

6.3 The material shall be free from stains, dirt, insect, hair or any other extraneous matter. It shall be free from veins, membrane, shall particles and places of appendages.

6.4 The material shall be free from bluish colour.

6.5 The material shall be free from any poisonous and deleterious substances.

6.6 Crab Meat canned in brine should conform to the following requirements also :

TABLE I : REQUIREMENTS FOR CRAB MEAT CANNED IN BRINE:

Sl. No.	Characteristic	Requirement	Method of Test, Ref. to Appendix of	
			IS: 7143*	IS: 2236**
			1973	1968
(i)	Vacuum in can in mm. Min.	150	—	A
(ii)	Sodium Chloride in brine percent by weight, max.	2%	—	C
(iii)	Acidity of brine as citric acid (anhydrous) percent (W/V), Max.	0.2%	—	D
(iv)	Acid insoluble ash, percent by weight, max.	2	A	—

*Specification for Crab meat canned in brine.

**Specification for prawns/shrimps canned in brine (First revision).

TABLE II. LIMITS OF METALLIC IMPURITIES IN CRAB MEAT CANNED IN BRINE

Sl. No.	Characteristic	Requirement	Method & Test, Ref. to Appendix in IS:2168-1971*
(i)	Arsenic, ppm, Max	1	B
(ii)	Lead, ppm, Max.	5	C
(iii)	Copper, ppm, Max.	10	D
(iv)	Zinc, ppm, Max.	50	E
(v)	Tin, ppm, Max.	250	F

*Specification for pomfret canned in oil (First revision).

7. Bacteriological Requirements

The initial incubation of the sampled cans shall be done at 37°C for seven days. After this initial incubation, the brine of the cans, on inoculation into thiogiycollate cystine broth and incubation at 37°C for 48 hours, shall not show any sign of bacterial growth.

8. Coding :

8.1 The cans shall be embossed with the markings of the drained weight, name of the manufacturer or his factory code and year, month and date of manufacture. An illustration for embossing the code in the abbreviated form is given below :

C B 5 X

1B05

In the above illustration "CB" stands for Crab Meat canned in brine "5" stands for drained weight and, in this illustration, it signifies 5 oz. drained weight "X" stands for the name of the manufacturer in the abbreviated form or his factory code "1" stands for the year of the manufacture and in this illustration, it signifies the year 1981. "B" stands for the month of manufacture and, in this illustration it signifies the month of February.

"05" stands for the date of manufacture during the month.

The months of manufacture shall be designated as:

Month	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
September	J
October	K
November	L
December	M

8.2 Drained Weight:

Except in the case of 4.5 oz. pack, which being the standard pack, the actual drained weight shall be embossed in oz. on the cans

SCHEDULE I

LEVELS OF CONTROL

(See Rule 3)

Sl. No.	Test or inspection Characteristics	Requirements	Qty/No. of samples to be tested	Lot/Size/frequency	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Material :				
1.1	Water	Potable quality with 3-5 ppm available chlorine; shall not contain coliforms more than 10 in 100 ml. and TPC not more than 100/ml.	250 ml.	Every day	

1	2	3	4	5	6
1 2	Raw Material				
	Temperature	10° C, Max	1 kg	Every 250 kg. or part thereof	
	Discolouration, Odour Black spot Foreign matter Loose shell Antennae etc Beet Testing	As per specifications	1 kg	-do-	
		Bact test for E coli, Max 20/g.	50 gms.	A day's total arrival	For units having control as per Clause 3 2
1 3	Ice	shall be colour-less, shall not contain coliforms more than 10 in 100 ml. & TPC not more than 100/ml	1 sample not less than 25 gms	Each day's receipt	
1 4	Cans Rust Lacquer Deformity	As per standard specification	100%	Each batch	
1 5	Cartons	As per exporter's requirements	1%	-do-	
1 6	Chemical	Pure Chemicals must be used		Each consignment.	
2	Processing				
2 1	Washing	3 times Min.	100%	Each lot	
2 2	Blanching				
	Concentration of the medium Duration of Dip Temperature of the medium	As per processors' requirements		Each batch	
2 3	Grading/Count	As per standard specifications	5%	Each code	
2 4	Filling weight	-do-		-do-	
2 5	Filling medium				
	Concentration	-do-	—	Each Mix.	
	Volume	Not less than 35% of the can capacity	5%	Each batch	
2 6	Exhausting Time Temperature	As per processor's requirements	5%	Each batch	
2 7	Seaming				
	Leakage	-do-	-do-	-do-	
	Seam strength	-do-	2 Nos.	-do-	
2 8	Sterilisation Temperature Pressure Duration	-do-	—	-do-	
2 9	Cooking water				
	Chlorine Content	-do-	5 c c	Every one hr	
3	Product				
3 1	Drained Weight	As per declared wt			
3 2	Antennae, legs, veins etc	5 Nos in a can max			
3 3	Foreign matter	Nil			
3 4	Broken pieces percentages	10% max			
3 5	Grade	Declared grade	As per Schedule	Each grade of a code II	
3 6	Appearance	Characteristic			
3 7	Colour of the meat	-do-			
3 8	Odour of the meat	-do-			
3 9	Flavour of the meat	-do-			
3 10	Texture of meat	-do-			
3 11	Discolouration of meat	Nil			
3 12	Percentage of salt	3 5% Max. W/V for canned shrimp, 2% Max W/V for Crabmeat	As per Schedule II	Each grade of a code	

1	2	3	4	5	6
3.13	Percentage of Acidity	0.2% W/V			
3.14	Vaccum	150 mm			
3.15	Head space	5 to 7.5 mm.			
3.16	Can interior and exterior	Satisfactory			
3.17	Brine	Clear	-do-	For units having control as per clause 3.2.	
3.18	Bact. Testing	No growth in thioglycollate broth.			
4.	Packing & Labelling :				
4.1	Anti-rust application	As per exporter's requirements	100%	Each day's production.	
4.2	Labelling	-do-	1%	-do-	
4.3	Packing in cartons	-do-	1%	-do-	
4.4	Drop test	*	3 Packed cartons	-do-	
4.5	Water spraying test	**	-do-	-do-	
5.	Equipment Control :				
	(a) Tempreature indicators (b) Pressure indicators (c) Time indicators (d) Weighing scales (e) Any other measuring instruments.	Accuracy	Each	At a pre-determined periodic frequency	History cards for each one may be maintained.

* The cartons when dropped from a height of 150 cms. neither the cartons nor the contents shall undergo any damage.

** The carton is to be allowed to be exposed against a spray of humid air preferably in a salt spray chamber for 24 hours and the contents inside shall not show any sign of exterior corrosion at the end of 24 hours.

SCHEDULE-II

(See Rule 4)

No. of cartons (containing 24 cans in each) in the lot	No. of cartons to be selected
Upto 12	2*
13 to 24	3*
25 to 40	4*
41 to 80	5
81 to 120	6
121 to 180	7
181 to 250	8
251 to 350	10
351 to 500	12
501 to 750	14
751 to 1000	18
1001 to 1300	22
1301 and above	25

Note:

(1) From each carton so selected one can shall be drawn as sample.

(2) When cases contain more than 24 cans the number of cases shall be computed as standard cases containing 24 cans, for the purpose of using this table.

(3) *The minimum number of cans to be drawn from a lot shall be 5, irrespective of the number of cartons in the lot.

APPENDIX I

From

_____

_____

_____

To

The Export Inspection Agency-
Cochin/Calcutta/Bombay/Madras.

Dear Sir(s)

Please carry out the inspection of the consignment, particulars of which are given below, for the issuance of a certificate of inspection, as required under the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

We are enclosing a cheque/draft No._____ dated_____for Rs._____on_____ towards inspection fee for this consignment.

*The inspection fee of Rs._____for this consignment may kindly be debited in our deposit account pass Book No. _____which is enclosed:

1. Name and address of the exporter
2. Name and address of the manufacturer.
3. Buyer's Order No./Export contract No.
4. Description of the consignment
   (a) Name of the commodity
   (b) Brand Name, if any
   (c) Grade size etc.
   (d) Quantity
   (e) No. of packages
   (f) Value (FOB/CIF)
   (g) Shipping marks

5. Exact address where the goods are lying for inspection

6. Technical requirements including specifications as stipulated in the export contract

7. Details of shipment
   (a) Probable date of loading into ship
   (b) Name of ship
   (c) Date of sailing
   (d) Port of shipment

8. Details of the seal, if any

9. Any other relevant information

It is hereby certified that the consignment mentioned above has been manufactured/processed in accordance with the levels of controls mentioned in the Export of Canned Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

*It is also certified that the above consignment is from the lots approved as per para 3.3.2 of the above said Rules.

It is also certified that no additional technical or quality requirements other than that mentioned at column 6 above have been stipulated by the overseas buyers.

Place: Signature:

Date: Designation:

Seal of the Exporter:

*Delete whichever is not applicable.

**Strike out in the case of consignment produced under IPQC System.

[No. 6(4)/80/EI&EP]

का० आ० 864—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण अभिकरण मद्रास को खनिज तथा अयस्क ग्रुप-1 के निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है।

[सं० 5(3)/83-ई०आई० एण्ड ई०पी०]

सी. बी. कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 864.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year Export Inspection Agency Madras as an Agency for the inspection of Minerals and Ores Group I.

[No. 5(3)/83-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर 1982

का० आ० 865.—कर्नल जय कृष्ण, 12 स्कूल लेन, न्यू को सामान्य सुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत टी०वी मानीटर के साथ या उसके बिना एक वीडियो टेप रिकार्डर का आयात करने के लिए 46000/-रुपये का सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी०/जे०/ 0391146/एन०/एम०एन०/ 83/एच०/82/ए०एल०एस० दिनांक 16-6-82 प्रदान किया गया था। प्रार्थी ने, उपर्युक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट खो गया या अन्यानस्थ हो गया है। आगे यह बताया गया है कि सीमा-शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क निकासी परमिट का मूल्य अभी तक उपयोग नहीं हुआ है।

2. अपने इस तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, दिल्ली के सामने विधिवत शपथ लेते हुए स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी० /जे०/0391146/एन०/एम० एन०/83/एच०/82/ए०एल० एस० दिनांक 16-6-82 प्रार्थी से खो गया अथवा अन्यानस्थ हो गया है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सी० सी०) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर्नल जय कृष्ण को जारी किए गए मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी० /जे० 0391146/एन०/एम० एन०/ 83 /एच०/82/ए० एल० एस० दिनांक 16-6-82 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रार्थी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सं० 17/119/ए०एम०-83/ए०एल० एस०]

जे० पी० सिंघल, उप मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 20th December, 1982

S O. 865.—Col, Jai Krishna, 12,School Lane, New Delhi was granted a C.C.P. No. P/J/0391146|N|MN|83|H|82|ALS dated 16-6-82 for Rs. 46000 for the import of one Video Tape Recorder with or without TV Monitor under G.C.A. The applicant has applied for issue of duplicate of the above mentioned CCP on the ground that the original CCP has been lost or misplaced. It has further been stated that the CCP was not Registered with any Custom Authorities and as such, the value of CCP has not been utilised at all.

2. In support of this contention, the licensee has filed an affidavit on stamp paper duly sworn in before a Notary Public, Delhi. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/0391146|N|MN|83|H|82|ALS dated 16-6-82 has been lost/misplaced by the applicant. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-55. as amended from time to time the said original CCP No P/J/0391146|N|MN|83|H|82|ALS dated 16-6-82 issued to Col. Jai Krishna.

3. A duplicate copy of C.C.P. is being issued to the applicant separately.

[F. No. 17/119/AM-83/ALS/3494]

J. P. SINGHAL, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1983

का० आ० 866.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 को विखण्डित करती है, उन बातों के संबंध में के सिवाय जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व इस आदेश के अधीन किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा० सं० 02011/3/78-नमक]

एस० बी० गोयल, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th January, 1983

S.O. 866.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Salt (Price Control) Order, 1977, except as respects things done or omitted to be done under the Order before such rescission.

[F. No. 02011/3/78-Salt.]

S. B. GOEL, Dy. Secy.

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1983

का० आ० 867.—केन्द्रीय सरकार, अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1982 (1982 का 50) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 752(अ) तारीख 20 अक्तूबर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की मद संख्या (7) और (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7. उपमुख्य कार्यपालक, अमृतसर आइल वर्क्स, अमृतसर।"

[फाइल संख्या 18/17/82 ई ओ पी]

टी० आर० परमेश्वरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना सं० का० आ० 752 (अ) तारीख 20 अक्तूबर, 1982 के अधीन प्रकाशित किया गया था। यह पहला संशोधन है।

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 25th January, 1983

S.O. 867.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Amritsar Oil Works (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1982 (50 of 1982), the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies No. S.O. 752(E) dated the 20th October 1982 namely :—

In the said order, for items numbers (7) and (8), the following shall be substituted namely :—

"7. Deputy Chief Executive, Amritsar Oil Works, Amritsar.

[F. No. 18/17/82-EOP]

T. R. PARAMESWARAN, Jt. Secy.

Note.—Principal order was published vide notification No. S. 0752(E) dated the 20th October, 1982. This is the first amendment.

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1983

का० आ० 868.—यत पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 754 तारीख 12-2-1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि० के क्षेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से दीपक फर्टीलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि० तलोजा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए।

महाराष्ट्र राज्य	जिला-रायगढ	तालुका-पनवेल	
गांव	गेट नंबर	क्षेत्र	
		स्क्वे० मीटर्स	
आसुडगांव	53 पी० टी०	102	00
	52 पी० टी०	26	00
	54 पी० टी०	38	00
	59 पी० टी०	28	00

[सं० O-12016/5/82-प्रो०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 28th January, 1983

S.O. 868.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 754 dated 12-2-82 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended, to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said

lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in Deepak Fertilizers and Petrochemical Corporation Ltd., free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State : Maharashtra	District : Raigad	Taluka : Panvel		
Village	G. No.	H. No.	Area	
			Sq.	Mtrs.
1	2	3	4	
Asudgaon	53 pt.	—	102	00
	52 pt.	—	26	00
	54 pt.	—	38	00
	59 pt.	—	28	00

[No. O-12016/5/82-Prod.]

का० आ० 869.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 756 तारीख 15-2-1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए दीपक फर्टिलायजर्स और पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० के क्षेत्रीय करण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तलोजा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य : महाराष्ट्र	जिला : रायगढ	तालुका : उरण		
गांव	सर्वेक्षण नंबर		क्षेत्र	
			एकड़े०	मीटर्स
नवघर	67	3 पी० टी०	21	00
	52	1 पी० टी०	14	00
		3 पी० टी०	20	00
		4 पी० टी०	18	00
		6 पी० टी०	4	00
	54	1 पी० टी०	25	00
		2 पी० टी०	18	00
		3 पी० टी०	15	00
		6 पी० टी०	12	00
		7 पी० टी०	14	00
		8 पी० टी०	10	00
		9 पी० टी०	12	00
	98	6 पी० टी०	16	00
		10 पी० टी०	14	00
		11 टी० टी०	14	00
	99	7 पी० टी०	30	00
	100	7 पी० टी०	16	00
		8 पी० टी०	12	00
		13 पी० टी०	14	00
		14 पी० टी०	22	00
	104	3 पी० टी०	8	00
	105	1 पी० टी०	20	00
		2 पी० टी०	10	00
	रेल	—पी० टी०	46	00
	नाला	—पी०टी०	16	00

[सं० O-12016/6/82-प्रो०]

S.O. 869.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 756 dated 15-2-82 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesing in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in Deepak Fertilizers and Petrochemical Corporation Ltd., free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited. Taloja.

State : Maharashtra	District : Raigad		Taluka : Uran	
Village	S. No.	H. No.	Area Sq. Mtrs.	
1	2	3	4	5
Navghar	67	3 pt.	21	00
	52	1 pt.	14	00
		3 pt.	20	00
		4 pt.	18	00
		6 pt.	4	00
	54	1 pt.	25	00
		2 pt.	18	00
		3 pt.	15	00
		6 pt.	12	00
		7 pt.	14	00
		8 pt.	10	00
		9 pt.	12	00
	98	6 pt.	16	00
		10 pt.	14	00
		11 pt.	14	00
	99	7 pt.	30	00
	100	7 pt.	16	00
		8 pt.	12	00
		13 pt.	14	00
		14pt.	22	00
	104	3 pt.	8	00
	105	1 pt.	20	00
		2 pt.	10	00
	Railway	pt.	46	00
	Nala	Pt.	16	00

[No. O—12016/6/82 Prod.]

का० आ० 870.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 757 तारीख 15-2-1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए दीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० के खेतीयकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से दीपक फर्टिलायजर्स और पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तलोजा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य-महाराष्ट्र	जिला-रायगड		तालुका-पनवेल	
गांव	सर्वेक्षण नंबर		क्षेत्र	
			स्क्वे०	मीटर्स
वहाल	सड़क	—	432	00
	440	1	64	00
	440	2	16	00
	441	1.	160	00
	422	—	84	00

[सं० O-12016/7/82-प्रोड]

S.O. 870.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 757 dated 15-2-82 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesing in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in Deepak Fertilizers and Petrochemical Corporation Ltd., free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Taloja.

State : Maharashtra	District : Raigad		Taluka : Panvel	
Village	S. No.	H. No.	Area	
			Sq.	Mtrs
1	2	3	4	5
Vahal	Road	—	432	0 0
	440	1	64	00
	440	2	16	00
	441	1	160	00
	422	—	84	00

[No. O-12016/7/82-Prod.]

का० आ० 871 —पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1963 (1963 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3084 तारीख 4-9-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

L.A. Case No. 1

अनुसूची

पाईप लाईन वाक्सई से दहिवली तक,
तालुका : मावल, जिला : पुणे, राज्य : महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर		क्षेत्रफल	
				हैक्टर	ऐयर
1	2	3		4	
वाक्सई		00 का भाग	..	00	00
		10 का भाग	..	00	11
		13 का भाग	..	00	04
		14 का भाग	..	00	20
		16 का भाग	..	00	11
		17 का भाग	..	00	15
		18 का भाग	..	00	13
		20 का भाग	..	00	09
		34 का भाग	..	00	18
		159 का भाग	..	00	20
		163 का भाग	..	00	16
देवघर		43 का भाग	..	00	18
		44 का भाग	..	00	27
		48 का भाग	..	00	29
		60 का भाग	..	00	16
		64 का भाग	..	00	35
		65 का भाग	..	00	11
		69 का भाग	..	00	42
		70 का भाग	..	00	20
कार्ला		81 का भाग	..	00	31
		161 का भाग	..	00	24
		163 का भाग	.	00	42
		165 का भाग	.	00	35
		166 का भाग	.	00	24
		167 का भाग	..	00	33
		168 का भाग	..	00	21
		206 का भाग	..	00	16
दहिवली		25 का भाग	3/4	00	32
		गेट नं० (64,65)	..		

[क्र० सं० 12016/26/82-प्रो०1]
एल० एम० गोयल निदेशक

S.O. 871.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 3084 (No. 12016/26/82-Prod. I) dated 4-9-82 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in Deepak Fertilizers and Petrochemical Corporation Ltd., free from encumbrances.

L. A. case No. 1/82.

SCHEDULE

Pipeline from Waksai to Dahivali

Taluka : Maval. Distt. : Pune Maharashtra

Village	Survey No.		Hissa No.	Area	
	Gut No.			H.	R.
1	2		3	4	
Waksai	Part				
,,	10	,,	—	00	11
,,	13	,,	—	00	04
,,	14	,,	—	00	20
,,	16	,,	—	00	11
,,	17	,,	—	00	15
,,	18	,,	—	00	13
,,	20	,,	—	00	09
,,	34	,,	—	00	18
,,	159	,,	—	00	20
,,	163	,,	—	00	16

1	2	3	4
Devghar	43 ,,	—	00 18
,,	44 ,,	—	00 27
,,	48 ,,	—	00 29
,,	60 ,,	—	00 16
,,	64 ,,	—	00 35
,,	65 ,,	—	00 11
,,	69 ,,	—	00 42
,,	70 ,,	—	00 20
Karla	81 ,,	—	00 31
,,	161 ,,	—	00 24
,,	163 ,,	—	00 42
,,	165 ,,	—	00 35
,,	166 ,,	—	00 24
,,	167 ,,	—	00 33
,,	168 ,,	—	00 29
,,	206 ,,	—	00 16
Dahivali	25 ,,	,, —	
	G. No. 64 & 65	3/4	00 32

[No. O—12016/26/82-Prod-I]
L. M. GOYAL, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1983

का० आ० 872.—यत: दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (घ) के अनुसरण में 27 मार्च, 1983 तक की शेष अवधि की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बंगलौर विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्यों ने 22 सितम्बर, 1982 को हुई अपनी बैठक में डा० बी० गोवर्धन हेगड़े, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्रोस्थोडोन्टिक्स विभाग, गवर्नमेंट डेंटल कालेज, बंगलौर को डा० एम० एन० नन्जप्पा के स्थान पर भारतीय दन्त परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है,

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 9 फरवरी, 1978 की अधिसूचना सं० का० आ० 533 में पुन: प्रकाशित भारत सरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 12 अप्रैल, 1949 की अधिसूचना सं० 10 10/48-एम-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "(घ) धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं० 10 और उससे संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"30. डा० गोवर्धन हेगड़े,	बंगलौर
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	विश्वविद्यालय,"
प्रोस्थोडोन्टिक्स विभाग,	
गवर्नमेंट डेंटल कालेज,	
बंगलौर-1	

[सख्या वी० 12013/4/82-पी० एम० एस०]
एम० पी० पाठक, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th January, 1983

S.O. 872.—Whereas in pursuance of clause (d) of section 3 read with sub-section (4) of section 6 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) Dr. B. Goverdhan Hegde, Professor and Head of the Department of Prosthodontics, Government Dental College, Bangalore, has been elected to be a member of the Dental Council of India by the members of the Senate of the Bangalore University to fill the casual vacancy for the reminder of the term till 27 March, 1983 in place of Dr. S. Nanjappa, in its meeting held on the 22nd September, 1982;

Now, therefore, in pursuance of clause (d) of section 3, read with sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 10-10/48-MI, dated the 12th April, 1949, as republished by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 533, dated the 9th February, 1978, namely :—

In the said notification, under the heading "(d) Elected under clause (d) of section 3", for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"10. Dr. B. Goverdhan Hegde,	
Professor and Head	
of the Department of	
Prosthodontics Government	
Dental College, Bangalore.	
Bangalore University	22-9-82".

[No. V-12013/4/82-PMS]

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O. 873.—In this Ministry's notification No. A. 12028/(i)/2/77-MS dated the 7th August, 1979, the following corrections /amendments are hereby notified.

S. No.	Parapage	For	Read
1	2	3	4
1.	Para 1; line 2.	Central Research Institute, Kasauli	Department of Serologist & Chemical Examiner to the Government of India, Calcutta.
2.	Para 4; under Disqualification.	Was	has
3.	(i) Para 4(b)		'has' to be inserted between 'or' and 'contracted'.
	(ii) Para 4(b) 7th line	Gounds	Grounds
4.	In the title at the top of the Schedule on P. O.	Directorate	Department
5.	In note 2 in Col. 7		After the word 'the Commission', the words 'is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be availabe to fill up the vacancies reserved for them' may be added.
6.	At the end of the Schedule on pg.3(a)	"Sd/- Under Secretary Union Public Service Commission"	May be Deleted

[No. A. 12025(1)/2/77-MS]
S.P. PATHAK, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1983

का० आ० 874.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय के शिमला तथा जबलपुर स्थित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[संख्या ई-11011/5/82-हिन्दी]

इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 25th January, 1983

S.O. 874.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hedeby notifies the Press Information Bureau's Offices located in Simla and Jabalpur, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E-11011/5/82-Hindi.]

I. B. KARN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1983

का० आ० 875.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने अरक्कोणम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-2-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-4/82पी०एच०बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 31st January, 1983

S.O. 875.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-2 1983 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Arakkonam Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/82-PHB]

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1983

का० आ० 876.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कोझुवनाल टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-2-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[सं० 5-10/83-पी०एच०बी०]

New Delhi, the 2nd February, 1983

S.O. 876.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-2-1983 as the date on which the Measured Rate will be introduced in Kozhuvanal Telephone Exchange Kerala Circle.

[No. 5-10/82-PHB]

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1983

का. आ. 877.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने तेवाराम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-2-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-4/83-पी.एच.बी.]

New Delhi, the 3rd February, 1983

S.O. 877.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as Introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-2-1983 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Thavaram Max III Telephone Exchange Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/83-PHB]

का. आ. 878.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951, के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने तीरुपयाथन्गुदि टेलीफोन में दिनांक 16-2-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-4/83-पी.एच.बी.]

[आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक, (पी०एच०बी०)]

S.O. 878.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-2-1983 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Thirupayathangudi Telephone Exchange Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/83-PHB]

R. C. KATARIA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

श्रम विभाग

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1983

का० आ० 879.— केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 1072, दिनांक 23 फरवरी, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, केरल राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

अध्यक्ष :

1. विशेष सचिव, केरल सरकार, श्रम विभाग, त्रिवेन्द्रम ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

सदस्य :

2. उप सचिव (वित्त साधारण), केरल सरकार, वित्त विभाग, त्रिवेन्द्रम 3. उप सचिव (श्रम कल्याण), केरल सरकार, श्रम विभाग, त्रिवेन्द्रम ।	राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति ।
4. श्री अनन्थन सुब्रह्मणिया अय्यर प्रधान, केरल टाईल फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, त्रिवेन्द्रम । 5. श्री जैम्स माकिल, सचिव, एसोसिएटेड प्लान्टर्स आफ केरल, कूलूर, कोचीन—18 6. श्री एन० भागीरथन, प्रधान, सोनी कैश्यू एक्सपोर्टर्स, क्विलोन (केरल)	राज्य में नियोजकों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि ।
7. श्री थम्पानूर रवि, टी. सी. 25/1044, श्रीमूलम् रोड, थम्पानूर, त्रिवेन्द्रम-1 8. श्री जी० करुणाकरन पार्वती मन्दिरम् थिरुकाडावूर, क्विलोन, 9. श्री के० एन० रविन्द्रनाथ, महा मंत्री, सी० आई० टी० यू० केरल स्टेट कमेटी सिटू—हाउस, वांचियूर, क्विलोन	राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि ।

[संख्या एस-20012/6/78-पी० एफ०-2]

पी० सिन्हा, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 20th January, 1983

S.O. 879.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O.No. 1072, dated 23rd February 1976, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Kerala, consisting of the following persons, namely:—

1. Special Secretary to the Government of Kerala, Labour Department, Trivandrum. Members:	Chairman appointed by the Central Government.
2. Deputy Secretary (Finance General) to the Government of Kerala, Finance Department, Trivandrum. 3. Deputy Secretary (Labour Welfare) to the Government of Kerala, Labour Department, Trivandrum.	Two persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.
4. Shri Ananthansubramonia Iyer, President, Kerala Tile Factories, Manufacturer's Association, Trichur. 5. Shri James Makil, Secretary, Associated Planters of Kerala, Kaloor, Cochin-17. 6. Shri N. Bhagheerathan, Proprietor, Soni Cashew Exporters, Quilon.	Three representatives of employers appointed by the Central Government in consultations with the Organisation of employers in the State.
7. Shri Thampanoor Ravi T.C.25/1044, Sreemoolam Road, Thampanoor, Trivandrum-1. 8. Shri G. Karunakan Parvathi Mandiram, Thrikkadavoor, Quilon. 9. Shri K.N. Ravindranath, General Secretary, C.I.T.U Kerala State Committee, C.I.T.U House, Vanchiyoor, Trivandrum.	Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the Organisation of employees in the State.

[No. 20012(6)/78-PF.II]

P. SINHA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी 1983

का० आ० 880.—भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4286 तारीख 30-9-1976 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में पद रिक्त हुआ है ।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री ओ० पी० सिंगला को 17-1-1983 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या एस०—11020(1)/83-डी०-1(ए)]

New Delhi, the 25th January, 1983

S.O. 880.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court, New Delhi constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour No. S.O. 4286 dated the 30th September, 1976.

Now Therefore, in pursuance of the provisions of Section of 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri O.P. Singla as Presiding Officer of the Said Labour Court with effect from 17-1-1983.

[No. S-11020(1)/83-D.I.A. (i)]

का० आ० 881.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 3871 तारीख 30-9-76 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में पद रिक्त हुआ है।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री ओ० पी० सिंगला को 17-1-83 से उक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एस-11020(1)/83-डी-1(ए) (ii)]
एल० के० नारायणन, अवर सचिव

S.O. 881.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, New Delhi, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour No. S.O 3871 dated the 30th September, 1976.

Now Therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri O.P. Singla as the Presiding Officer of the Industrial Tribunal with effect from 17-1-1983.

[No. S-11020(1)/83-D.I.(A) (ii)]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 27th January, 1983

S.O. 882.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Kusunda Area No. VI, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workman which was received by the Central Government on the 24th January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 31 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Kusunda Area No. VI, Post Office Kusunda, Dist. Dhanbad;

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate

For the Workmen—Shri Lalit Burman, Vice-President, United Coal Workers' Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 19th January, 1983

AWARD

By Order No. L-20012/62/81-D.III(A), dated the 9th June, 1981, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Kusunda Area No. VI, Post Office Kusunda, District Dhanbad in stopping Shri Japu Bhuia, Miner/Loader from work with effect from the 1st December, 1976 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. Sri Lalit Burman, Vice-President, United Coal Workers' Union, affiliated to All India Trade Union Congress, which has sponsored the cause of the concerned workman, Japu Bhuia, has filed written statement and rejoinder on behalf of the workman asserting that the action of the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited in stopping Japu Bhuia, Miner, from work with effect from 1-12-76 is unjustified, whereas the management has filed written statement and rejoinder asserting that the said action of the management is fully justified.

3. In this case a petition was filed on 22-3-82 by Sri B. Joshi on behalf of the management stating that by Order No. L-20012/192/78-III(A) dated 26-4-80 the Central Government in the Ministry of Labour had already, at the instance of another Union, namely, the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, referred an industrial dispute to the Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, on the self same issue as has been referred to this Tribunal by Order No. L-20012/62/81-D.III(A) dated 9-6-81 and hence during the pendency of the adjudication of the reference made to Tribunal No. 3 where it has been registered as Ref. No. 29 of 1980, the present reference on the self same issue to this Tribunal at the instance of the United Coal Workers' Union affiliated to the All India Trade Union Congress, is not maintainable. Thereupon by order dated 19-4-1982 the management was given time to move the Ministry for transfer of this case to Tribunal No. 3 and to file a copy of the petition to be filed before the Ministry in this connection.

4. On 1-12-82, however, a petition was filed by Sri Lalit Burman on behalf of the workman objecting to the transfer of the case to Tribunal No. 3. On that date Sri Joshi appearing for the management submitted that the case which was referred by the Ministry to Tribunal No. 3 has since been disposed of and an award has been given which is pending Gazette publication and in that view of the matter he does not now press for transfer of this case to Tribunal No. 3, Sri Joshi, however, further submitted on behalf of the management that since an award has been given by Tribunal No. 3 in an identical case in which Japu Bhuia, Miner, having identity card No. 131052 is also a party, the present reference regarding Japu Bhuia, Miner, whose identity card number, which has been filed in this case, is the same, is not maintainable. On the other hand, it was submitted by Sri Lalit Burman appearing on behalf of the workman that Japu Bhuia having the same identity card number, who was party in the reference made to Tribunal No. 3 and whose case was sponsored by the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, was an imposter, and that Japu Bhuia, who is a party in the present reference and whose case is sponsored by the United Coal Workers' Union affiliated to the All India Trade Union Congress, is the real Japu Bhuia, his identity card number being the same. In order to appreciate the controversy between the parties it seemed necessary to see the award given by Tribunal No. 3 in the reference made to it which was pending Gazette publication, and, in the circumstance, the case was adjourned to 11-1-83 for deciding the preliminary question regarding the maintainability of the present reference on Gazette publication of the award made by Tribunal No. 3 in the case referred to it.

5. On 11-1-83 Sri Joshi appearing for the management filed a photostat copy of the award dated 9-11-82 given by Tribunal No. 3 in Ref. No. 29 of 1980 arising out of Order No. L-20012/192/78-D.III(A) dated 26-4-80 after serving a copy of

the award on Sri Burman appearing for the workman. Thereupon Sri Burman wanted time till 12-1-83 to study the award dated 9-11-82 given by Tribunal No. 3 before making his submission. Hence the case was fixed for 12-1-83 for hearing on the preliminary point regarding maintainability of the present reference in view of the award dated 9-11-82 given by Tribunal No. 3 in Ref. No. 29 of 1980.

6. On 12-1-83 the Order No. L-20012/192/78-D.III(A) dated 26-4-80 of the Central Government in the Ministry of Labour referring the dispute to Tribunal No. 3 was marked Ext. M-1 and the photostat copy of the award dated 9-11-82 given by Tribunal No. 3 in Ref. No. 29 of 1980 was marked Ext. M-2 on behalf of the management, and thereafter Sri Joshi on behalf of the management and Sri Burman on behalf of the workman were heard on the point of maintainability of the present reference in view of the aforesaid award dated 9-11-82 of Tribunal No. 3 and the award in this case was reserved.

7. By Order No. L-20012/192/78-D.III(A) dated 26-4-80 (Ext. M-1) the Central Government in the Ministry of Labour had, in exercise of its powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 referred to Tribunal No. 3, Dhanbad, for adjudication as to whether the action of the management in terminating the services of several concerned workmen mentioned in the Annexure including Japu Bhuia, Miner, with effect from 1-12-76 was legal and justified, and if not, to what relief the said workmen were entitled and from what date. By award dated 9-11-1982 (Ext. M-2) the Tribunal No. 3 in Ref. No. 29 of 1980 has held that the action of the management in terminating the services of the concerned workmen is legal and justified and they are not entitled to any relief.

8. The present reference which has been made to this Tribunal and which has been registered as Ref. No. 31 of 1981 has been made by the Central Government in the Ministry of Labour by Order No. L-20012/62/81-D.III(A) dated 9-6-81 and the dispute referred for adjudication is whether the action of the management in stopping Japu Bhuia, Miner, from work with effect from 1-12-76 is justified, and, if not, to what relief is the said workmen entitled.

9. From the order of reference (Ext. M-1) in Ref. No. 29 of 1980 decided by Tribunal No. 3 it would appear that date of appointment of Japu Bhuia, Miner, is 3-1-63 and his identity card number is 231052 and his Provident Fund Account number is C/332571. From the identity card which has been filed on behalf of the concerned workman, Japu Bhuia along with list of documents dated 16-11-81 in Ref. No. 31 of 1981 pending before this Tribunal it would appear that the date of his appointment is also 3-1-63 and his identity card number is also 231052 and his Provident Fund Account number is also C/332571.

10. It is, therefore, established beyond doubt that not only the subject matter of the dispute in the present Reference No. 31 of 1981 pending in this Tribunal is the same as was before Tribunal No. 3 in Reference No. 29 of 1980, but it is also established that Japu Bhuia, Miner, who is the concerned workman in Ref. No. 31 of 1981 pending in this Tribunal was also a party in Ref. No. 29 of 1980 before Tribunal No. 3 as not only his name but also date of appointment, identity card number and Provident Fund Account number in both the cases completely tally. That being so, once the dispute has been adjudicated against the concerned workman Japu Bhuia by award dated 9-11-82 given by Tribunal No. 3 in Ref. No. 29 of 1980, the same matter cannot be adjudicated upon again by this Tribunal.

11. The only difference between Ref. No. 29 of 1980 disposed of by award dated 9-11-82 given by Tribunal No. 3 and the Ref. No. 31 of 1981 pending before this Tribunal is that whereas in Ref. No. 29 of 1980 before Tribunal No. 3 the cause of the concerned workmen including Japu Bhuia Miner, was sponsored by another union namely, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, the case of Japu Bhuia Miner, in Ref. No. 31 of 1981 pending before this Tribunal has been sponsored by the United Coal Workers' Union which is affiliated to All India Trade Union Congress. But that will not make any difference in view of clause (d) of sub-section (3) of section 18 of the Industrial Disputes Act, 1947 which lays down that an award of a Tribunal which has become enforceable shall be binding not only on all parties to the industrial dispute, but, where a party is composed of workmen, on all persons who were employed in the establishment to which the dispute relates on the date of the dispute and all persons who subsequently became employed in that establishment.

12. Therefore, in view of the award dated 9-11-82 given by Tribunal No. 3, Dhanbad, in Ref. No. 29 of 1980 arising out of Order No. L-20012/192/78-D.III(A) dated 26-4-1980 of the Central Government in the Ministry of Labour in which it has been held that the action of the management in terminating the services of the concerned workmen including Japu Bhuia is legal and justified and they are not entitled to any relief, the present reference made to this Tribunal by the Ministry by Order No. L-20012/62/81-D.III(A) dated 9-6-81 on the self same issue in respect of Japu Bhuia is not maintainable and he is not entitled to any relief. The reference is answered and the award is given accordingly.

[No. L-20012(62)/81-D.III(A)]

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer

S.O. 883.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 24th January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 23 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonasdih, District Dhanbad;

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated, the 19th January, 1983

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012/178/79-D.III(A) dated the 9th October, 1980, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the Schedule to the said order and the said Schedule runs as follows —

"Whether the action of the management of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad in terminating the services of Shri Chhota Chhatu Chamar, Miner, with effect from the 26th October, 1976 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court, to-day, i.e. 19-1-83. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly The memorandum of settlement shall from part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

[No. L-20012(178)/79-D.III(A)]
MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.

MEMORANDUM

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Reference No. 23/80

Employers in relation to the management of Govindpur Colliery ;

AND

Their Workmen

Petition of compromise

The humble petition on behalf of the parties above named most respectfully sheweth :—

1. That without prejudice to the respective contention of the parties contained in their respective written statement, the parties have settled the dispute on the following terms:—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That Shri Alkaha Chamar, the son of the concerned workman named Chhota Chhatu Chamar will be given employment as miner/loader at Govindpur Colliery on probation for a period of one year. Thereafter the question of confirmation will be decided in accordance with the Standing Orders applicable to the establishment.

(b) That Shri Alkaha Chamar should produce two copies of the photographs duly attested by the B.D.O of the Area in which his village is situated and duly attested by the union in proof of his genuinity before his employment.

(c) That Shri Alkaha Chamar should report for duty within one month from the date of filing up this settlement before the Hon'ble Tribunal, otherwise he will forefeit his right of employment under this settlement.

(d) That the concerned workman Chhota Chhatu Chamar accepts his superannuation with effect from 26th October 1976 as legal and justified and he will not dispute regarding his date of birth which is 14-3-16 and will not claim any other benefit disputing his date of birth.

(e) That the union will consider this settlement as a special case and will not cite this case as a precedent in cases of age disputes relating to other workman.

2. That in view of this settlement there remains no issue to be adjudicated in the present case.

Under the facts and circumstances stated above this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to hold the settlement as fair and proper and be pleased to pass an Award in terms of this settlement.

For the Workmen. For the Employers

Sd/- (Illegible)

(1) Sd/- (Illegible)
(2) Sd/- (Illegible)

DECLARATION

I, Sri Chhota Chhatu Chamar, the concerned workman do hereby declare that the contents of the terms of the settlement were read over and explained to me and I have fully understood the same. I accept the settlement with my own volition without pressure from any side.

The concerned workman
put his L.T.I. in our
presence.

L.T.I. of Chhota Chhatu, Chamar.
(Illegible)

(1) Sd/- (Illegible)

(2) Sd/- (Illegible).

[No. L-20012(178)/79-D-III (A)]

S.O. 884.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bararee Coke Plant of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 13 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S.10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bararee Coke Plant of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, Distt. Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.
On behalf of the workmen—Shri B. Lal, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated, the 12th January, 1983

AWARD

This is a reference under Section 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012(328)/81/D.III(A), dated the 11th February, 1982 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bararee Coke Plant of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad in terminating the services of Shri Diplal Singh, Watchman with effect from the 19th October 1971 vide Management's Notice dated the 12th October, 1971 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

The workman in this case is Shri Dip Lal Singh, Watchman of Bararee Coke Plant. It is said that he was a permanent employee and his services were terminated w.e.f. 19-10-1971 without sufficient cause and without following the procedure of retrenchment as laid down in Industrial Disputes Act, 1947. Bararee Coke Plant belongs to M/s Bararee Coke Company Ltd.

before take over by the Central Government under an ordinance dated 17-10-71. It is the case of the workman that soon after the ordinance i.e. 19-10-71 his services were terminated. The workman protested against his illegal termination of services all along and even approached the higher echelon of the management of B.C.C.L. but with no result. This Industrial dispute was raised by the Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad, and since the conciliation failed a reference was made.

The management of BCC Ltd. in their Written Statement denied that the concerned workman was ever an employee of Bararee Coke Plant. The management of Bararee Coke Plant was taken over by the Central Government on 27-12-71 by a notification. The concerned workman was not on the roll of Bararee Coke Plant at the time of take over of the management and therefore he was not in employment of present management. A plea taken is since there was no employer and employee relationship between the management and the concerned workman at any time, this reference was invalid, illegal and without jurisdiction. The positive case of the management is that the concerned workman was an employee of Bhulanbaradee Coke Plant which was a separate establishment from Bararee Coke Plant. This Bhulanbaree Coke Plant was closed w.e.f. 1-7-70 by its owner M/s. Bararee Coke Co Ltd and all workmen were retrenched with effect from the date on account of the closure of that establishment. Shri Dip Lal Singh, the concerned workman, and two others were retained in services as Watchmen to guard the property the closed establishment. The management has further said that Bhulanbararee Coke Plant was transferred to M/s Pandey Vijoy Krishna Sahaye on 14-6-1971 by virtue on an agreement between the parties under which a new management did not accept the liability of the workmen who are required to be retrenched on Payment of retrenchment compensation by the previous management. The concerned workmen continued to be in employment by M/s. Bararee Coke Company Ltd. even after the transfer of the Coke Plant to M/s. Pandey Vijoy Krishna Sahave till such period when all other assets were disposed off M/s. Bararee Coke Co. Ltd. retrenched Shri Dip Lal Singh w.e.f. 14-10-71 by notice dated 12-10-71 and paid retrenchment compensation The case of the management is that the concerned workman accepted his retrenchment without any protest and withdrew the full amount from the Coal Mines Provident Fund Office. The management has also said that this dispute was raised after a lapse of 9 years by the union and so on this ground alone the reference should be dismissed.

On behalf of the workmen one witness Shri Dip Lal Singh (WW-1) was examined. His evidence is that he was first appointed in Bararee Coke Plant in the year 1964. He has further said that he was stopped from work from 1971 and he did not receive any notice for retrenchment. He was not paid any wages nor retrenchment compensation. His evidence is that with him there were nearly 25 other workmen in the plant and except him all are working in the plant or in the Colliery In his cross—examination he has admitted that from Bararee Coke Plant he was transferred to Bhulanbararee Coke Plant in 1966. There is only one document Ext. W-1 which has been admitted in the evidence on behalf of the workmen. This letter is a comment of the management before the AIC(C), Dhanbad on the dispute raised on behalf of the workmen.

On behalf of the management 3 witnesses have been examined. Shri Nand Kishore Kumar, MW-1 is the time keeper in Bararee Coke Plant since 12-2-69. His evidence is that the coke plant was taken over by the Central Government w.e.f. 27-12-1971. He has said that there was no person in the name of Dip Lal Singh working in Bararee Coke Plant. He has proved Ext. M-1 which is a token Register of Bararee Coke Plant. He has also proved Leave Register of Bararee Coke Plant, Ext. M-2. According to him these two registers contain the name of all the workmen between 1968—77. In his cross-examination MW 1 has said that M/s. Bararee Coke Company had another Coke Plant at Bhulanbararee, and Ext M-1 and M-2 are not in respect of Bhulanbararee Coke Plant. The witness did not know whether Bhulanbararee Coke Plant is also used to maintain similar token Register and leave Register. He has admitted that there was only one Works Manager for Bararee Coke Plant and Bhulanbararee Coke Plant.

MW-2 Shri Baleshwar Pathak is the Senior Personel Officer of Bararee Coke Plant. He has said that the Bararee Coke Plant is in Bhagiband Area while Bhulanbararee Beehive Coke Oven isin Bowra Area. Both these areas are under two different General Managers. The witness produced certain documents, and about them he says that he received these documents in the file maintained in Bhowra Area Office. He has proved a letter dated 12-10-71, Ext. M-3, which is a retrenchment notice issued to Dip Lal Singh. The acknowledgement card is marked X for identification. The representation letter is marked Y for identification. Another letter was marked Z for identification. He has proved Ext. M.4 which is a true copy of the letter dated 27-12-71 bearing signature of Shri J.C. Narula. He has said that Bhulanbararee Coke Plant was closed ever sihce he knows. In cross-examination the witness has proved Ext. W-1 about which I have said above. About the payment of retrenchment compensation the witness has said that he simply saw a bill. He did not check up any Register to ascertain whether the retrenchment compensation had been paid.

MW-3 is Shri Nar Bahadur. He has been working in Bararee Coke Plant since the year 1950. From 1968 he has been working as Habildar of Night Guards. He knows the concerned workman and he has said that the concerned workman signed Ext. M.5 The Acknowledgement card also bears the signature of Shri Diplal Singh and it has been marked Ext. M.6. The letter marked Z for identification has been signed by Shri I. K. Ghosh, the then Works Manager. The witness has proved Ext. M.7. The witness has said that the coke plant of Bhulanbararee was closed in the year 1970 when all the workers were retrenched. He has further said that the workman and some of the Guards continued to work even after closure and in 1971 they were also retrenched and received retrenchment compensation. The evidence of the witness is that Shri N. C. Chatterjee who is the Cashier paid the retrenchment compensation in his presence. In his cross-examination the witness has said that he was not working in the plant where the concerned workman used to work. He has further said that the workman received compensation hand to hand in the office of the Coke Plant. He has admitted that at the time of payment his duty was to be present to see that the undesirable element do not come to the office.

The admitted position on behalf of the workmen is this, since 1966 Shri Diplal Singh had been working in Bhulanbararee Coke Plant and it is also admitted position that Bararee Coke Co., which owned Bhulanbararee Coke Plant retrenched the workmen of Bhulanbararee Coke Plant. The concerned workman and some other continued thereafter to be in service. The case of the management is that the concerned workman was retreached by the ex-owner before the take over of the management by the Government. The case of the concerned workmen is that after an ordinance to take over the Collieries and Bararee Coke Plant the concerned workman was retrenched. Now let us consider the point that arises in this case for consideration.

In this reference the concerned workman Shri Diplal Singh is said to be a workman of Bararee Coke Plant belonging to Bharat Coking Coal Ltd. The nationalisation took place in the early part of 1972 but the take over was effected by virtue of an ordinance. The management's case is that the Bararee Coke Plant was taken over by the Central Government by virtue of a notification dated 20-12-1971. it is in this context that retrenchment notice dated 12-10-71. Ex M.3 has to be considered. Paragraph-2 of this letter reads thus :—

> "(2) By an agreement dated 14-6-1971 the Bee-hive Coke Ovens have been taken over by Pandey Bijov Krishna Sahay on contract. This Contractor is in possession of the Bee-hive Coke Ovens with effect from above date of Agreement (14th day of June, 1971). This Contractor is an independent Employer of his own workmen."

It will appear that the plea for retrenchment on the concerned workman is that the Coke Ovens had been taken over by a Contractor on condition that he would employ his own workmen. The concerned workman was asked to collect his dues before 19-10-71. This letter is very significant. It

has been signed by the Works Manager of Bararee Coke Co. Ltd. MW-3, the Habildar has said that the compensation was paid in the Office of Bararee Coke Plant. MW-2 who is an old employee of Bararee Coke Co. has said that there was only one Works Manager of Bararee Coke Plant and Bhulanbararee Coke Plant. The attempt on the part of the workman is to show that Bararee Coke Plant and Bhulanbararee Coke Plant was owned by the same employer and the same Works Manager used to manage both these plants and so both these plants must be taken to be part and parcel of the same establishment. On behalf of the Bharat Coking Coal Ltd. it has been admitted that Bararee Coke Plant and Bhulanbararee Coke Plant were both taken over and nationalised and Bharat Coking Coal Ltd. became the owner of both. For the sake of convenience they are located in different areas marked by the Bharat Coking Coal Ltd. but prior to nationalisation there is no doubt that both these plants i.e. Bararee Coke Plant and Bhulanbararee Coke plant were part and parcel of the same establishment. The case of the management is that Bhulanbararee Coke plant had been closed at the time of take over and it has never been worked thereafter. Of course, no document has been filed to show as to why Bhulanbararee Coke plant was never worked after nationalisation. The simple case of the management is that it was closed from before and there was no workmen to be taken over on the rolls of the Bharat Coking Coal Ltd. The case of the workmen on the other hand is that Bararee Coke Plant and Bhulanbararee Coke Plant belonged to the same establishment, and it will be necessary to see as to whether the concerned workman was retrenched, for otherwise he would be deemed to be workman of the plant which was running. In this connection Ext. M-3 has been referred together with Ext. W-1. It is firstly to be pointed out that there could be no retrenchment on the ground that the plant had been leased out to a Contractor. What is meant to be said is that the workmen of the plant could not be retrenched on the ground that the owner had employed contractor to work the plant. The Industrial Disputes Act does not envisage such a situation. It has been urged on behalf of the workmen that even if the plant was being run by a contractor the position would be that the Co. was running the plant. On this ground it has been stated that there could be no valid retrenchment under the Industrial Disputes Act. The next point urged is that no retrenchment compensation has been paid, and the management has produced no evidence to show that the retrenchment compensation was at all paid, MW-2, Personnel Officer has simply come to say that he had seen a bill for retrenchment compensation but he has not seen the register. Now no such document has been produced by the management, secondly the management examined MW-3, Shri Nur Bahadur to show that he was present at the time when the concerned workman was paid retrenchment compensation. MW-3 is deposing from memory and so in absence of documentary evidence it cannot be positively said that the concerned workman was at all paid retrenchment compensation. Atleast this is a matter to be proved in this Court and it has not been done. It is settled law that for the purpose of retrenchment to be valid the workman should be paid retrenchment compensation. In absence of the same the retrenchment cannot be at all valid and effective, and so in the eye of law the workman would continue to be in the employment of the establishment. It appears that the concerned workman was stopped from work on the ground that the Contractor was running Bhulanbararee Coke Plant instead of the owner himself. Since he would be still a workman of the establishment, he would be deemed to be an employee of the plant which the ex-owner was himself running i.e. Bararee Coke plant. Now this being the position at the time of take over of Bhulanbararee Coke plant, we cannot blame the Custodian for not enrolling the workman of Bhulanbararee Coke plant for the simple reason that ex-owner of Bararee Coke Plant did not record the name of the concerned workman as workmen of Bararee Coke plant on the assumption that the concerned workman had been retrenched. In the eye of law he was not retrenched. We also cannot blame the Bharat Coking Coal Ltd. for not putting the concerned workman on the to be an employee of the plant which the ex-owner was roll of Bharat Coking Coal Ltd after nationalisation as workman of Bararee Coke Plant but nevertheless the concerned workman never ceased to be a workman of Bararee Coke plant as retrenchment was illegal.

It has been urged on behalf of the management that in this reference the concerned workman has been said to be an employee of B.C.C.L. but there is no relationship of employer and employee between the two and so the reference is not maintainable. But in view of my findings that in the eye of law the concerned workman was never retrenched and so was an employee of Bararee Coke Plant, and therefore as he was a workman at the time of take over he would be an employee of the B.C.C.L. This reference is, therefore, maintainable.

The only pertinent question is as to whether the concerned workman can claim wages from the time of nationalisation from the B.C.C.L. i.e. from 1-5-72. The learned advocate representing the workmen has said that in the written statement filed on behalf of the concerned workman it had been specifically stated that the concerned workman himself and his union, the RCMS approached the officers of the B.C.C.L. for consideration of his case, and therefore the concerned workman is entitled to past wages. It has also been pointed that as against this plea no evidence had been adduced to negative the plea on behalf of the management This appears to be true that Shri Dip Lal Singh the workman for a pretty long time has been loitering in the street for his re-employment and so he should be allowed full wages for the idle period.

Thus considering all aspects of the case I have to hold that the action of the management of Bararee Coke Plant of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda District Dhanbad in terminating the services of Shri Diplal Singh, Watchman with effect from the 19th October, 1971 vide management's notice dated the 12th October, 1971 is not justified. Consequently, the concerned workman Shri Dip Lal Singh is entitled to be reinstated in his job w.e.f. 1-5-72 i.e. the date of nationalisation. He is also entitled to back wages and other emoluments w.e.f. 1-5-72 from M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

This is my Award.

J. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20012/328/81-D.III(A)]

S.O. 885.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Headquarters of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Koyala Bhawan, Post Office Koyala Nagar, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd January, 1983.

ARBITRATION AWARD UNDER SECTION 10-A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN RESPECT OF INDUSTRIAL DISPUTES BETWEEN THE MANAGEMENT OF BHARAT COKING COAL LIMITED, DHANBAD AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY RASHTRIYA COLLIERY MAZDOOR SANGH, DHANBAD

APPEARANCES :

Shri S. S. Mukherjee, Personnel Manager (NEE), Bharat Coking Coal Ltd, Dhanbad—Representing Employer

Shri G. D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC), Dhanbad—Representing workmen.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

AWARD

(1) By an Arbitration Agreement dated 24-7-82 published in the Gazette of India Part-II Section 3, Sub-section II as per Government of India in the Ministry of Labour orders No. L-20013(6)/82-D.III(A) dated 18/19-8-1982, parties above named referred the following specific matter in the dispute to my arbitration under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947. The Agreement inter alia provided that the decision of the Arbitrator shall be binding on them.

"Whether the demand of the Union—Sri Suresh Parsad Singh should be placed in technical Grade-B with retrospective effect is justified? If so, what relief the workman is entitled to?"

(2) At my instance the Deputy Chief Personnel Manager (NEE), B.C.C. Ltd., Karmik Bhawan, Dhanbad (hereinafter to be called as Management) filed the statement of their case with copy to Shri G. D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad (hereinafter called as Union) vide his letter No. BCCL/PA-III/Conc.|82|52178-79 dated 22-9-82. In turn, the union filed their rejoinder with copy to the management vide their letter No. BCL/82/8316-17 dated 5-11-82. Thereafter with a view to hear the parties personally also, the hearing was fixed at Dhanbad on 23-12-82 wherein both the parties participated. During the hearing on 2312-82, the parties stated as follows :—

Union :

Shri G. D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Singh, Dhanbad argued that the management had invited applications as per their Circular No. BCCL/CA-1/76|18932-19076 dated 6-8-1976 from the staff working in the BCCL for the selection for the post of Technical Assistant Grade B in the scale of pay of Rs. 510-854 (un-revised). The qualification required for eligibility of the candidates for applying for the said post was graduate in science with physics, Chemistry and Mathematics. Shri Suraj Prasad Singh, one of the applicant who qualified in the written test in the interview, topped the list of the selected candidates. Instead of placing Shri Suraj Prasad Singh, Clerk in the grade of Rs. 510—854 (un-revised) he was placed as Technical Assistant in the grade of Rs. 442—570 vide office order No. BCCL./PA-II/5|129|77|17791-94 dated 28|3 p-3-1977 and subsequently he was put in grade of Rs. 378—570, recovering the excess payment made to the workman for the period already paid vis-a-vis earlier order on the ground that the earlier order has typographical mistake indicating wrong scale of pay vide Order No BCCL/PA-II/5|2|129|77|60852-56, dated 15/16-11-79. It was added that quality control department of the management where the workman was working as a new one and the scale of pay for the technical assistant working in the said section have not been fixed by the NCW II. Therefore, the management after evaluation of the job had decided that the technical assistants working in the quality control department to be posted there should be given the pay scale of Rs. 510—854 (un-revised) as technical assistant Grade-B. Shri Suraj Prasad Singh joined as a result of the selection under reference in the quality control department as Technical Assistant on 1-4 1977. Technical Assistant in the quality control department are doing the same and similar job but being paid salary in different scale of pay. Shri Suraj Prasad Singh protested against the order placing him in the scale of pay of Rs 442—570 more than once to the management and in support, the workmans representative even produced/filed copies of workman's letters dated 2-3-79, 18-6-79, 10.11./9 12.11.79 and also a copy of the Regional Sales Manager, Coal India Ltd, Rourkela Sttel Plant letter No. RSM/BCCI CORRFS|738 dated 2-7-79 to the Personnel Manager, Commercial Directorate, Jealgora reuesting for redressal of the workman's grievances but of no avail. The said Regional Sales Manager again wrote to the G.M.P., BCCI, Dhanbad under letter No. RSM/DP(BCCL) CORRFS|994 dated 29-10-79.

Management :

The management represented by Shri S. S. Mukherjee, Personnel Manager (NFF), Karmik Bhawan, BCCL, during arguments admitted that the management had a few vacancies for the post of Technical Assistant grade-B in the scale of pay of Rs. 510—854 (un-revised) for the different offices in BCCL in quality control department. The minimum qualification for eligibility was B.Sc. The applications were invited only for the departmental employees. Although the applications have been specifically called for placement in the scale of Rs. 510—854 the Selection Committee recommended that the persons selected by them which include Shri Suraj Prasad Singh should be given one grade higher than the grade in which he was actually working. Shri Suraj Prasad Singh was working in clerical grade of Rs. 330—438, he was given clerical grade-II, i.e. 378—570. At the time of issuing office order erroneously instead of the scale of Rs. 378—570, the scale of Rs. 442—570 was shown. It was also admitted that the NCW II did not provide any wage scale for the staff working in quality control department as technical assistant and so the management having evaluated the jobs to be performed by the technical assistant and their responsibilities, had invited applications from the departmental candidates, for placement in the scale of Rs. 510—854 (un-revised). No recovery on account of the erroneous order issued and the excess payments made to the workman has been made. After subsequent consideration and as a matter of policy Shri Suraj Prasad Singh alongwith other staff have been placed as technical assistant grade-B since a few months back of 1982. It was added that the workman accepted the terms and conditions of the offer made to him by the order dated 20/31-3-77 (No. BCCL/PA-II|5|2|129|77|17791) and had he any grievance in this regard, he should not have accepted the offer.

A copy of the internal Circular No. BCCL./PA-1/76|18932-19076 dated 6-8-76 was produced by the management and has been taken on record. A copy of the minutes of the D.P.C. dated 18-1-77 was also produced by the management.

2. I have gone through the facts of the case and have carefully considered the arguments placed before me by both the parties including the documents filed by them during the hearing From the facts of the case, it is seen that the management had invited applications for the post of Technical Assistant Grade-B, laying qualifications of eligibility and also fixing the scale of pay for the said post after job evaluation because for the Technical Assistant Grade-B for working in the quality control department of the BCCL, no scale of pay had been laid down by the National Coal Wage Agreement No. II. After holding written test/interview, the Selection Committee, so formed by the management, found that the workman under reference viz., Shri Suraj Prasad Singh had topped the list of the selected candidates but was not given the scale of pay of Rs. 510—854/- (unrevised) decided by the management for the said post of Technical Assistant Grade-B on the grounds that the Selection Committee recommended a lower scale of pay. To my mind, the management's said argument does not appear to be convincing for the reasons that assuming none of the selected candidates was eligible for the said post and the said scale of pay specially when for such type of job, the Technical Assistants were being paid the same wages in other departments of the BCCL, and in view of the recommendations of the job evaluation committee. At most, the Selection Committee could have said that in the said written test and interview all were unfit for the said job and the management, acting thereon, could have initiated action for fresh selection after changing the norms and other conditions of eligibility etc. So far, the management's argument that the workman accepted the offer made to him of the lower scale of pay ceases to have any relevancy because thereafter he has been persistingly pleading through representations for the grant of the scale of pay of Rs. 510—854 (un-revised) for which he had been called for written test/interview and wherein he rather topped the selected candidates.

3. In view of the above facts and considerations, I am inclined to accept the contention of the Union that Shri Suraj Prasad Singh is entitled for the scale of pay of Rs. 510—854 (un-revised) alongwith the benefits accruing out of it with retrospective effect, i.e., the date of joining as such as per Management's order No. BCCL./PA-II/5|2|129|77|17791-94 dated 28/31-3-1977.

4 I give my award accordingly and no order as to costs.

SHYAM KRISHNA,
Dy. Chief Labour Commissioner

[No. L-20013(6)/82-D.III(A)]

A.V.S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 27th January, 1983

S.O. 886.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Shri Conceicao Pereira, Owner of Launch 'Anselmo' C/o Marine Traders, Goa and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/40 of 1982

PARTIES :

Employer in relation Shri Conceicao Pereira, Owner of Launch 'Anselmo' C/o Marine Traders, Vasco-da-Gama, Goa

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—No appearance.

For the workmen—No appearance.

INDUSTRY : Port & Dock STATE : Goa, Daman and Diu.

Bombay, dated the 10th January, 1983

AWARD

(Dictated in the Open Court)

By order No. L-36012/2/82-D.IV(A) dated 17-9-1982 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of Shri Conceicao Pereira, Owner of Launch 'Anselmo' in terminating the services of Shri Sham K. Pagi, Launch crew with effect from 23-3-1982 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Although the reference was received in the month of September, 1982 and although notices were issued to the parties neither the workman concerned nor the Union espousing the cause appeared in the case and the same is the case with the management, as a result of which despite the fact that the matter was fixed on 25-10-1982, 9-11-1982, 27.12.1982 and then on 3-1-1983, neither parties filed statement of claim or take any steps conducive to a decision on merit. There is therefore no go but to dispose of the reference.

No order as to costs.

Sd/-

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-36012/2/82/D.IV(A)]

S.O. 887.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to Messrs V. M. Salgaoncar and Brothers Private Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-4 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to M/s. V. M. Salgaoncar and Bros. Private Limited, Owner of Transhipper S. S. Sanjeevani, Vasco-da-Gama (Goa)

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the employer—Mr. P. K. Tele, Labour Consultant.

For the workman—Mr. F. Rebello, Advocate.

INDUSTRY : Ports & Docks STATE : Goa, Daman & Diu

Bombay, dated the 31st day of December, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-36012(1)/77-D.IV(A) dated 18th January, 1978, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs V. M. Salgaoncar and Bros. Private Limited, Owner of Transhipper S.S. Sanjeevani, Vasco da Gama (Goa) and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs V. M. Salgaoncar and Bros. Private Limited, Vasco da-Gama (Goa) in termination the services of Shri F.X. Rodrigues, Electrician, with effect from the 27th January, 1977 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The workman, F. X. Rodrigues, joined duties on ship S.S. Sanjeevani of the employer on 19-3-1976 as an Electrician He was assigned the duties in the crane and conveyor section of S.S. Sanjeevani. The workman when appointed was paid a fixed salary of Rs. 500/- per month. The workman stated in his statement of claim that as a result of an agreement between the Union representing the workmen employed on the S.S. Sanjeevani and the management, he was entitled to overtime wages, and also the food allowance. However, the workman was not paid overtime wages, and the food allowance The workman, therefore, informed the employer that he had not been paid the aforesaid allowances from the day he had joined his duty. The workman stated that he did not receive any reply from the management, but instead, was served with a notice dated 25-1-1977 in which it was stated that his services were no longer required. The workman complained to the Administrative Manager of the employer that his services had been terminated without any reason and that the decision of the management should be re-considered. The workman was informed by a letter dated 25-2-1977 that his services had been engaged on temporary basis and that they were terminated as the company no longer required the same. After the termination of the services of the workman, he was paid overtime wages and also the food allowance which were not earlier paid to him The workman, therefore, challenges the order of termination on the ground that it was mala fide and his services were terminated to victimise him for demanding overtime wages and food allowance. No reasons have been assigned for the termination of the service by the employer. The termination is alleged to be illegal as no notice was served on the workman and no retrenchment compensation was paid in terms of Section 25-F of the Industrial Disputes Act On these grounds, the workman prayed for a declaration that he continued to be in service and was entitled to full back wages and continuity of service.

3. The company resisted the claim of the workman by filing its written statement on 19-4-1978. The company pleaded as follows The workman was employed from 19-3-1976 purely on a temporary basis in a temporary vacancy. As the work for which the workman was employed came to an end around the end of January, 1977 the services of the workman were terminated by a letter dated 25-1-1977. The company denied that the services of the workman were illegally terminated with mala fide intentions. The company asserted that the services were terminated because the work for which he was employed came to an end. It was stated that the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act were not applicable in the instant case. The company, therefore, prayed that the prayers made by the workman be rejected.

4. Both the sides produced certain documents in support of their cases. Oral evidence was also led by both the sides. However, before the recording of evidence was completed the parties arrived at a settlement under which the employers were to pay a sum of Rs. 17,000/- to the workman within thirty days from the date of the settlement and the workman in consideration of the fact that he was being paid the aforesaid amount was to accept that he had no any other claim whatsoever against the company, in respect of the subject matter of the reference before this Tribunal. The parties, therefore, prayed that this Tribunal be pleased to pass an award in terms of the settlement.

5. I find that the settlement on the whole is just and proper The workman was in service of this company from 19-3-1976. His services were terminated on or about 25-1-1977. He was a temporary workman and had put in less than one year's service. It appears from the material that there were frictions between him and his immediate superiors Taking into consideration all these things the settlement appears to be just and fair I, therefore, make the award in terms of the settlement, which is annexed as exhibit A' to this award.

6. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI Presiding Officer

[No. L-36012(1)/77-D. IV(A)]

EXHIBIT A.

Encl:—Exhibit 'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NO. 1, AT BOMBAY

Reference No. CGIT/4/78

BETWEEN

M/s. V. M Salgaocar & Bros. Pvt. Ltd..

AND

Their workman (F. X. Rodrigues)

In the matter of termination of services of Shri F. X. Rodrigues.

May it please Your Honour :

The parties hereto have arrived at a Settlement amongst themselves on the following terms and conditions :

(a) The Employers will pay a sum of Rs 17,000/- (rupees seventeen thousand only) to the Workman Shri F. X. Rodrigue, within 30 (thirty) days from the date of the Settlement;

(b) The workman in consideration of the fact that he is being paid the aforesaid amount, states that he has no other claim whatsoever against the Company/Employer in respect of the subject matter of the reference before this Tribunal;

(c) The dispute is settled in terms of paragraphs (a) and (b) above.

The parties pray that this Honourable Tribunal be pleased to pass an Award on the above terms.

Panaji, Goa.

Dated 18th December, 1982.

Sd/-	Sd/-
Representing the Employer	The Workman.
Sd/-	Sd/-
Advocate for the Employer.	Advocate for the Workman

S.O. 888.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

REFERENCE NO. CGIT-11 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to Food Corporation of India

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the workman :Mr. P. N. Ojha, Resident Secretary, All India Trade Union of Food Corporation Employees & Workers.

For the employer : Mr. J. D. Srivastava, Dy. Manager (Legal).

INDUSTRY : Food Corporation

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 31st day of December, 1982.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. 42012/3/81-FCI/D.IV(A) dated 10th June, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the District Manager (Docks), Food Corporation of India, Bombay, in terminating the services of Shri R. K. Samant, a permanent Assistant Motor Mechanic, with effect from the 9th February, 1977 (Forenoon) is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The workman, R. K. Samant, was appointed as a Khalasi with effect from 15-1-1971 in the Food Corporation of India (hereinafter referred to as the "Corporation") at the District Office, Docks, Bombay. From July 1974 he was deployed to work as an Asstt. Mechanic. His services were terminated with effect from 9-2-1977 on the ground that he absented continuously from duty with effect from 19-3-1976 without any prior permission. According to the Corporation he was directed by letter dated 5-10-1976 to report for duty along with a medical fitness certificate from a Government Doctor in case he was absent on medical ground within seven days from the receipt thereof. He was informed that if he failed to take action as directed he would be liable for disciplinary action as he had violated the provisions of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971. According to the Corporation, the workman received this memo on 15-10-1976. However, he failed to report for duty nor did he send any communication or medical certificate to support his unauthorised absence. The Corporation states in the written statement filed by it that in exercise of the powers contained in Regulation No. 19(1) of the Corporation's Staff Regulations, 1971, the District Manager issued a notice dated 10-11-1976. The notice, however was returned back by the postal authorities with an endorsement "unclaimed returned to sender". The Corporation pleads that as no communication was received from the workman despite the issue of the memo dated 5-10-1976 and the notice dated 10-11-1976,

after completion of 90 days period from the service of the notice, the services of the workman were terminated by the competent authority with effect from 9-2-1977 as per clause 19(1) of the said Staff Regulations

3. It is alleged by the Corporation that Regulation 68 of the Staff Regulations makes provision for appeal against the orders issued by the competent authorities and Regulation 70 specifically stipulates that no appeal provided under these regulations shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of 45 days from the date on which a copy of the office order appealed against is delivered to the applicant. It is alleged that no appeal was received from the the workman against the order of termination or no any other letter was received from the workman intimating to the management the reason for his continuous absence from 19-3-1976 onwards. It was averred in the written statement that it was only after a lapse of three years and four months—the workman wrote to the Regional Labour Commissioner (C), Bombay, for his reinstatement by his letter dated 10-6-1980. A copy of this letter was not marked to the Corporation. It was submitted that as the workman did not prefer to take steps as provided under the Staff Regulations he could not challenge his termination at the belated stage. It was pleaded on behalf of the management that the action taken by it in terminating the services of the workman was as per the provisions of the Staff Regulations after providing the workman a reasonable opportunity and was, therefore, justified and the workman was not entitled to any relief.

4. In the statement of claim the workman admitted that he was absent from duty with effect from 19-3-1976. It was, however, denied that he had not informed the Corporation about his absence. The workman stated that two post-cards were dropped to the District Manager, Docks, by his brother, informing about his sickness. Subsequently, after recovery, the workman resumed duty on 21-4-1976 as he was declared fit by the Doctor. The workman alleged that on the day he reported for duty he was informed by Foreman, Naik at G.I.G. Workshop that the workman had been posted at Docks and will not be allowed to report at G.I.G. Workshop. As per these instructions he reported for duty in Docks and attended duty on 21st and 22nd March, 1976. The workman further stated that he was directed by one of the officers of the Corporation not to sign the muster and report to the concerned Manager for regular attendance/duty in the Corporation as he was absent for one month. He thereafter approached all the higher officers of the Corporation for regular duty order, but everyone of them misguided him by telling that his absence will be regularised. But, nothing was done in this behalf. According to the workman, this caused him mental agony and he fell sick for six months.

5. The workman denied that he had received Corporation's memo dated 5th October, 1976. He denied that he had refused to accept the Corporation's notice dated 10-11-1976. He alleged that the Postal Department might have failed to trace his residence and, therefore, the notice might have been sent back with the endorsement "not claimed". It was admitted that he received the notice of termination dated 9-2-1977. It was, however, stated that the workman had appealed to the competent authority within 45 days as prescribed under Regulation 68 of the Staff Regulations and reminded the authorities about his appeal from time to time. It was alleged that when the workman failed to hear anything from them he had to approach the Regional Labour Commissioner (C) for his reinstatement in service with consequential reliefs. It was finally submitted that the management was wrong in terminating his services under Staff Regulation without affording him an opportunity to defend himself. It was prayed that the workman be granted the reliefs of reinstatement and full back wages

6. At the time of hearing of this reference the workman filed his affidavit on 15-6-1982 by way of oral evidence. He was cross-examined on behalf of the management. The management also filed the affidavit of V. S. Thakur District Manager, Docks. He was cross-examined on behalf of the workman.

7. The workman was first appointed as a Khalasi with effect from 15-1-1971. The order of appointment is produced by the management and it is at exhibit F-1. From July 1974 the workman was deployed to work as an Asstt. Mechanic It is not in dispute that the workman was absenting from duty from 19-3-1976. The management has produced the office copy of the memo dated 5-10-1976 along with the list at exhibit F-4. The text of the memo is as follows :—

> "It has come to the notice of the undersigned that Shri R. K. Samant, Asstt. Mechanic, has been absenting unauthorisedly w.e.f. 19-3-76 without any further intimation/permission to the office, which has been viewed very seriously.
>
> He is, therefore, directed to report for duty alongwith the Medical Fitness Certificate from the Government Doctor/Hospital in case, he is absent on medical ground, within 7 days on receipt hereof, failing which he will be liable for disciplinary action as he has violated the provision made in the Staff Regulation No. 24 (IV) (VI) of the Food Corporation of India Staff Regulation Act, 1971."

This memo was sent by registered A/D. The acknowledgement in token of the delivery of the memo received from the Postal Department is at exhibit F-2. The memo was received on 15-10-1976. It, however, appears that it is not signed by the workman himself but somebody else on his behalf. The case of the workman is that he did not receive this memo. He, however, did not dispute that the correctness of the address mentioned in this memo. We have at exhibt F-3 a notice dated 10-11-1976 sent by registered post to the workman by the management. The packet has returned from the Postal Department with the endorsement "not claimed". The workman denied in his deposition that he did not claim this registered letter addressed to him by the Corporation. After the expiry of 90 days from the date of notice (exhibit F-3) an office order was issued on 9-2-1977 which states that the services of the workman were terminated with effect from 9-2-1977 as per clause 19(1) of the Staff Regulations, 1971. It is not in dispute that the workman received this office order.

8. It is the case of the workman that the two post-cards were sent by his brother to the District Manager of the Corporation informing about his sickness (see para 2 of the statement of claim). However, beyond the bare words of the workman there is no evidence that such letters were sent by the brother of the workman. No any document showing that these letters were sent through post has been produced on record. The brother of the workman is not examined. The claim of the workman, therefore, that his brother had informed the Corporation about his illness cannot be accepted. The workman then wanted to assert that after his recovery from the illness he resumed his duty on 21-4-1976 as he was declared fit by the Doctor. He has produced a copy of the certificate of one Dr. Rajan which is dated 20-4-1976. It states that the workman was suffering from weakness and giddiness from 18-3-1976 and was adviced to take rest, and that he was then fit to resume the duty. It appears that the workman signed the muster-roll on 21-4-1976 and 22-4-1976 That the workman signed the muster-roll on these two dates has been admitted by the District Manager, Thakur in his cross-examination. However, Thakur has stated in his affidavit that the workman did not report for duty along with the fitness certificate. He has also stated that it is the procedure that whenever an official is on prolonged absence particularly for illness he has to report for duty during office hours so that fitness certificate can be properly checked and resumption order be passed by the proper authority. Thakur asserted in his affidavit that the workman neither reported to the District Manager nor to his Dy. Manager and that in fact he did not resume the duty. Thakur stated in his affidavit that the workman might have taken the advantage of just signing the muster-roll without the knowledge of the Duty-in-Charge with the help in his associates The workman has stated in his affidavit that when he reported for duty on 21-4-1976 he had produced the fitness certificate. However, he stated that certificate was returned by the office with verbal comment "go and report to D.M". I am inclined to believe the version of the management that the workman was not allowed to resume the duty on 21-4-1976 without complying with the necessariy formalties. On the material that has come on record I am inclined to hold that the workman absented from duty from 18-3-1976 till the time the office order of the termination of his services was passed on 9-2-1977.

9. It is the case of the workman that he preferred an appeal to the Regional Manager of the Corporation on 4th March, 1977, complaining against the order of termination. The workman has placed on record some letter under which, according to him, he reminded the Regional Manager about the disposal of his appeal. It is seriously disputed on behalf of the management that the workman had preferred an appeal against the order of termination or had sent any reminders in that connection. The workman has tried to place on record the documents purporting to be the certificates of posting under which he sent the appeal to the Regional Manager on 4-3-1977 and issued subsequent reminders. These documents are challenged on behalf of the management as being false and fabricated.

10. The management examined one N.K. Deo, who is the Postal Superintendent of Bombay R.M.S. He was shown the documents purporting to be the certificates of posting produced on behalf of the workman. It appears from the depostion that the dates on these certificates and also the names of the Post Offices through which the letters are alleged to have been sent are not legible. The evidence of the examined for the management, I may say, throws some doubt on the genuineness of these certificates. Any way, the fact whether the workman had preferred an appeal against the order of termination of his services is not very relevant in this proceeding. What we have to see in this proceeding is whether the order of termination is justified.

11. The order of termination is challenged on behalf of the workman on the ground that the services of the workman could not be terminated by recourse to the provisions in the Staff Regulations, especially regulation 19(1) of the Corporation without initiating disciplinary proceedings against the workman. The Corporation has placed on record the copy of the Staff Regulations, 1971. These Regulations do not specifically enumerate what acts or omissions can be called misconduct on the part of a workman. However, remaining absent without permission or leave for a long time can certainly be called a misconduct. It is clear from the Corporation's memo dated 5th October, 1976, which is produced along with the list at exhibit F-4, that the workman was directed to report for duty within seven days on receipt of that memo. He was informed that if he failed to do so he would be liable for disciplinary action as he had violated the provision made in the Staff Regulation no. 24(IV)(VI) of the Staff Regulations, 1971. It is clear from the material on record that the services of the workman were terminated for misconduct of remaining absent from duty without leave or permission. This can be caled misconduct on the post of workman. There is, therefore, much substance in the contention advanced on behalf of the workma that the services should have been terminated after holding a proper departmental inquiry. The termination of the services of the workman appears to be by way of punishment for misconduct.

The termination of the services of the workman could not have been sustained. The management has, however produced evidence in this proceeding to prove the misconduct. The Supreme Court in the case of workman of Firestone Tyre and Rubber Co. v. Management (1973 I LLJ P. 278) has held that if no inquiry is held or the inquiry held is defective, the management can lead evidence before the Tribunal to prove the misconduct. That evidence, oral and documentary shows that the workman was absent from duty for a considerable time and that he did not report for duty in spite of notice dated 5-10-1976 (exhibit F-4) which was sent on proper address and which was received by somebody on his behalf. He managed, according to the management, to surreptitiously sign the muster-roll, for 21st April and 22nd April, but he did not comply with the formality of reporting for duty to a proper officer with the proper certificate as regarding his illness and fitness certificate. The notice dated 10-11-1976 (exhibit F-3) sent to him on proper address was returned back 'as disclaimed'. The contention of the workman that his brother had sent two letters to the management informing about his illness has been rejected by me as it is not supported by any evidence beyond his word. As observed in the case of workman of Firestone Tyre and Rubber Co. (supra), when the evidence is adduced before the Tribunal, the merits of the impugned order of dismissal and discharge is at large before the Tribunal and the letter, on the evidence adduced before it, has to decide for itself whether the misconduct alleged is proved. On the material placed before me, I find that the management has succeeded establishing the misconduct on the part of the workman.

12. The next question is whether the punishment of the termination of the services of the workman is justified. The workman was absent from duty for a long time and in spite of notice sent to him, he did not care to report for duty. He was absent from duty for over ten months without permission or any intimation in writing before his services were terminated on 9-2-1977. I am, therefore, inclined to hold that the termination of the services of the workman is justified and no relief of reinstatement should be granted in his favour.

13. The order of termination, however, will not be effective from 9-2-1977 as it was not passed after the inquiry. The management has led evidence to prove the misconduct. On this evidence, I am holding that the misconduct is proved and the termination of the services of the workman is justified. The termination, therefore, will be effective from the date on which, the award in this reference would become operative.

14. The question is whether the workman should be granted back wages for the period 9-2-1977 i.e. the date on which the management purported to terminate his services without an inquiry to the date the award in this reference becomes operative. There are some peculiar factors to be considered. The workman was not attending the duty for a long time prior to 9-2-1977. Ordinarily, the order of termination of the services prevents the workman from attending the duty. This is, however, a case where the workman was absent for a long time and, therefore, his services came to be terminated. It is not therefore that he was prevented from attending the duty by the order of termination dated 9-2-1977. Admittedly, the workman received the notice of termination. According to the management, he, however, did not prefer an appeal against that order under the provisions in Regulation 68 of the Staff Regulations, 1971. The workman has produced on record a copy of a document purporting to be an appeal filed before the competent authority. It was not sent by registered post nor handed over personally and signature obtained, in token of having filed it in the office concerned. The workman wanted to rely upon certain document purporting to be certificate of posting under which it was sent. I have, however, found that those documents cannot be relied upon. It was after a lapse of three years and four months that the workman wrote to the Regional Labour Commissioner(C), Bombay, for his reinstatement vide his letter dated 10-7-1980. The question, therefore, is whether the workman should be paid back wages from 9-2-1977 to the date on which the award would become operative. I have held that the misconduct on the part of the workman is proved. There are also latches on his part. Taking into consideration all these circumstances, I think it would be proper and fair to award only one-fourth of the back wages from 9-2-1977 to the date on which the award in this reference would become operative.

15. In the result, I find that even though the management did not terminate the services of the workman after proper inquiry, the management has by the evidence adduced before me proved the misconduct on the part of the workman. The termination of his services, therefore will be effective from the date on which this award would become operative. The workman deserves the punishment of termination of services for the misconduct proved to have been committed by him. The workman will be entitled to one-fourth of the back wages from 9-2-1977 to the date on which the award in this reference becomes operative.

16. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer

[No. I-42012/3/81/FCI[D.IV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

New Delhi, the 27th January, 1983

S.O. 889.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Poidih Colliery, Sitarampur Sub-Area of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen which was received by the Central Government on the 19-1-1983

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 82/82

PARTIES :

Employers in relation to the management of Poidih Colliery, Sitarampur Sub-Area of Eastern Coalfields Ltd., Dist. Burdwan.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Chakravarty, Genl. Secy., C.M.E.U

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal

Dated, the 12th January, 1983

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 referred the dispute to the Central Governmtnt Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Calcutta, Subsequently by Order No. S-11025(4)/80-D.IV(B) dated 14th/17th November, 1980 transferred the dispute to this Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Poidih Colliery of Sitarampur Sub-Area, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Sitarampur, Dist. Burdwan in taking clerical duties from S/Shri Chanchal Kumar Neogi, Somen Ghosh, Nital Banerjee, R.N. Das, S. P. Roy, Satyesh Majhi and Tracer's duties from Shri B. N. Bhattacharjee from various dates in 1975 and 1976 and not regularisihg them in the proper grades is justified ? If not, to what relief are the concerned workment entitled and from what date ""

2. On 11-1-1983 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award

Enc : Settlement

J. N SINGH, Presiding Officer

[No. L-19013(58)/77-D IV(B)]

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NO. 3, DHANBAD

Reference No 82 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Poldih Colliery of Sitarampur Sub-Area of E.C. Ltd

AND

Their Workmen.

Joint petition of compromise :

Both the parties herein concerned beg to submit as under :

1. That the above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal and the matter has not yet been heard.

2. That the parties, in the meantime have discussed the above matter mutually and have settled the matter in dispute on the terms stated herein below

TERMS OF SETTLEMENT

(i) That S/Shri Chanchal Kumar Neogi, Somen Ghosh, Nital Banerjee, R. N. Das, S. P. Roy, and Satyesh Majhi the concerned workmen who are already posted in Clerical Grade II, will be given one special increment on their existing basic pay as on 1-1-83.

(ii) That for the purposes of determining seniority alone in the Grade it will be deemed as if all of them as referred to in the foregoing sub-para, were in the existing Grade with effect from October, 1979 subject to condition that the aforesaid workmen shall have no financial claim whatsoever in the matter of treating their seniority from the notional date of October, 1979.

(iii) That Shri B. N. Bhattacharjee, the remaining concerned workman will be placed in the appropriate Grade of Tracer with one increment on the initial basic pay of the Grade with effect from 1-1-1983.

(iv) That by this settlement, the instant matter arising out of the present reference is fully and finally resolved and the workmen shall have no financial claim or back wages whatsoever other than those specifically mentioned in subparas (i) and (iii) above.

(v) That the parties shall bear their own costs of the present proceedings.

(vi) That both the parties agree that the terms of this settlement are fair and proper, and that this settlement shall become effective on the date this is accepted by the Hon'ble Tribunal

3. That both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this settlement and pass an award in terms thereof.

And for this act of kindness, both the parties as in duty bound, shall ever pray.

Dated this the 11th day of January, 1983.
For and on behalf of the workman.

Sd/- (Illegible)
Vice-President, CMEU

For and on behalf of the employers.

P. N. Goswami, Senior Personnel Officer, Sitarampur (R) Colliery.

New Delhi the 28th January 1983

S.O 890—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramnagore Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Ltd, and their workmen which was received by the Central Government on the 25th January 1983

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

Reference No 6 of 1978

PARTIES

Employers in relation to the management of Ramnagore Colliery of IISCO Limited P O Kulti Burdwan

AND

Their workmen

APPEARANCES

On behalf of Employers—Mr Nilay Ghosh Advocate

On behalf of Workmen—Mr S Roy Advocate

STATE West Bengal INDUSTRY Coal

AWARD

By Order No L 19012(40)/76 D III(B)/D IV(B) dated 1st September 1977 the dispute as to "Whether the action of the management of Ramnagore Colliery of IISCO Limited Post Office Kulti District Burdwan in denying regularisation of service to Sarva Shri Md Rafik Md Hanif Md Usuf Baran Das Rajkumar Shaw, Durga Mahato Stone Cutters and refusal to allow them to resume their work with effect from 19 4-76 by the management is justified" existing between the management of Ramnagore Colliery of IISCO Limited and their workmen was referred to this Tribunal for adjudication

2 When the matter was first taken up for hearing the parties submitted that serious talk of compromise is going on between the parties and that there is every possibility of compromise of the dispute and as such time was given to arrive at a compromise The matter was ultimately fixed for final hearing or filing of compromise petition on 17 1 1983

3 On 17 1 1983 when the case was called up the parties filed the compromise petition with a prayer to pass an award in terms of the said compromise which runs as follows

A The six workmen mentioned in the order of reference will be appointed by the Company as fresh appointees from the date of joining their duty after the compromise petition is filed before the Learned Tribunal and in terms stated below

B They will have no claim for any back service or benefit of back wages prior to the date of joining referred above

C They (all the six workmen) will be placed in the Category I in the scale of pay of (National Coal Wage Agreement II) dated 11th August 1979 Rs 15-0 26 18 12 as prescribed for Daily Rated workmen and will be placed on joining at the initial basic of Rs 15/ per day and shall be entitled to other allowances as are applicable to such categories of employees as prescribed in the NCWA of 1979 as referred above

D Their initial place of posting shall be decided by the Management

E (i) The age of superannuation shall be at 58 years

(ii) They will produce certificate of Birth Registration before the date of joining In absence of Birth Register certificate the opinion of Company's Doctor shall be obtained about their age which shall be final

F The appointment of any of the six workmen shall be subject to their medical fitness by the Colliery Medical Officer which shall be final

G They or any of them shall join within 1 (one) month from the date of issuance of their appointment letter The Union shall supply within 15 days the addresses of the six individual workmen from the date of filing of the compromise petition In default of joining at the place of posting within 1 (one) month from the date of issuance of the appointment letter, the offer shall stand cancelled and they will have no claim whatsoever either of employment and or any other benefit "

I find the terms are fair and reasonable and they are for the benefit of the workmen concerned As such I accept the terms of compromise as mentioned above

4 As prayed for by the parties and in view of the circumstances stated above I pass an "Award" in terms of the compromise as embodied in paragraph 3 above

Dated Calcutta
the 18th January 1983

M P SINGH Presiding Officer

[No L 19012(40)/76 D IV(B)]

S O 891.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ghorawari Colliery of Messrs Western Coalfields Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 20 1 83

BEFORE JUSTICE SHRI S R VYAS (RETD) PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR CUORT JABALPUR (M P)

Case No CGIT,LC(R)(36) 1982

PARTIES

Employers in relation to the management of Ghorawari Colliery of M/s Western Coalfields Limited Kanhan Area District Chhindwara (M P) and their workman Shri John Daya Boring Mazdoor, C/o Shri Y Daya Mission Compound P O Junnardeo District Chhindwara (MP)

APPEARANCES

For workman—none

For Management—Shri P S Nair, Advocate

INDUSTRY Coal DISTRICT Chhindwara (M P)

AWARD

Dated January 11, 1983

Vide Government of India Ministry of Labour Notification No L-22012(4)/82-D IV(B) Dated 15th May, 1982 the following dispute has been referred to this Tribunal for adjudication under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Western Coalfields Limited Kahhan Area in treating the removal of Shri John Daya Boring Mazdoor from the rolls as automatic is justified If not to what relief the workman is entitled ?"

1 The claim of the workman is that since the year 1973 he was employed as a Boring Mazdoor in the Kanhan Area of Western Coalfields Limited Co that from time to time he was transferred to different collieries in Datla West, Rakhikol Damua Ghorawari etc and lastly from Damua to Ghorawari that when he reported for duty at the Ghorawari Colliery he was vide Ghorawari Colliery letter of 31 5 1976 sent back to Damua that when he reported for duty at Damua he was not provided with any work and was every day asked to come the next day without any work being provided to him and that in this manner he is without any employment at any place

The workman thus contends that he is, since 1976, without any job and employment and that he should be provided with job employment and wages etc

2 The management's case is that the workman was employed on temporary basis, that on 14-5-75 he was sent along with some other workers to Damua where after the work was completed he was on 22-5-76 sent to Ghorawari Colliery along with 17 other workmen but he did not join, that it was on 23-11-79 that he submitted a representation that he could not join because of being sick, that for the period of absence from 22-5 76 to 23-11-79 no application for leave was made, that he himself abandoned the job, that a workman who remains absent without sanction of leave has no right to the job and not only loses the same but also is guilty of misconduct and that a regular domestic enquiry was not possible as his residential address was not available

3 No rejoinder was filed by the workman

4 In the rejoinder by the management it is stated that the workman was not sent back to Damua as alleged, that since the workman did not report for duty at Ghorawari Colliery there could be no question of sending him back to Damua, that in the letter dated 31-5 76 the name of the workman was not included, that he was not asked to come on the next day as alleged and that the workman absented himself without any justification

5 On the aforesaid statements of the parties the following issues were framed

ISSUES

(3 9-82)

(1) Whether the management of the WCL was justified in treating the workman Shri John Daya's name as automatically removed from the rolls on the grounds taken in the statement of the claim ?

(2) To what relief are the parties entitled to ?

The workman sent his statement of claim by post and thereafter did not appear on any one of dates the hearing No one also appeared for him The management examined two witnesses and produced one document in answer to questions put by the Tribunal to one of its witnesses The workman also did not adduce any evidence I have examined ed the statements of the parties and the evidence given by the management My findings on the aforesaid issues are as under :—

Issue No 1 —There is no evidence that the management of the WCL, Kanhan Area had treated the removal of the workman Shri John Daya from the rolls as automatic On the contrary the management's claim is that the workman has voluntarily abandoned the job In case the management has treated or is treating the name of the workman as automatically removed then the same is not justified

Issues No 2 —The workman is entitled to the relief as per order passed below

6 Reasons for the findings —The workman in his statement of claim has alleged that he was employed in the Kanhan Area of WCL since 1973 as a Boring Mazdoor This fact is not denied by the management in their statement of claim It is further admitted by the management in their statement of claim that that on 14 5-75 the workman along with other workers was sent to Damua Colliery and that on 22 5-76 to Ghorawari Colliery It is thus clearly admitted by the management that from 1973 to 22-5-76 the workman was their employee It is neither pleaded nor proved that between 1973 and 22 5-76 the workman was employed for broken periods only Had it been that he was given casual or temporary employments then there could be no question of sending him to Damua on 14 5 76 and then sending him back to Ghorawari Colliery on 22-5-76 is admitted in para 3 of the management's statement The management has for reasons not explained used the words "Sent" instead of "Transfer' The only reason could be that the management did not wish to admit in every clear terms that the workman was their regular employee

7 MW 1, U P Verma the Labour Welfare Officer of the Ghorawari Colliery admits in para 1 of his statement that the workman was, on 22-5-76, transferred from Damua to Ghorawari Colliery but he did not join This admission further corroborates the conclusion in the above paragraph that the workman was a regular employee and not a casual or temporary employee as alleged Casual and/or temporary employees are not transferred they may however be given temporary and/or casual employment as and when work justified

8 MW 1 U P Verma has further stated that in the Ghorawari Colliery as the workman did not report for duty neither his name was entered in the "Form B" register nor was he retransferred to Damua Colliery nor was there any question of the termination of his services The witness further admitted in para 8 of his statement that when the workman is transferred from one Colliery to another his personal file, Last Pay Certificate Leave Account and other relevant papers are sent and that those papers must have been sent by the Damua Colliery to his colliery for record It is surprising that these papers have been kept back and not produced in this case Had they been produced it could be shown that the workman was a **regular** employee of Damua Colliery and not a casual or temporary employee as alleged by the management

9 The next witness is MW 2, Y N Mathur, Personnel Officer of the Datla Group He says that the workman was employed as a Boring Mazdoor in Damua Colliery in 1976 and was also employed in some other collieries before being employed in Damua Colliery He also says that before he was transferred from Domua to Ghorawar he had not completed 240 days of working, that only in cases of permanent workers the Last Pay Certificate is issued on transfer and that when in May 1976 the workman was transferred from Damua to Khorawari he did not report for duty either at Damua or at Ghorawari

10 By the aforesaid evidence the management wanted to prove that the employment of the workman at Damua was of a casual nature He, however, has not given the details as regards the date of employment of the workman in Damua in 1976 even though he admitted that he was employed in other collieries also It has already been held in para 6 above that the workman was employed from the year 1973 in different collieries of the WCL Consequently his statement that the employment of the workman was of a casual nature cannot be accepted as a true statement

11 MW 1 V P Verma says that the workman was transferred to Ghorawari from Damua and did not report for duty MW 2 Y N Mathur admits that the workman was employed in Damua Colliery and was transferred to Ghorawari Colliery It is then clear that the workman was an employee of the Damua Colliery in 1976 Between 1973 and 1976 his service particulars have not been produced It cannot be believed that between 1973 and 1976 the workman did not any one in calendar year complete 240 working days It was the duty of the management to produce the relevant service records of the workman who admittedly served for more than 3 years Why such material evidence has been kept back has not been explained by the management In these circumstances the only conclusion that can, and must be drawn is that a workman was their regualr employee and it was for this reason only that he was transferred frequently from one colliery to another

12 From the evidence discussed above it is clear that at least upto 22 5-76 the workman was their employee and was transferred from Damua to Ghorawari Colliery The management contends that after workman was transferred on 22-5 76 to Ghorawari Colliery he reported for duty only on 23 11 79 He was however not taken back on duty and was also refused employment because he had neither applied for leave nor he explained his absence It is further urged that [illegible] of the workman was tantamount to [illegible] abandonment of the job The management

however does not say in clear terms that by such absence the workman lost his lien on the post and suffered automatic to removal of his name from the rolls. Even if it be so such an understanding or opinion on the part of the management cannot be accepted.

13. It is an admitted fact that on 23-11-79 the workman reported for duty. The management could and ought to have called upon him to explain his absence. A chargesheet could have been served if the cause of absence put forward by the workman was not found satisfactory. This however was not done. The manner in which the management, inspite of the workmon reporting for duty, turned him back treating the workman as having abandoned the job must be treated as unjustified and against law.

14. According to the provision of the I.D. Act. If termination of service of a workman is brought about for any reason whatsoever, it would be retrenchment except if the case falls within any of the excepted categories, i.e. (1) termination by way of punishment inflicted pursuant to disciplinary action; (2) voluntary retirement of the workman; (3) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; (4) or termination of the service on the ground of continued ill-health. Once the case not fall in any of the excepted categories the termination of service even if it be according to automatic discharge from aservice under agreement would nonetheless be retrenchment within the meaning of expression in S. 2(oo). It must as a corollary follow that if the name of the workman is struck off the roll that itself would continue retrenchment.

15. The aforesaid principle of law has been laid down by Hon'ble the Supreme Court in L. Robert D'Souza Vs. The Executive Engineer, Southern Railway (AIR 1982 S.C. p 854). This decision concludes the issue between the parties to this case. The management has not complied with the provisions of Sec. 25F of the I.D. Act. Consequently the workman must be treated as continuing in the management's employment at least from 23-11-79. The refusal to give employment from 23-11-79 was not at all either justified or legal.

16. According for the reasons given above the workman is treated as continuing in the employment of W.C.L. from 23-11-79. He shall be paid his wages and other allowances from that date (23-11-79). The management shall give employment to the workman and assign him duties on the last post held by him in the colliery in which he had been on duty.

An award is accordingly passed.

Both parties shall bear their own costs as incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L 22012(4)|82-D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1983

का॰आ॰ 892.- उत्प्रवास अधिनियम 1922 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री के॰ उपगुप्तन, अनुभाग अधिकारी, श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) को 10-1-1983 के अपराह्न से उत्प्रवासी संरक्षी त्रिवेन्द्रम के रूप मे नियुक्त करती है।

[डी॰जी॰एल डब्ल्यू॰/11017/1/81 ईएमआईजी II]

शशि भूषण, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O 892.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1922 (7 of 1922), the Central Government hereby appoints Shri K. Upagupthan Section Officer, Ministry of Labour and Rehabilitation (Deptt. of Labour) to be the Protector of Emigrants, Trivandrum with effect from the after-noon of 10 1.1983

[No. DGLW-11017(1)/81-EMIG]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy

New Delhi, the 28th January, 1983

S.O. 893.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/1 of 1982

BETWEEN

Employers in relation to the Management of Union Bank of India

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri F. D. Damania, Advocate.
Miss Beryl Pereira, Personnel Officer.

For the Workmen—Shri M. S. Udeshi, Advocate.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra

Bombay, the 17th December, 1982

AWARD

On receipt of the failure of conciliation report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 10(1)(d) read with Section 12(5) of the said Act referred the following dispute for adjudication :—

"Whether the action of the management of Union Bank of India, Gandhi Bag, Nagpur in not sanctioning leave and deducting wages for one day on 20th January, 1981 in respect of S/Shri M. K. Selute, P. V. Tembhurnikar and R. B. Sondhia is justified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?"

2. The incident in question which gave rise to the present reference is alleged to have taken place on 20th January, 1981 when all the six members of the sub-staff serving in Gandhi Bag Branch of the Union Bank of India Nagpur are alleged to have remained absent without assigning any cogent reason as a result of which the Bank deducted proportionate wages for the said day from the salary of the respective employees on 23rd January, 1981 but three of the employees having produced medical certificate in support of their plea of illness, the cases of those three employees namely S/Shri G. R. Anasane, R. S. Kumre and M. S. Gondane were reconsidered and their leave was sanctioned and the money was ordered to be refunded. Such however was not the case with the three remaining employees namely S/Shri Selute, Tembhurnikar and R. B. Sondhia and hence the reference.

3. By their claim statement Ex. 3/W the contention of the Union who is espousing the cause of the three workmen is that the action of the Bank in deducting the wages was arbitrary and in violation of the principles of the natural justice and fair play, since the same was done without any intimation and without assigning any reasons. It is further alleged that the said action is violative of Chapter 19 of the Bipartite Settlement of the year 1966 and further infringes the fundamental rights of the employees. It is further alleged that these employees were entitled to various types of leave including casual leave which was to their credit and therefore the order of the Bank contravenes the Bipartite Settlement.

4. The Bank has filed written statement at Ex. 2/M whereby their contention is that all the members of sub-staff remained deliberately absent on 20-1-1981 in pursuance of their concerted action without any previous

notice or prior permission and that this action amounted to illegal strike. It is alleged that when these three employees were called upon to justify the cause of their absence, they could not do so and that the reasons advanced were far from satisfactory and therefore the Bank insisted that they have got a right to carry out the deduction.

5. On the strength of these pleadings the following issues arises for determination and my findings thereon are:—

ISSUES	FINDINGS
(i) Whether the Union proves that rejection of the leave application by the Bank was mala fide and therefore illegal for the reasons stated?	No
(ii) Does the Bank prove that absence was a concerted action on the part of 3 members of sub-staff amounting to a strike?	Yes
(iii) Are these employees entitled to get wages as claimed?	No
(iv) What relief?	As per order.

REASONS

6. The facts involved are not very much in dispute. As already stated the incident occured on 20th January, 1981 on which day the Bank re-opened, 18th and 19th January, 1981 being holidays as Sunday and Bank holiday. It is the contention of the Bank that previous to this the Union as well as all the members of the sub-staff had approached the authorities for appointing a substitute in place of one Shri Avasthi who used to remain frequently absent but the Bank decided not to appoint any substitute from January, 1981 and turned down the representation in this regard by the Secretary of the Union as well as the members of sub staff. It is alleged that on account of the action of the management in not heeding to the request of the Union and members of sub-staff, as a sort of concerted action, on 20th January, 1981 all these members remained absent with the result that on the relevant day the Bank had to carry on without a single member of sub-staff.

7. It is also pointed out that although in all six employees were involved, because of the production of medical certificate by the remaining employees viz., Anasane, Kumre and Gondane, the Bank had to reconsider their case despite the fact that the Regional Manager was all along being of the opinion that they are also party to the concerted action and their wages deducted were subsequently released.

8. Everything therefore would depend upon whether there are reasons to believe or whether there is material to hold that it was a concerted action on the part of the three employees, whether the deduction of the wages was carried out legally and in pursuance of the provisions appearing in the bipartite settlement and lastly whether these employees in case are found to be entitled for wages, can still claim the wages. The evidence in this regard adduced by the Union consists of statements of three employees viz., S/Shri R. B. Sondhia, M. K. Selute and P. V. Tembhurnikar. Exhibits 4/W, 5/W and 7/W, and there is the statement of the Secretary of the Union Shri L. P. Nandanwar, Ex. 6/W, which evidence is countered by the evidence of two Bank witnesses namely S/Shri K. N. Mehta and M. M. Amalsadvala Exhibits 8/M and 32/M, respectively the Branch Manager and Regional Manager of the places. In the evidence of Shri Mehta it is transpired, though the fact is denied by Shri Nandanwar, that previous to the date of incident on or about 14th January, 1981 the General Secretary of the Union as well as the members of the sub-staff had approached the Branch Manager and they were insisting upon the appointment of a substitute. The fact that before January, 1981 the Bank did make appointment of a substitute in place of the absentee peon stands admitted and having regard to the fact that the Branch Manager had absolutely no reason to say any thing falsely in this regard, I am convinced that these employees as well as their representative who happened to be a member of staff at the relevant time, must have moved in the matter for securing the appointment of a substitute. When there was no seventh member of the sub-staff and when Avasthi was on long leave due to sickness or for other reasons, it was but natural for the remaining employees to secure appointment of a peon substitute thereby reducing the load of work. Therefore though there is denial in this regard, I cannot believe the statement of either of Shri Nandanwar or the statements of others and I hold that there must have been such an attempt on the part of these employees prior to the date in question.

9. When even according to the Union or these employees the absence of one member of sub-staff was causing some inconvenience, we can imagine the inconvenience caused to the Bank by all these members of sub-staff remaining absent and away from the Branch on 20th January, 1981. If therefore the Branch Manager, being conscious of the previous history concluded that it was a concerted action, I do not think there was anything wrong in the said assumption. When examined before me, Shri Sondhia says that because of his daughter's illness he could not attend the Bank on that day. The explanation of Shri Selute is that he had to accompany his son to some place, while Shri Tembhurnikar refers to the Civil Suit. Now Shri Selute had submitted the application on the very day asking for two days leave on the ground of household work still he resumed duty on the next day on 21st January, 1981 on that day Shri Selute had cancelled the leave for one day. In the case of remaining three members of sub-staff, as seen from Exhibits 18/M, 21/M and 25/M they had alleged ill-health and therefore had asked for leave, in support of which all the three had produced medical certificates. Shri Gondane was on leave from 15th January, 1981 and had produced medical certificate in this connection. Because of these medical certificates the Bank as already stated re-considered their cases and therefore these three employees are not in the picture. Even then it does not mean that the remaining three members of sub-staff must not have acted concertedly. Shri Tembhurnikar says that he had to attend the Civil Court but it cannot be said that this fact was made known to him on 20-1-1981 but must have learnt about it long before and therefore the contention that all of a sudden on 20-1-1981 he remained absent without intimation cannot be believed. In the case of Shri Selute he had to accompany his son but for what purpose is not at all stated and in the case of Shri Sondhia due to his daughter's illness he had to attend the hospital, but there is nothing to substantiate this allegation.

10. There is one another circumstance namely that on 20-2-1981 according to the Regional Manager Ex. 32/M he had a talk with the Secretary of the Union when it was suggested that if these three employees also could give in writing that it was not a concerted action and the cause stated was genuine, the Bank was prepared to reconsider the decision and release their wages also but this suggestion had no desired result. Shri Amalsadvala when examined before the Tribunal has stated to this effect and although in the cross-examination it is challenged I see no reason to disbelieve the responsible Officer like the Regional Manager. Had it not been a concerted action and had there existed really a genuine ground, absolutely there should not have been any difficulty for the three remaining employees to reduce the said fact into writing. They having not done so leads to the only inference that the cause put forth must not be true and they remained absent because of the reluctance of the Bank to appoint a substitute in place of a absentee member of sub-staff.

11. The pay day was 23-1-1981 and the record goes to prove that the deductions in the case of these employees were made on the said day The next question, therefore, for determination is whether the Bank could have done so and what are the rights conferred on the Bank by the Bipartite Settlement. To justify the deduction as a sort of unilateral action without asking the explanation of these employees, the authorities of the Bank are relying upon the circular dated 14-6-1979 Ex 56/M and also another circular dated 23-9-1977 Ex. 55/M impressing upon the members of the staff that wages would be proportionately cut for the day for which they would absent from duty. In the first mentioned circular it was further stated that failure to perform normal work in normal manner will render the members of staff for wage cut and also for disciplinary action. Now it is urged that when the Regional Manager or the Branch Manager acted in pursuance of the circular which was made known to the members of staff, the action of deducting wages even before any opportunity was given to put forward their say, would be legal and justfied. However, what we find is that the provisions regarding casual leave have been mentioned in the bipartite settlement of the year 1966 appearing in paragraphs

13.22 to 13.28. Paragraph 13.22 lays down the number of days of causal leave while paragraph 13.23 says that ordinarily previous sanction of the authority before taking such leave should be obtained. at the same time makes provision that if it was not possible the said authority shall be informed as soon as practicable in writing or if writing is not possible, orally or through any person. All these three employees in question were residents of Nagpur and really speaking had there been any genuine cause, they could have contacted the Branch Manager. An attempt was made to suggest that Shri Tembhurnikar on 17-1-1981 had approached the Accountant with the request for leave on 20-1-1981 but he having assured that there was no cause for obtaining leave provided he would attend the office at 12 noon or so no attempt was made to put forward the application in writing. It was argued on behalf of the employees that Shri Nagdeo who was the concerned Accountant could have been examined by the Bank to negative this contention and since he was not examined, it would fortify the contention of the workman concerned. We have already seen that Shri Tembhurnikar, according to him was to attend Court and it was not possible for him to pre-judge the time required and could not have presumed that case would be over before 12 noon. It was really for the workman to prove that there was communication from the employees to the Accountant and Shri Nagdeo who is serving near Bombay could have been easily called and examined before the Tribunal. This uncorroborated explanation of the member of the sub-staff is also not plausible to be believed.

12. Paragraph 13.27 deals with the action to be taken by the Bank and it says that any absence from duty without satisfying the requisite conditions under which leave may be taken or obtaining such leave on false grounds would justify any bank, after giving the employee an opportunity to explain, in not treating the employee as on casual leave but as being absent without leave on loss of pay and allowance Laying emphasis on "after giving an opportunity" it was urged on behalf of the Union that the deduction having been made without giving opportunity to the concerned employees is violative of the terms of bipartite settlement and therefore illegal. A reference is already made to the circular which the employer bank considers as authority to carry out deduction or take suitable action, but when there is a bipartite settlement to which the Bank is also a party, no circular unilaterally issued by the Bank can override the provisions of such settlement and therefore we need not take into account the circulars above referred to.

13. It seems that the Bank was thinking at one stage taking disciplinary action also for the alleged misconduct but subsequently issued Memos. Ex. 29/M, 30/M and 31/M and the Bank dropped the said idea and treated the case as closed. Relying on this action it was urged that the Bank having waived the right of moving in the matter now they cannot go forward with the attempt to justify the deduction of wages. In this connection one important fact has to be borne in mind namely that on account of the unauthorised absence from duty, two actions were possible namely deduction of wages on the principle of no work no pay and also treating it as a misconduct and to proceed accordingly. By the three memos the Bank must have waived the right to take disciplinary action but thereby it does not mean that when the employees by their concerted action remained absent, they are still eligible for wages. Issue of three Memos. similarly the refund of wages of the three remaining employees in whose case the Bank was satisfied about the genuineness of the cause, would not hamper the case of the Bank provided they can legally do so.

14 Deduction of wages is also contemplated by Section 9 of the Payment of Wages Act, 1936. Section 7(2)(B) of the said Act lays down that deduction from wages may be made on account of absence of employees from the place where by the terms of employment he is required to work. The right of the Bank therefore is a statutory right as well as a right given by the bipartite settlement. at the same time the bipartite settlement further enjoins upon the Bank to take such action in a particular manner

15 My attention was drawn to the case reported in 1980 (II) LLJ. page 344 a decision of the Hon'ble Bombay High Court in M/s Apar (Pvt.) Limited Vs. S. R. Samant and other where on the ground that the workman had resorted to go-slow, the management had effected deduction in wages and the question arose whether the said act on the part of the management was legal or otherwise and the Lordships of Bombay High Court ultimately held that in the absence of specific terms in the settlement or statutory provision, an employer has no right to reduce the wages or employments on the allegation that the workers had resorted to go-slow tactics. It was noted that no norms had been fixed either workmanwise or departmentwise to spell out the individual liability or responsibility to do particular quantity of work. Similarly it was found that neither any settlement nor any provisions of law spoke of the right of the management to carry out the deduction on the ground of go-slow and therefore ultimately the order of deduction was struck down. In the instant case though there was no breach of the provisions of the Act and we have already seen under the Bipartite Settlement and under Section 7 and 9 of the Payment of Wages Act deductions have been contemplated on account of absence. The Bipartite settlement however lays down the procedure to be followed by the Bank, which in the instant case, it must be stated, was not at all followed. the deduction was made earlier and the Memos. were served subsequently.

16. That there was infringement of paragraph 13.27 of the Bipartite Settlement can never be disputed. The question however does not end here and it is further to be seen whether these employees who concertedly stayed outside the Bank causing to their knowledge great inconvenience, laying fingers on paragraph 13.27 of the Bipartite Settlement can still come to the Tribunal saying that it has become their service condition. In this connection the principle is those who come to the Tribunal must come with clean hands. If there was no genuine cause for the absence and the absence was unwarranted and these employees deliberately remained absent from the place of work such a conclusion is not possible. Therefore, in view of my finding that the Bank has established before the Tribunal that the absence was a concerted action on the part of the three members of substaff, there cannot be any order of refund of wages. Even in the case of serious action like dismissal without enquiry, if the management is in a position to substantiate the allegation of misconduct resulting in such final order law unables the management to establish the same and to substantiate their action. In the instant case there is proof that there was failure to comply with the provisions of paragraph 13.27, in the sense there was no prior opportunity given to the employees to explain, but when occasion arose for establishing the various facts, the evidence on record as indicated proves that the action was a concerted action. In these circumstances in my view the Tribunal cannot go to the rescue of those employees who were guilty of a particular action, I may call it a wrong action, and therefore though there is a breach of paragraph 13.27 of the Bipartite Settlement and though the action could have been said to be not in accordance with the Bipartite Settlement, having regard to the totality of the situation and having regard to the conduct of the employees I hold that no relief is permissible.

Award accordingly. No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-12011/41/81-D. II(A)]

S.O. 894.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Mercantile Bank Limited, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No CGIT-2/15 of 1981

PARTIES :

Employer in relation to the Management of Mercantile Bank Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri F. D. Damania, Advocate

For the workmen—Shri Madan Padnis, Advocate.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra.

Bombay, the 1st January, 1983

AWARD

By their order No. L-12012/303/80-D.II.A dated 1-8-1981 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Mercantile Bank Limited, Bombay in denying promotion to S/Shri J. R. Pereira, Markoni D'Costa, Dadi E. Adjania, S. Y. Vedak, V. A. Mankame and T. H. P. A. Fernandes, the Head Clerks to the post of Special Assistants, is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. By a notice dated 3-1-1980, 19 members of clerical cadre serving with the opponent Bank were posted as Special Assistants some of whom were serving as Chief Clerks, some as Head Clerks and some as Section Heads and it is the grievance of the workmen that even the members of the clerical staff were considered for promotion. Now as Special Assistants, the concerned employees draw Rs. 283.00 as Special Allowance, a part of which would attract pension, provident fund and some such other benefits The grievance of the Union who is espousing the cause of some of the workmen is that while considering the names of suitable candidates, preference was given to some of the promotees only because they happened to be members of a particular union who persuaded the authorities to select these promotees, thereby overlooking the legitimate claims of other workmen, who owe allegiance to the Mercantile Bank Ltd. Employees' Congress that is the Union who is espousing the present cause. It is complained that the list of appointees never displayed any pattern, policy or principle. There was no pattern of seniority or merit and by making selections of the members belonging to the Federation, namely the Mercantile Bank Employees' Federation, the Bank practised partiality resulting in victimisation and further the Bank also acted mala fide. It is alleged that these selections were made only because the selected candidates belonged to the Mercantile Bank Employees' Federation and not to the Congress. The Union then cited the pattern adopted by various Banks for the purpose of promotion as Special Assistant and it is alleged that by not following a specific pattern, the Bank has practised unfair labour practice.

3. By their written statement x. 5/M the Bank has contended that since the Union which is espousing the cause of these six workmen has no significant following in the Bank, while substantial majority of the workmen being with the Federation, the Union cannot espouse the cause nor it can be turned into an industrial dispute. It is alleged that in pursuance of the understanding or agreement arrived at with the Federation so far as the Bombay Region is concerned where 19 posts of Special Assistants were treated, not only the Chief Clerks, Head Clerks but also the Section Heads or Sections-in-Charge were eligible for the said purpose and therefore if on the basis of the seniority-cum-merit, the management made certain selections from those class of employees including the Section Heads, it being a managerial function, the Union cannot and should not have any grievance against such selection. It is alleged that while making promotions seniority of the employees of a particular department, Section or Sub-Branch to which the employee was attached at the time of promotion, was taken into consideration as per the Bank's normal practice and after assessing the merits. It is alleged that since the Chief Clerks, Head Clerks and Section heads were already drawing special allowance applicable to them, no interview or any test was carried out and the test was assessment of individual merits, and accordingly the list was prefared and suitable postings were made under the relevant order. It is further alleged that so far as Shri T. H. P. A. Fernandes whose name appears at S. No 6 on whose behalf no demand having been made by the Union his reference is infractuous and in his case at least the same must fail. The Bank then further pointed out that several employees from the list of selectees at the relevant time being the members not of the Federation but of the Congress, the grievance that to oblige a particular union at the cost of the other union has no substance and therefore must be discarded. It is alleged that at the relevant time while selecting 19 promotees, the individual merits of in all 49 employees were considered and of these who were found suitable after assessment of their work and merits and further considering the seniority, selections were made which according to the Bank now cannot be questioned on the ground of mala fides by the Union The charge of mala fides is also denied, similarly the grievances of victimisation and lastly it is contended that no addition to the work force can be compelled by the Tribunal and that the Union can never demand the cancellation of the list validly selected by the Bank.

4. There is rejoinder at Ex. 6/W by the Congress, where grievances are reiterated but though it was alleged that the selections were not only from the cadre of Head Clerks, Chief Clerks or Section Heads but also from the cadre of clerks, at the time of argument no such point was raised by Shri Padnis the learned Advocate for the Congress and therefore that point need not detain us for much time. It is further contended that all these promotees after their promotions as Special Assistants are doing the same type of work which they were performing prior to their promotions and there occurred no change whatsoever in the nature of the duties discharged by them. Other points are already taken up in the statement of claim and therefore need not be referred to.

5. Similarly there is rejoinder by the Bank at Ex 7/M where also barring the fact that it was managerial function which cannot be questioned, nothing else has been stressed and since according to the Bank Sectionwise/Departmentwise seniority-cum-merit-cum-suitability was the test applied, no promotions made at the relevant time can be questioned in the reference.

6. On the above pleadings the following points arise for consideration and my findings thereto are :—

	Issues	Findings
1.	Whether the dispute has been raised by an Union having substantial representative capcity ? If not Whether reference is competent ?	Yes it is competent
1A.	Whether the Union proves that for promotion to the posts of Special Assistant, only category to be considered is the category of Head Clerks ?	No
2.	Or Whether the Head Clerks, Section Heads or Chief Clerks could be considered for such promotion as contended by the Bank ?	Yes so far as in Bombay Region.
3.	Does the Union also establish that the claims of S/Shri Pereira and others as mentioned in the schedule to the Reference were ignored malafide by the Bank as contended ?	Make in law proved
4.	Does the Bank prove that they had applied seniority-cum-merit-cum-suitability test while effecting selections to the post of Spl. Assistants ?	Yes but without laying down the modalities.
5.	If yes, can this Tribunal enter into merits of application of such test, if the Union does not establish the malafides ?	Yes and modalities can be laid down by the Tribunal.
6.	Whether the Bank proves that the seniority is departmentwise and not cadre wise ?	No.
7.	If yes, whether such department wise seniority is to be accepted and followed ?	No.
8.	To what relief the Union is entitled ?	As per award.

REASONS

7. Although there was an attempt made to suggest that the Employees' Congress because it has no significant following in the Bank atleast in Bombay Region, cannot convert the present individual dispute into an industrial dispute, the membership record produced on behalf of the Employees' Congress indicates that out of 515 employees serving in the region, about 93 employees owe allegiance to the said Union and having regard to this proof, the contention that there is no significant following in the industry cannot survive and probably because of this at the time of argument this point was not seriously stressed.

8. The attempt to attribute mala fides to the Bank is on the sole ground that because Bank was hand in glove with the Employees' Federation, legitimate claims of some of the workmen were not considered. The record however indicates conclusively that the majority from these six workmen, on whose ehalf the Union has now raised cudgels, at the relevant time when the cause of action took place, owed allegiance to and were members of the Employees' Federation and not of the Employees Congress, though the very record further indicate that they switched over to the new Union subsequently. The contention therefore that to the deteriment of the interest of the members of the Congress, selecions of the members of the Federation were made to oblige the authorities of the Federation, can never stand to test. When some of these employees were members of the Federation, they cannot complain that their claims were ovelooked because they happened to be members of the Congres, or that by doing so the Bank acted mala fide. The charge of mala fides therefore on this ground is not at all substantiated.

9. It was then contended that when in other regions Section Heads were not considered for promotion of Special Assistants, Bombay Region was made exception so that certain members of the rival Union could be provided for. In this connection it is pertinent to note that the Bank had agreed to create new posts of Special Assistants out of new 49 posts all over India 19 posts of Special Assistants were allotted to Bombay Region and this allocation was in pursuance of the agreement arrived at with the Federation the terms of which agreement are spelt out from the copies of the correspondence between the Bank and the Federation At Ex. 21/M there is a copy of the letter dated 24-12-1979 addressed by the Bank to the Secretary of the Federation with speaks that as far as Bombay Region is concerned besides Chief Clerks, and Head Clerks, Section incharges shall also be eligible to be considered for being promoted as Special Assistants. It is pertinent to note that as admitted by Shri Vedak, Ex. 18/W and also admitted by Shri Pereira, Ex. 19/M some other persons like Roman Fernandes and Engineer were members of the Federation at the relevant time. It is further pertinent to note that because of the understanding with the Federation, the posts were increased and thus the employees could secure some advantage. Before that as per the contents of Ex 21/M there were 9 posts of Special Assistants all over India, two were in Calcutta Office, two in New Delhi Office, one in Delhi Office and four in Bombay Office. Out of these four, three in Bombay Office were previously in The Hongkong and Shanghai Banking Corporation and not liable to be replaced on their retirement. When therefore in pursuance of the discussions between the Federation and the Bank, more avenues were created by creating additional posts, the employees' Congress cannot be allowed to select some of the clauses of the agreement ignoring the remaining. If therefore they wanted all the 19 promotions to be made, whatever was the understanding will have to be accepted and the Employees Congress cannot be allowed to reapprobate and approbate. If therefore as spelt out in Ex. 21/M and 22/M the Section Heads so far as Bombay Region were also to be considered, merely because the list of promottees includes some of the Section Heads, though Head Clerks and Chief Clerks were senior to them, the same cannot be struck down merely on this ground.

10. There is however one legitimate grievance on the part of the employees namely that while effecting the selections not pooled seniority but Sectionwise and departmentwise seniority was considered, although as seen from Ex. 15/W, which is a specimen of appointment letter for Special Assistant, indications are that the posts were interchangeable as regards jobs with any other Special Assistants and that the timing and frequency of such changes was to be entirely at the discretion of the management. It is further stated in the said specimen letter that other duties applicable to the clerical cadres were in addition to the duties performed by the said special Assistants. Shri G. S. Gulvadi examined on behalf of the Bank, though stressed the need of Sectionwise or departmentwise promotions, at the same time admitted that subsequent on retirement of some of the Special Assistants applications were invited from Head Clerks and Section Heads serving in the Bombay Region not restricting to a particular section in which the vacancy arose. So far as the promotion of 19 employees were concerned, as the facts stand, because of the new creation of the additional posts, it is true this was the first occasion. Yet the particulars of understanding or agreement as evident from Ex. 21/M and 22/M, do not speak of any such restriction viz., that the seniority to be considered not regionwise but Sectionwise or departmentwise. If the Bank wanted to make it Sectionwise, in the first place they should have notified such intention and should have entered into agreement if not with both the union atleast with the majority Union and should have carried out the implementation of such agreement. Having regard to the Specimen letter of posting and having regard to the fact that in subsequent occasion the pooled seniority and not the Sectionwise or Departmentwise seniority was considered, the grievance made by the Employees' Congress assumes great force. Even the evidence of the witness examined on behalf of the Bank leads to the inference that without laying down any modalities in this regard certain selections were made as a result of which some senior hands were ignored, no doubt ultimately it would be the discretion of the Bank while determining the merits and the seniority, as claimed by the Bank but for the said purpose, they must consider the claims of all the concerned employees serving in the region who are eligible to be promoted and after assessing the merits of the individual employees and looking into their seniority taking them as a whole, the Bank if had made any selections, no ground could have been urged against it. As a result of Section/Department wise selection, some of the members as mentioned in Ex. 12/M though considerably senior could not be considered. As already stated if the Bank finds special merits in a particular employee, though lower in serial order, they could have picked up such employees after following the modalities, exercise of the discretion the Bank would not be a matter of dispute yet though ultimately the descretion of the Bank is to prevail, if in the absence of such modalities the selection is challenged, that challenge will have to be upheld.

11. The ratio laid down in workmen of M/s. Willamson Magor & Co. Ltd., Vs. M/s. William Magor & Co. Ltd. and another, a case decided by the Lordships of Supreme Court, 1982 (1), LLJ, page 33 is fairly applicable to the fact of the instant case. It is laid down there that promotion though managerial function cannot be left to the subjective test of the authorities but must be on, the basis of objective test. If such thing had not occured then it amounts to victimisation in

other words malice in law and any such promotion is liable to be struck down. It was insisted that some standard should be laid down for promotions, and merely repeating that it is managerial function or the discretion of the management for assessing the merits would not suffice and it is farther held that while deciding such cases, it is incumbent on the Tribunal to lay down modalities to be observed for effecting such promotions. If wrongly Section-wise seniority was considered, when the agreement or the understanding never speaks of any such test or parameter, and thereby if the interest of any employee who answered the requisite qualifications was affected, the only course left open that the Tribunal is to strike down such promotion. It is true that the Tribunal cannot impose its will on the Bank nor while striking down the promotions any direction can be made that a particular employee should be promoted and it is for the Bank who after observing certain modalities made in this regard shall perform its managerial function and carry out the selections. If the present arrangement is allowed as it is, it is bound to leave bad taste in the month of those who do not get the chance of being considerered for the promotion thus disturbing the peace in the Bank.

12. While laying down these modalities I direct as follows :—

(i) Seniority shall be considered not Section-wise or Department-wise but cadre-wise in Bombay Region. While doing so the Head Clerks, Chief Clerks and the Section Heads shall be eligible for promotion.

(ii) Each year of service as Head Clerk, Chief Clerk or Section Head as the case may be shall carry one mark.

(iii) If a particular employee is a Graduate he should carry two extra marks. If such a Graduate has passed the final examination with distinction, he should cary two additional marks.

(iv) Similarly, Bank's departmental examination Part I and II respectively should carry one extra mark each.

(v) If any employee has secured more than 75% marks in S.S.C. or equivalent examination he should get one mark extra.

(vi) While effecting promotions confidential file for five years previous to the year of promotion shall be considered. If there are any adverse ramarks, communicated to the employee, in his confidential record each such adverse remark would make liable to deduction of three marks. Similarly if there are good remarks in the confidential record also communicated during this period, acknowledging special merits, every such remark shall carry two extra marks.

(vii) After making the total number of marks thus calculated in the case of each of the concerned employee, the Bank shall prepare a list in serial order of merits disclosed by marks, and should make posting according to the number of vacancies as may be available.

(viii) In case two employees secure equal number of marks seniority in age shall be criteria. Even if those are equal, the decision of the Bank shall be the final.

(ix) New promotions as per the direction shall be carried out within two months from the date of publication of the award.

13. The promotions of 19 candidates impugned by the Employees Congress are hereby struck down. The Bank shall consider the merits of each respective candidates and applying the tests laid down shall make the promotions.

14. Although I am striking down the promotions, the 19 promotees shall continue to work in the said capacity as a stop-gap arrangement till the new promotions are made in pursuance of the directions. These 19 promotees till that time shall be eligible to draw special allowance. Those who have already retired, their cases need not be re-opened. Those who are to retire within two months from the date of this order also need not be considered.

Award accordingly.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-12012/303/80-D. II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O. 895.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay-1, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the India Security Press, Nasik Road, Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on the 19-1-83.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-2 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of the India Security Press, Nasik Road, Maharashtra

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the employer—Mr. B. M. Masurkar, Advocate.
For the workman—Mr. S. M. Dharap, Advocate.

INDUSTRY : Security Press STATE : Maharashtra

Bombay, the 31st day of December, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-42012(52)/79-D.II(B) dated 2nd July, 1980, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have

referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of the India Security Press, Nasik Road, Maharashtra, and their workman, in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of India Security Press Nasik Road, Maharashtra, in terminating the services of Shri Uttamgir D. Gosavi, Office Peon, vide Office Order No. Admn. 87/M dated 18th September, 1978, is justified and legal ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The workman, Uttamgir D. Gosavi, was appointed as an office peon in the office of the India Security Press (for short the "Press") with effect from 11th October, 1975. His services were terminated by an order dated 18-9-1975. Under the said order of appointment the workman was informed that the appointment was purely on temporary basis and was liable to be terminated without assigning any reason under rule 5 of he Central Civil Service (Temporary Services) Rules, 1965. The appointment order also mentioned that the workman was appointed on probation for two years in the first instance on a pay of Rs. 196 per month in the scale of Rs. 196-3-220-EB-3-232 plus dearness allowance and other allowances at the rates admissible under rules in force from time to time.

3. The workman in his statement of claim alleged as follows. He was appointed in pursuance of the Government of India, Cabinet Secretariat, Department of Personnel, New Delhi's instructions, contained in their memo dated 28th December, 1972 because he was possessing certificate of National Physical Efficiency Test 1967-68 awarded by the Government of India Ministry of Education. After his appointment on 11th October, 1975, he became entitled to yearly increments. He received both the increments which fell due on 11th October, 1976 and 11th October, 1977. He completed probationary period of two years on 11th October, 1977. After the completion of the probationary period he was continued. The workman further alleged that since he was continued in the employment after the completion of the probationary period satisfactorily and since there was no memo or charge-sheet issued to him he was deemed to be permanent. Under the circumstances the service rules which are applicable to the temporary employees were not applicable to him. The post in which he was appointed as a peon is a permanent vacancy and the same still continued in existence. His services were, therefore, illegally terminated.

4. Without prejudice to these contentions the workman contended that the termination of his services amounted to retrenchment as defined under Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It was alleged that the Press is an industry within the meaning of Section 2-J of the Industrial Disputes Act. He falls within the definition of the term 'workman' as defined in section 2(s) of the industrial Disputes Act. The workman alleged that the management had committed breach of the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act in not saying retrenchment compensation as well as notice pay as required therein. The workman stated in the statement of claim that his services have been terminated by a letter dated 18th September, 1978, which was received by him only in 26th October, 1978 He was still that date working in the Press as a peon. Even though the order referred to the payment of equivalent amount of a month's salary in lieu of notice period in fact, the same was not offered or paid to him at the time of termination.

5. The workman further stated that the employer did not follow the provisions for retrenchment viz., "first come first go". Some persons who were junior to him and who were named in the statement of claim were continued in service after his termination. The employer has thus committed a breach of Section 25-G of the Industrial Disputes Act. It was stated in the statement of claim that in case the employer contended that the services have not been terminated by way of retrenchment the termination amounted to dismissal of his services without affording an opportunity to defend himself. His termination, therefore, was void ab initio and illegal. After his termination he attempted to secure alternate employment. He failed in his attempts and he is unemployed without any job. On these pleadings the workman prayed that he be reinstated with full back wages and continuity of service.

6. The employer Security Press resisted the claim of the workman by their written statement dated 12th May, 1981. It is pleaded as follows. The workman's appointment in service was purely on temporary basis and the same was liable for termination without assigning any reason under rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965. The drawing of two increments while in service beyond the period of probation had no relevance as the workman's services being temporary were liable to be terminated without assigning any reason. The length of service is also immaterial so long as the workman worked in temporary capacity in the Government Department. It was further pleaded that the termination of the services of the workman was only a simple discharge; the question of issuing any memo or charge-sheet regarding the performance in service did not, therefore, arise. The workman cannot claim as of right confirmation in the service unless the orders to that effect were issued by the Government under the aforesaid rules. The employer further submitted that the termination of the services under rule 5 of the said rules of 1965 did not fall within the definition of the word 'retrenchment' as provided for under the Industrial Disputes Act. As the workman's services have not been terminated as and by way of retrenchment the provisions of the Industrial Disputes Act are not attracted. Section 25-F and other Sections of the Industrial Disputes Act are not applicable to the case of the workman. It was further pleaded that the workman remained absent on the afternoon of 18-9-1978 without any intimation or permission from the office and hence the order of termination could not be served on him for sometime. As the workman failed to turn up at the place of employment the payment by way of salary in lieu of notice though kept ready could not be disbursed to him and hence notice pay was not paid to him. It was also pleaded that the workman was employed in the office of the press, the Factories Act, therefore, did not apply and that the fact that the juniors to the workman have been retained in the service is not relevant in this case. The employee is not a workman as provided for under the Factories Act. The workman has not been dismissed from service and as such the question of affording

him an opportunity to defend himself does not arise. On these pleadings it was submitted that the demand of the workman for reinstatement and other reliefs be rejected

7. Additional written statement was filed on behalf of the employer on 12th July, 1982, containing that the initial appointment of the workman in the Press was irregular and illegal on the ground that the workman was not entitled to be employed in the Press as he was not sponsored by the Employment Exchange nor he belonged to the category of meritorious sportsmen deserving special consideration as laid down in Government of India circular dated 28-12-1972. It was stated that the initial appointment of this workman was manoeuvred in collusion with one of the officers of the Press. It was stated that this workman would not have been employed if he had not made wrong claim that he belonged to the category of meritorious sportsmen deserving special consideration for employment in the Government organisation.

8. The point that arises for my consideration in this reference is whether the action of the Press in terminating the services of the workman, Gosavi, was justified and legal. In addition to the documentary evidence produced by the parties, the workman has examined himself in this reference. No oral evidence was adduced on behalf of the Press. Now, coming to the documentary evidence it will be seen that the appointment order in respect of this workman is at exhibit P-1, shows that the workman was appointed on probation for two years on the scale mentioned in that order with effect from 11-10-1975 until further orders. It was stated that the appointment was purely on temporary basis and was liable for termination forthwith wihout assigning any reason under rule 5 of the said Rules 1965. Now, the two years' probationary period expired on 11-10-1977. The letter of termination of the services of the workman is at exhibit P-2. It is dated 18th September, 1978. The probationary period of two years expired on 11-10-1977 and the letter of termination is issued after about eleven months. It is not the case of the employer that the probationary period was extended. It cannot, therefore, be said that his termination was on the basis that he was a probationer and as his work was not found to be satisfactory his services were terminated. This is also not the plea of the Management.

9. It is pleaded by the employer by its additional written statement that the initial appointment of the workman was irregular and illegal on the ground that he was not sponsored by the Employment Exchange nor he belonged to the category of meritorious sportsman deserving special consideration. Now, it is not in dispute that the present workman was not sponsored for appointment by the Employment Exchange. Reliance is placed on behalf of the Press upon a Government of India circular dated 28th December, 1972 which is placed on record by the employer-Press. It is at exhibit P-3. That circular enjoins that the recruitment to all class III and IV posts shall be made through the Employment Exchange. However, the circular directs that on certain categories of sportsmen shall be considered meritorious and shall be eligible for consideration for recruitment to the service in class III and IV posts, even if they are not sponsored by the Employment Exchange. The categories of sportsmen stated in that circular are as follows :—

(i) Sportsmen who have represented a State or the country in a National or International Competition in any of the games/sports mentioned in the list at annexeure 'A'.

(ii) Sportsmen who have represented their Universities in the Inter-University Tournament conducted by the Inter-University sports Board in any of the sports/games shown in the list at annexure 'A' and

(iii) Sportsmen who have represented the state schools teams in the National Sports/games for Schools conducted by the All India School Games Federation in any of the games/sports shown in the list at annexure 'A'."

The workman in his deposition stated that he had submitted an application to the Press for employment. He was then called for interview. At the time of interview he had produced two certificates. He has produced those certificates on record. They are at exhibit W-1 and W-2. The certificate at exhibit W-1 is issued by the Government of India. It states that the workman has competed in the National Physical Efficiency Tests conducted in the year 1967-68 in the State of Maharashtra and has successfully qualified for the award of "Two Stars" Merit Certificate. The certificate at exhibit W-2 is dated 26-8-1975. It is issued by Janata Vidyalaya, District Nasik. It states that the workmen was bone fide student of that Vidyalaya; that he was interested in playing various games and bore good moral character. Now, strictly speaking these two certificates do not clothes the workman with the qualifications required in under the Government of India circular dated 28th December, 1972 (exhibit P-3). The question, however, for consideration is whether the management now can terminate the services of the workman on the ground that he was not initially qualified for recruitment to the post of a peon.

10. A reference can be made in this connection to the decision in the case of Rajeshwar Nath v. Union of India (1981 L.I.C. 696) where a single Judge of the Rajasthan High Court observed :—

"Where the employee who was appointed on the post of Class IV in Railway, was working continuously for more than one and a half decade, his retrenchment merely on the ground that his age was little more than the maximum eligible age for appointment at the time of his appointment was invalid. If the Railway had not been vigilant at the time of appointment, the ensure eligibilty, it is not open to them to throw a railway employee out of employment in the casual manner after a period of 15 years."

To the same effect are the observations in the case of Shiv Das Khajuria v. State of J. & K. (A.I.R. 1959 J&K 13). In that case also there was some misrepresentation by the employee at the time of his appointment and he was discharged from service after about two years of his appointment. The order of discharge was held to be bad.

11. As observed by the Rajasthan High Court if the management had not been vigilant at the time of appointment to ensure eligibility, it is no open to them to throw the employee out of employment after a substantial period. It may be mentioned that in the written statement filed on behalf of the management on 12th May, 1981, no case is made out that the initial appointment of the workman was irregular and illegal and was manoeuverd in collusion with one of the officers of the Press and that, therefore, his services were a terminated. This contention is sought to be taken the additional written statement dated 12th July, 1982. Apart from this, if the management wanted to say that the workman had obtained the initial appointment by fraud it would not be a case of simple discharge. The termination of the services of the workman in that case would be punitive and it would be necessary for the management to submit a charge-sheet and hold a departmental inquiry. In the absence of such departmental inquiry in which the workman is given an opportunity to defend himself, the termination of the services of the workman would be bad.

12. The important grounds on which the termination of the services of the workman is challenged are those based on Section 25-F and Section 25-G of the Industrial Disputes Act. The services of the workman were terminated under rule 5 of the said Rule, 1965. It would appear from the letter of appointment (exhibit P-1) dated 24th October, 1975, that the workman had been appointed as an office peon on probation for two years in the first instance with effect from 11-10-1975. Obviously, this probationary period expired on 11-10-1977. The workman continued in service after the probationary period was over. It is true that he was not confirmed in the post and it may be assumed that his appointment continued on temporary basis. Assuming that the management could terminate the services of the workman by resorting to the powers conferred by rule 5 of the said Rules, 1965, the question is whether the termination amounted to retrenchment.

13. Now, the expression "retrenchment" has been defined in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It is provided there :—

> "retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include—
>
> (a) voluntary retirement of the workman ; or
>
> (b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf ; or
>
> (c) termination of the services of a workman on the ground of continued ill-health ;"

Now, in the case of Santosh Gupta v. State Bank of Patiala (1980 I.I.C. p. 687) the Supreme Court has observed :—

> "The expression "termination of service for any reason whatsoever" in Section 2(oo) covers every kind of termination of service except those not expressly included in Section 25-F or not expressly provided for by other provisions of the Act as 25-FF and 25-FFF."

As laid down in the case of Tapan Kumar Jana v. Calcutta Telephones (1981 II L.L.J. 382) even a casual labourer is not excluded from the definition of a workman. It was observed in the said case by the Divisional Bench of the Calcutta High Court that it has not been laid down in the Act that only a permanent employee of an industry will be a workman. It is sufficient if an employee is employed in an industry for hire or reward. In view of this position, the termination of the services of even a temporary workman will amount to retrenchment and it will be necessary to comply with the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act, at the time of such retrenchment.

14. Mr. Masurkar, the learned counsel for the management, however, argued that the workman in this case worked as an office peon in the administration section. It was also contended by Mr. Masurkar that the workman was not appointed a workman as provided under the Factories Act. This argument is based on the ground that even though the Press may be a factory the workman was not employed in the factory. He was working as a peon in the administrative section. The question, however, is whether the employee was a workman under the Industrial Disputes Act. It cannot be disputed and it was not seriously disputed before me that the Press is not an industry. It is true that the Press is run by the Government. It cannot be said that by running the Press sovereign functions of the State are being discharged. Even though the parties have not led oral evidence, there is no dispute on the point that the main functions of the Press is to print currency notes or cheques. This work cannot be said to be the primary and inalienable function of the Government. The Government can entrust such a work of printing to other agencies. It is observed by His Lordship Justice Beg, C.J. in the decision of the Supreme Court in Bangalore Water Supply v. A. Rajappa (1978 I L.L.J. 349) that only those services which are governed by separate rules and constitutional provisions such a Articles 310 and 311 should strictly speaking, be excluded from the sphere of industry by necessary implication. He Lorship Justice V. R. Krishna Iyer observed in para 46 of the report :—

> "For instance, sovereign functions of the State cannot be included although what such functions are has been aptly termed "the primary and inalienable functions of a constitutional government." Even here we may point out the inaptitude of relying on the doctrine of regal powers. That has reference, in this context, to the Crown's liability in tort and has nothing to do with Industrial Law. In any case, it is open to Parliament to make Law which governs the State's relations with its employees. Articles 309 to 311 of the Constitution of India, the enactments dealing with the Defence Forces and other legislation dealing with employment under statutory bodies may, expressly or by necessary implication, exclude the operation of the Industrial Disputes

Act, 1947. That is a question of interpretation and statutory exclusion; but, in the absence of such provision of law, it may indubitably be assumed that the key aspect of public administration like public justice stand out of the circle of industry. Even here, as has been brought out from the excerpts of ILO documents, it is not every employee who is excluded but only certain categories primarily engaged and supportively employed in the discharge of the essential functions of constitutional government. In limited way, this head of exclusion has been recognised throughout."

As observed by His Lordship Justice Krishna Iyer in para 49 of the report that the material question is; what is the nature of the actual function assumend—is it a service that the State could have left to private enterprise. It cannot be disputed that the work that is being carried out in the Press is the work which could have been left to private enterprise. It cannot be said that the present workman was primarily engaged in the discharge of the essential functions of the Government. The workman, therefore, will be a workman within Section 2(s) of the Industrial Disputes Act.

15. Now, it cannot be disputed that the workman has rendered continuous service for a period of one year within the meaning of Section 25-F of the Industrial Disputes Act. He was appointed on 11-10-1975 and his services were terminated on 18-9-1978. Now, the Supreme Court has in the case of L. Robert D'Souza v. Executive Engineer, Southern Railway (Indian Factories Journal and Factories Journal Reports, Vol. 60 p. 144) decided on February 16, 1982, observed :—

"Once the case does not fall in any of the excepted categories, the termination of service, even if it be according to automatic discharge from service under agreement, would none the less be "retrenchment" within the meaning of section 2(oo) of the Act."

The Supreme Court further observed :—

"Even assuming that the workman whose service was terminated was a daily worker, once he has rendered continuous uninterrupted service for a period of one year or more within the meaning of Section 25-F of the Act and his services are terminated for any reason whatsoever and the case did not fall within any of the excepted categories, notwithstanding that the rules governing his service would be attracted, they would have to be read subject to the provisions of the Act, and the termination would amount to "retrenchment".

16. A reference may also be made in this connection to the decision of the Kerala High Court in the case of Bhaskaran v. Sub-Divisional Officer (1982 L.I.J. p. 248) where it is observed :—

"The provisions of Sections of 25F, 25G and 25H have overriding effect. Anything inconsistent contained in any other "law", which necessarily includes the Service Rules, cannot be given effect to. They have simply to be ignored, if the establishment in question is an industry."

In view of this legal position, the termination of the services of the workman will have to be held as ab initio void and illegal.

17. The next question is what relief should be given to the workman. A reference may usefully be made to the decision of the Supreme Court in the case of Surendra Kumar v. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi (1980 L.I.C. 1292). In this case it was observed :—

"Plain common sense dictates that the removal of an order terminating the services of workman must ordinarily lead to the reinstatement of the services of the workman. It is as if the order has never been and so it must ordinarily lead to back wages too. But, there may be exceptional circumstances which make it impossible or wholly inequitable vis-a-vis the employer and workman to direct reinstatement with full back wages. For instance, the industry might have closed down or might be in severe financial doldrums; the workman concerned might have secured better or other employment elsewhere and so on. In such situations, there is a vestige of discretion left in the Court to make appropriate consequential orders."

18. In the instant case there is violation of Section 25-G of the Industrial Disputes Act also. The workman has stated in para 6 of the statement of claim that some workman junior to him have been continued in service after the termination. He has supported that contention by a statement on oath. That statement is not contradicted. The workman has stated that he did not get service anywhere after his termination. The workman, therefore, be entitled to reinstatement and full back wages.

19. In the result, I find that the management of the Press was not justified in terminating the services of he workman, Uttamgir D. Gosavi, office peon, and the termination of his services was not legal. The workman, therefore, is entitled to the relief of reinstatement with full back wages and other consequential benefits.

20. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer

[No. L-42012(52)/79-D.II(B)]

A. K. SAHA MANDAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का०आ० 896.—मैसर्स कुमिन्स डीजल सेल्स एण्ड सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, पूना 411004 (महाराष्ट्र/7318) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (मुम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (मुम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/306/82-पी.एफ.-2]

S.O. 896.—Whereas Messrs Cummins Diesel Sales and Service (India) Limited, Poona (MH/7318) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this schme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point to view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(306)/82-PF. II]

का०आ० 897.—मैसर्स अनाकापाल्ले को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, नं० एम 33, अनाकापाल्ले 531001, (आन्ध्र प्रदेश/1226), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारिगों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/303/82-पी.एफ.-2]

S.O. 897.—Whereas Messrs The Anakapalle Co operative Marketing Society Limited, No. M-33, Anakapalle-531001, (AP/1226) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, and where any amendment is likely to affect adversely the interst of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(303)/82-PF. II]

का०आ० 898.—मैसर्स डिशेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता 1 (पश्चिम बंगाल/634 एण्ड पश्चिम बंगाल/627), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम इस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/(371)/82-पी.एफ.-2]

S.O. 898.—Whereas Messrs Dishergarh Power Supply Company Limited, 8, Clive Row, Calcutta-1 (WB/634 and WB/637) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment

from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amout payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(371)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1982

का०आ० 899.—मैसर्स यू०पी० सेल्स एण्ड सर्विस लिमिटेड, पो० बाक्स नं० 392, इंजीनियर्स एण्ड मशीनरी मर्चेन्ट, कानपुर (उ०प्र०/3557) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम इस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/(453)/82-पी. एफ.-2]

New Delhi, the 21st December, 1982

S.O. 899.—Whereas Messrs U.P. Sales & Service Ltd., Engineers and Machinery Merchant, Kanpur (UP/3557) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(453)/82-PF. II]

का०आ० 990—.मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, विश्वेश्वरैया इण्डस्टियल एरिया, हवाइट फील्ड रोड, बंगलौर 48 (कर्नाटक/ 5305), (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओ का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यो के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/(450)/82-पी.एफ -2]

S.O 900.—Whereas Messrs Graphite India Limited, Visvesvaraya Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore-560048 (KN/5305) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinater referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, th exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within " days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(450)/82 P.F. II]

का० आ० 901—मैसर्स श्री नित्याकल्याणी टैक्सटाईल्स लिमिटेड, विरुवनदानी-623407, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु (तमिलनाडु/4853), (जिसने इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/454/82-पी. एफ.-2]

S.O. 901.—Whereas Messrs Sree Nithyakalyani Textiles Ltd., Tiruvandanai-623407, Ramanathapuram District, Tamil Nadu (TN/4853) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(454)/82-PF. II]

का० आ० 902.—मैसर्स अमर उजाला हिन्दी दैनिक, गुरुद्वारा गुरु का ताल, उद्योग नगर, आगरा 282007 (उ०प्र०/337) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/446/82-पी. एफ.-2]

S.O. 902.—Whereas Messrs Amar Ujala Hindi Daily, Gurudwara Guru-Ka-Tal, Udyog Nagar, Agra (UP/337) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal hairs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S. 35014(446)/82-PF. II]

का० आ० 903—मैसर्स आन्ध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश/295) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/451/82-पी एफ -2]

S.O. 903.—Whereas Messrs Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, Hyderabad (AP/295) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A), of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(451)/82-PF. II]

का० आ० 904.—मैसर्स श्री दिग्विजय सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, डाकघर दिग्विजय नगर अहमदाबाद (गुजरात/3951) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/452/82-पी एफ -2]

S.O. 904.—Whereas Messrs Shree Digvijay Cement Company Ltd., P.O. Digvijay Nagar, Ahmedabad (GJ/3950) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this schme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the LIfe Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014/452/82-PF II]

का० आ० 905.—मैसर्स सेशासयी इण्डस्ट्रीज, वादलूर, एस० ए० (साउथ आरकाट) वादलूर-607303 तमिलनाडु (तमिलनाडु/3169) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, जो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उस मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014/291/82-पी. एफ.-2]

S.O. 905.—Whereas Messrs Seshasayee Industries, Limited, Vadalur-607303, South Arcot (TN/3169) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/291/82-PF. II]

का० आ० 906—मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट आग्रो इण्डस्ट्रीज डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 3 मंजिल, पंचानन, मालवीय नगर भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश/1636) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में यथास्थिति रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे सब फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/36/82-पी. एफ -2]

S.O. 906.—Whereas Messrs Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited, 3rd Floor, Panchanan, Malviya Nagar, Bhopal-462003, (MP/1636) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(360)/82-PF. II]

का० आ० 907—मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम, प्लाट नं० 18, मालवीय नगर, भोपाल-3 (मध्य प्रदेश/3583), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/361/82-पी. एफ.-2]

S.O. 907.—Whereas Messrs Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam, Plot No. 18, Malvia Nagar, Bhopal (MP)/3583), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(361)/82-PF. II]

का० आ० 908—मैसर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली-110020 (दिल्ली/932) के पास (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्वारण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/447/82-पी. एफ.-2]

S.O. 908.—Whereas Messrs The National Small Industries (Corporation) Ltd. Near Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 (DL/932) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-

Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable undr this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(447)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1982

का० आ० 909.—मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, उक्त स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. जीवन बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित जीवन बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, उक्त स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक ऐसे कर्मचारी की बाबत जो उक्त स्थापन छोड़ देता है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य स्थापन में कार्य-भार ग्रहण करता है, उस अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में छोड़कर बाहर जाने वाले कर्मचारी के नाम में वह आनुपातिक रकम अन्तरित करेगा जो उसे उस दशा में संदेय होती जब वह कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का सदस्य होता ।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक जीवन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा ।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

8. जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर पूर्वोक्त जीवन बीमा स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नाम-निर्देशिती को दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम को संदाय करेगा ।

9. जीवन बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बिहार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

10. यदि किसी कारणवश, उक्त स्थापन के कर्मचारी, स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या पूर्वोक्त जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट उस तारीख से रद्द की गई समझी जाएगी और स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन समझा जाएगा ।

11. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, जीवन बीमा स्कीम के अधीन आने वाले किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशिती विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में कर्मचारी की मृत्यु होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

12. उक्त स्थापन अपनी कर्मचारी निधि से कम से कम पांच लाख रुपये की रकम पृथक् करेगा और उसे एक पृथक् खाते में रखेगा जिससे स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन उद्भूत होने वाली बाध्यता का निर्वहन किया जाएगा । उक्त पृथक् खाते में जमा की गई रकम की समय-समय पर पूर्ति की जाएगी जिससे स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन संदाय तत्परता से सुनिश्चित किया जा सके ।

[संख्या एस-35014/14/78-पी. एफ.-2]

New Delhi, the 22nd December, 1982

S.O. 909.—Whereas Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamshedpur, Bihar (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2-A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any seperate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer in relation to the said establishment shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns and payment of inspection charges shall be borne by the employer of the said establishment.

4. The employer in relation to the said establishment shall display, on the Notice Board of the said establishment a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government and as and when amended with the amendments thereof alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. The employer in relation to the said establishment shall arrange in respect of an employee who leaves for the said establishment and joins another establishment covered under the said Act, to transfer to the insurance fund in respect of the other establishment the proportionate amount that would have been payable had he been a member of the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 to the credit of the outgoing employee.

6. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund under the said Act or the Provident Fund of the establishment exempted under the said Act is employed in the said establishment, the employer in relation to the said establishment shall immediately enrol him as a member of the Life Cover Scheme.

7. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Life Cover Scheme appropriately, if the benefits available under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amount payable under Life Cover Scheme aforesaid be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to legal heir or nominee of the employee.

9. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to express their point of view.

10. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain cover under the Life Cover

Scheme of the said establishment as already opted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Life Cover Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

11. Upon the death of an employee covered under the Life Cover Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case, wherein seven days of the death of the employee.

12. The said establishment shall set apart from their working fund a sum of Rs. five lakhs and the same shall be kept in a separate account from which obligations arising under the Life Cover Scheme of the said establishment shall be discharged. Amounts credited to the said separate account shall be replenished from time to time to ensure prompt payment under the Life Cover Scheme of the said establishment.

[No. S. 35014/14/78-PF. II]

का० आ० 910—मैसर्स मेघदूत पिस्टन (प्रा०) लिमिटेड, 6 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, आगरा-6 (उ०प्र/3585), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना नाम अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/449/82-पी.एफ. 2]

S.O. 910.—Whereas Messrs Meghdoot Pistons (P) Ltd., 6, Industrial Estate, Agra-6 (UP/3585) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(449)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1982

का० आ० 911—मैसर्स बहारी गुड्स कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, 4740 रोशनारा रोड, दिल्ली-110007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय शीघ्रता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/464/82-पी.एफ. 2]

New Delhi, the 23rd December, 1982

S.O. 911.—Whereas Messrs Bahri Goods Carriers Private Limited, 4740, Roshanara Road, Delhi-110007. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in

any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt of the sum assured to the nominee/ legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(464)/82-PF. II]

का० आ० 912.—मैसर्स एम०पी० टेक्स्टबुक कार्पोरेशन, शिवाजी नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश/2076), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/465/82-पी. एफ.-2]

S.O. 912.—Whereas Messrs The Text Book Corporation, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P. 2076), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(465)/82-PF. II]

का० आ० 913.—मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट, आर० टी० सी० काम्पलैक्स, विशाखापत्तनम, (आ० प्र०/6986), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब ऐसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन के नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/455/82-पी.एफ.-2]

S.O. 913.—Whereas Messrs Rashtriya Ispat Nigam Ltd., Vishakhapatnam Steel Project, RTC Complex Vishakhapatnam (AP/6986), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(455)/82-PF. II]

का० आ० 914.—मैसर्स सुसन टैक्सटाइल वियरिंग लिमिटेड, पो० बाक्स 289, बरोदा-390001 (गुजरात/1808), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/460/82-पी. एफ.-2]

S.O. 914.—Whereas Messrs Sussan Textile Bearing Ltd., P.B. No 289, Baroda-390001 (GJ/4808) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(460)/82-PF. II]

का० आ० 915.—मैसर्स डेली कालेज इन्दौर (मध्य प्रदेश/3973), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के

रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों का विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/463/82-पी.एफ. 2]

S.O. 915.—Whereas Messrs The Dely College, Indore (MP/3973), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(463)/82-PF. II]

का० आ० 916.—मैसर्स माडर्न बेकरीज (इ) लिमिटेड, उप्पल कलां, हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश/4445), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एम 35014/456/82-पी.एफ.-2]

S.O. 916.—Whereas Messrs Modern Bakeries (I) Ltd., Uppal Kalan, Hyderabad (AP/4445), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriate, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees han the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely tht interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(456)/82/02 PF. II]

का० आ० 917—मैसर्स सुमन टक्सटाईल बियरिंग लिमिटेड, पो० बाक्स न० 288, बड़ौदा, (गुजरात/4578), (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 195? (195? का 19) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन

फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014(457)/82-पी.एफ.-2]

S.O. 917.—Whereas Messrs Sussen Textile Bearing Ltd., P.B. No. 288, Baroda-390001 (GJ/4578) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a traslation of the sailiant features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employee under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the

nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S.35014(457)/82-PF. II]

का० आ० 918 - मैसर्स डेली कालेज मैस, इन्दौर (मध्य प्रदेश 3519), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/458/82-पी.एफ.-2]

S.O. 918.—Whereas Messrs The Daily College Mess, Indore (MP/3519), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life

Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sailent features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employee under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fail to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(458)/82-PF. II]

का० आ० 919.—मैसर्स स्वास्तिक फायल्ज प्राईवेट लिमिटेड, रामारोड, (नजफगढ़ रोड), नई दिल्ली-110015 (दिल्ली /5578), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/461/82-पी.एफ-2]

S.O. 919.—Whereas Messrs Swastik Foils Pvt. Ltd., 37, Rama Road, (Najafgarh Road) New Delhi-110015 (DL/5578) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fail to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(461)/82-PF. II]

का० आ० 920.— मैसर्स एसटाकौम ट्रेड एण्ड कम्पनी लिमिटेड 47, डाक्टर एनी बीसेन्ट रोड, बम्बई-400018 (महाराष्ट्र/1067), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/459/82-पी.एफ.-2]

S.O. 920.—Whereas Messrs Raptakos Brett & Co., Ltd., 47, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400025 (MH/1067) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employee under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fail to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment hall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(459)/82-PF. II]

का०आ० 921.— मैसर्स न्यू विनोद सिल्क प्रा० लिमिटेड कस्तुरचन्द मिल्स एस्टेट, वादर बम्बई (महाराष्ट्र/450), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार,

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/462/82-पी एफ-2]

S.O. 921.—Whereas Messrs The New Vinod Silk Mills Pvt. Ltd., Kasturchand Mills Estate, Dadar, Bombay (MH/450). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employee under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fail to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(462)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1982

का०आ० 922.— मैसर्स न्यू विनोद मिल्क मिल्स प्रा० लि०, चक्रवर्ती अशोक रोड, अशोक मार्ग, कन्हीवली (इ) बम्बई-400101 (महाराष्ट्र 20690), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी

रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/471/82-पी. एफ.-2]

New Delhi, the 28th December, 1982

S.O. 922.—Whereas Messrs The New Vinod Silk Mills Pvt., Chakravarti Ashok Road, Ashok Nagar Kandivili (E), Bombay-400101 (MH/20690). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said estabilshment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(471)/82-PF II]

का० आ० 923—मैसर्स गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड, तेनाली, आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र प्रदेश/2362), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां

भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिग/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदित अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/474/83-पी.एफ.-2]

S.O. 923.—Whereas Messrs The Guntur Dist. Co-Op. Central Bank Ltd., Tenali, (AP/2362) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(474)/82 PF. II]

का०आ० 924.—मेसर्स इंजीनियरिंग कनस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, 3बी, सेक्सपीयर सारनी, कलकत्ता-700071 (पश्चिम बंगाल/16601), (जिसे इसमें इससे पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/473/82-पी.एफ.-2]

S.O. 924.—Whereas Messrs Engineering Construction Corporation Ltd., 3B, Shakespeare Sarani, Calcutta-700071 (WB/16601) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(473)/82-PF. II]

का० आ० 925.—मैसर्स हरिहर ट्रान्सपोर्ट एण्ड कम्पनी, संगम माडल कम्पलैक्स कुमारपतन 23, धारवार (कर्नाटक/5448), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/472/82-पी.एफ.-II]

S.O. 925.—Whereas Messrs Harihar Transport and Company, Sangam Motel Complex, Kumarpatnam-23-Dharwar Dist. (KN/5448), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(472)/82-PF. II]

का०आ० 926.—मैसर्स डेल्टन मेल्स (प्रा०) लिमिटेड, 3457, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–110002, (दिल्ली/3241), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/169/82-पी०एफ०-II]

S.O. 926.—Whereas Messrs Delton Sales (Pvt.) Ltd., 345/1, Delhi Gate, New Delhi-110002. (DL/3241) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions applied in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said estabilshment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees, then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(469)/82-PF. II]

का०आ० 927.—मैसर्स अरुणिका निरंजन, चक्रवर्ती अशोक रोड, अशोक नगर कन्दिवली (ई), बम्बई-1 (महाराष्ट्र-12566), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/466/82-पी० एफ-2]

S.O. 927.—Whereas Messrs Arunika Niranjan, Chakravarti Ashok Road, Ashok Nagar Kandivli (E) Bombay-1. (MH/12566). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspecting, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(466)/82-PF. II]

का०आ० 928.—मैसर्स स्पोंजा आयरन इण्डिया लिमिटेड, पालोंचा-507154, खमाम जिला, आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र प्रदेश/4687), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधि अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/467/82-पी० एफ०-II]

S.O. 928.—Whereas Messrs Sponge Iron India Ltd, Palonch-507154, Khammam District Andhra Pradesh (AP/4687) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(467)/82-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1983

का० आ० 929.—मैसर्स जगतजीत कॉटन टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, श्रीगंगा नगर (राजस्थान/20) (जिसे इसके इसमें पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा है) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है; उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम/की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/9/83—पी० एफ०-2]

New Delhi, the 22nd January, 1983

S.O. 929.—Whereas Messrs Jagatjit Cotton Textile Mills Ltd., Sriganga Nagar, (RJ/20), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under

clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Gorup Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees. under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by theLife Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S. 35014(9)/83-PF.II]

का० आ० 930 मैसर्स बिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, 33 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसी उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया

जायेगा और जहां किसी मोचन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस 35014/8/83 पी०एफ०-2]

S.O. 930.—Whereas Messrs The Delhi State Co. Op. Bank Ltd., 31 Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi-110002, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for the period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses Involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the recipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(8)/83-PF.II]

का० आ० 931.—मैसर्स ट्रेड लिंक लिमिटेड, प्रभास किरण तीसरी मंजिल, 17 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8-(दिल्ली/1075), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन, बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो कि उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014/7/83 पी०एफ० 2]

S.O. 931.—Whereas Messrs Trade Links Limited, Prabhat Kiran (3rd Floor), 17, Rajendra Place, New Delhi-110008 (DL/1075) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving has approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(7)/83-PF. II]

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1983

का० आ० 932.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शाम फैब्रिकेटर्स, शिवाजी उद्यमनगर, कोल्हापुर-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/91/82-पी०एफ-II]

New Delhi, the 25th January, 1983

S.O. 932.—Whereas it appears to the Central Government that sions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sham Fabricators, Shivaji Udyamnagar, Kolhapur-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(91)/82-PF II]

का० आ० 933.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पुष्पक एन्टरप्राईस, 54 शाह इण्डस्ट्रियल इस्टेट, दियोनार, मुम्बई-88, जिसमें 2-बी, शंकर दर्शन, पन्दरहवी रोड, चेम्बूर, मुम्बई-88 स्थित उनका कार्यालय भी शामिल है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/92/82-पी०एफ-II]

S.O. 933.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pushpak Enterprise, 54, Shah Industrial Estate, Deonar, Bombay-88 including its Office at 2-B, Shankar Darshan, 15th Road, Chembur, Bombay-88, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(92)/82-PF. II]

का० आ० 934.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टैन्डर्ड सिन्थेटिक शेड नं० डब्ल्यू-10, ट्रान्स-थाना, क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया, आफ थाना, बेलापुर रोड पवाना, जिला थाना-400601 जिसके अन्तर्गत बी० 23 अतुल पार्क, सिऑन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई-71 स्थित उसका कार्यालय भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/94/82-पी०एफ-II]

S.O. 934.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Standard Synthetics, Shed No. W-10, Trans Thana Creek Industrial Area, Off Thana-Belapur Road, Pawana-Distt. Thana-400601 including its office at B-23, Atur Park, Sion Trombay Road, Chembur, Bombay-71, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952, should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(94)/82-PF. II]

का० आ० 935.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ताम्बिया इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 1111-ए० गहेजा चेम्बर्स 213, नारीमन पाईन्ट, मुम्बई-400021, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/95/82-पी०एफ-II]

S.O. 935.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tania Investments Pvt. Ltd. 1111-A, Raheja Chambers, 213, Narimen Point,Bombay-400021, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(95)/82-PF. II]

का०आ० 936.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल (ओवरसीस) लिमिटेड, अटलान्टा बिल्डिंग, नारीमन पाईंट, बम्बई-400021, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/114/82-पी०एफ-II]

S.O. 936.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Limited, Atlanta Building Nariman Point, Bombay-400021, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said etablishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(114)/82/PF. II]

का०आ० 937.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पीडो-मोटर्स, ब्लाक नं० 12, शाह इंडस्ट्रियल इस्टेट, दयोनर वीलेज, बम्बई-400088, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/115/82-पी०एफ-II]

S.O. 937.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Speed-O-Motors, Block No. 12, Shah Industrial Estate, Deonar Village, Bombay-400088, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fnuds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(115)/82-PF. II]

का०आ० 938.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कलापी इंजीनियरिंग वर्क्स, 25/बी, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सांगली-416416, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/116/82-पी०एफ-II]

S.O. 938.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kalapi Engineering Works, 25/B, Industrial Estate, Sangli-416416, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35018(116)/82-PF. II]

का०आ० 939.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फिरोज कुडियानवाला इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेकिनान मेकेन्ज़ीज बिल्डिंग, बेलार्ड इस्टेट, बम्बई-400038, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/117/82-पी०एफ-II]

S.O. 939.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in rlation to the establishment known as Messrs Pheroze Kudianavala Engineers Pvt. Limited, Mackinnon Mackenizie Building, Ballard Estate, Bombay-400038, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(117)/82-PF. II]

का०आ० 940.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उर्वशी श्याम आहूजा, ट्रेन्डप्रिंटर्स, 4, उषा किरन, कारमीचील रोड, बम्बई-400026, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35018/118/82-पी०एफ-II]

S.O. 940.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Urvashi and Sham Ahuja Handprints, 4, Usha Kiran, Carmichol Road, Bombay-400026, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952, should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(118)/82-PF. II]

का०आ० 941—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी इन्स्टीट्यूट आफ मेरीन इंजिनियर्स (इंडिया) सूट 32, तीसरी मंजिल अटलान्टा, नरीमन पाइन्ट, बम्बई-400021 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35018/119/82-पी०एफ० II]

S.O. 941.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Institute of Marine Engineers (India), Suite 32, 3rd Floor, Atlanta, Nariman Point, Bombay-400021, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(119)/82-PF. II]

का०आ० 942.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बालचन्दनगर शेती कामगार सहकारी पतपेढी मर्यादित लालपुर, डाकघर बालचंदनगर, जिला पुणे, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35018/120/82-पी०एफ० II]

S.O. 942.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Walchandnagar Sethi Kamgar Sahakari Patpedhi Maryadit, Lalpur, Post Office Walchandnagar, District Pune, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(120)/82-PF. II]

का०आ० 943.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एवान्स एण्ड कम्पनी, बी-44 गिरिराज इंडस्ट्रियल एस्टेट, महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (ईस्ट), बम्बई-400093 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35018/121/82-पी०एफ० II]

S.O. 943.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Evans & Company, B-44, Giriraj Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Bombay-400093, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(121)/82-PF.II]

का० आ० 944.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एक्यूदक्त इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 207 अरुण चेम्बर्स टारडीओ रोड, बम्बई-400034, तथा इसका ब्रांच आफिस, पो०आ० बाक्स नं० 410, ई-132, फोकल पाइंट, लुधियाना-141010 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35018/122/82-पी०एफ० II]

S.O. 944.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Aquadutt Industries Private Limited, 207, Arun Chambers, Tardeo Road, Bombay-400034 including its branch office at P.O. Box No. 410, E-132, Focal Point, Ludhiana-141010, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(122)/82-PF.II]

का०आ० 945—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुम इलेक्ट्रोनिक्स, 45, अटलान्टा, 209, नारीमन पाइट, मुम्बई-400021 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/123/82-पी एफ-II]

S.O. 945.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sum Electronics, 45, Atlanta, 209, Nariman Point, Bombay-400021, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(123)/82-PF-II]

का०आ० 946—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साईमर केमीकल इंडस्ट्रीज, गुरु गोविन्द सिंह इंडस्ट्रियल एस्टेट, यूनिट नं० 8, ग्राउन्ड फ्लोर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुम्बई-400063 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/124/82-पी०एफ०-II]

S.O. 946.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Simer Chemical Industries, Guru Govind Singh Industrial Estate, unit No. 8, Ground Floor, Western Express Highway, Goregaon (East), Bombay-400063, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(124)/82-PF. II]

का०आ० 947—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चिकेमर टेनेरीज (इण्डिया) बम्बई, पुने रोड, बिहाईन्ड वुलकान-लावल कसरवाड़ी, पुने-411018 व क्रिसेन्ट चम्बर्स प्रथम तल, तमारिण्ड लेन, फोर्ट, मुम्बई 23, स्थित इनके कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/125/82-पी०एफ०-II]

S.O. 947.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chikerur Tanneries (India), Bombay Poone Road, Behind Vulcan Laval Kasarwadi, Poone-411018 including its office at Crescent Chambers, 1st Floor, Tamarind Lane, Fort, Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(125)/82-PF. II]

का०आ० 948—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरुण कैमी-डाईज (प्राइवेट) लिमिटेड, चितलसार मानपाड़ा, घोडबन्दर रोड, पोस्ट बाक्स नं० 30, थाने-400607, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/90/82-पी०एफ०-II]

S.O. 948.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arun Chemi-Dyes (Private) Limited, Chitalsar Manpada, Ghobdunder Road, Post Box No. 30, Thane-400607, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(90)/82-PF. II]

का०आ० 949—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स किंग आफ किंग्स, 23 ए, सेन्ट्रल चौपाटी बिल्डिंग, चौपाटी मुम्बई-7, जिसके अन्तर्गत (1) 101, कल्याणदास उद्योग भवन, प्रभादेवी, मुम्बई-25 और (2) लोकोजी मेन्शन 21, चौपाटी सी फेस, मुम्बई 7 स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/72/82-पी०एफ०-II]

S.O. 949.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs King of Kings, 23 A, Central Chowpatty Building, Chowpatty Bombay-7 including its branches at (1) 101, Kalyandas Udyog Bhavan, Prabhadevi, Bombay-25, and (2) Lakozy Mansion, 21, Chowpatty Seaface Bombay-7, have agreed that the pdovisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(72)/82-PF. II]

का०आ० 950—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाबू भाई पटेल एण्ड कम्पनी, 81, आरकेडिया बिल्डिंग, 195, नरीमन पाइंट, मम्बई-21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35018/55/82-पी०एफ० 2]

S.O. 950.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Baboobhai Patel and Company, 81, Arcadia Building, 195, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

[No. S. 35018(55)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1983

का०आ० 951—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शरोफ ओवरसीज शिपिंग एजन्सी, 23ए नेताजी सुभाष रोड, (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/229/82-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 28th January, 1983

S.O. 951.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shroff Overseas Shipping Agency, 23A, Netaji Subhas Road (7th Floor), Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017/229/82-PF. II]

1254 GI/82—15

का०आ० 952—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी०सी० इन्टरप्राइसेज, एच-42, पहाड़पुर रोड, कलकत्ता 24., नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35017/230/82-पी०एफ-2]

S.O. 952.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B. C. Enterprises, H-42, Paharpur Road, Calcutta-24, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds ond Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act. to the said establishment.

[No. S-35017(230)/82-PF-II]

का० आ० 953—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एक्सपर्ट पेपर पैक्स (प्रा०) लिमिटेड, 109/1, बेलियाघाटा मेन रोड कलकत्ता-10 अपने मुख्यालय रजिस्टर्ड आफिस जी-7, इंडियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता-13 में स्थित है के सहित, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु-संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/231/82-पी० एफ-2]

S.O. 953.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Expert Paper Packs (Private) Limited, 109/1, Beliaghata Main Road, Calcutta-10 including its Head/Registered Officer at 7, Indian Mirror Street, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(231)/82-PF. II]

का० आ० 954—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हल्दिया रिफायनरी (इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटिड) हल्दिया टाउनशिप मेनटैनेंस जोन यूनिट,पोस्ट आफिस हल्दिया आयल रिफाईनरी, जिला मिदनापुर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/232/82-पी० एफ-2]

S.O. 954.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Haldia Refinery (Indian Oil Corporation Limited)—Haldia Township Maintenance Job Unit, Post Office Haldia Oil Refinery, District Midnapore, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(232)/82-PF. II]

का०आ० 955.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आनन्द एंड कम्पनी (नीटिंग यूनिट), 5/1, पुड्डापुकुर लेन, कलकत्ता-1, अपने मुख्यालय जो कि उसी प्रीमियसिस में है के सहित, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35017/233/82-पी० एफ-2]

S.O. 955.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anand and Company, (Knitting Unit), 5/1, Puddapukur Lane, Calcutta-1 including its Head Office in the same premises, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(233)/82-PF. II]

का० आ० 956.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हाउर्स लाईन्स (प्रा०) लिमिटेड, 9, स्टीफन हाउस, 5, डलहौजी स्क्वेयर, ईस्ट, कलकत्ता-1 अपनी शाखा जो अबरदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, अंडेमान्स में स्थित है, के सहित, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/234/82-पी० एफ-2]

S.O. 956.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hawers Lines (Private) Limited, 9, Stephen House, 5, Delhousie Square East, Calcutta-1 including is branch at Aberdeen Bazar, Port Blair, Andamans, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(234)/82-PF. II]

का० आ० 957—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेबल प्रीमिजस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 225-ई आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता--20 अपने कारखाने जो साल्ट लेक सिटी, सेक्टर-4, कलकत्ता-64 में स्थित है, के सहित । नामक स्थापन] से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं०-35017/235/82-पी० एफ-2]

S.O. 957.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Webel Precision Industries Limited, 225 F, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta-20 including its factory at Salt Lake City Sector-IV, Calcutta-64 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(235)/82-PF. II]

का०आ० 958—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टीग्रेटिड ब्यूरो एंड मैंटिनेंस (प्रा०) लिमिटेड, 26, शेक्सपियर सरनी (दूसरी मंजिल), कलकत्ता-17, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/236/82-पी० एफ-2]

S.O. 958.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in erlation to the establishment known as Messrs Integrated Bureau and Maintenance (Private) Limited, 26, Shakespeare Sarani (2nd Floor) Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-36017(236)/82-PF. II]

का० आ० 959.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बिहारी जी ट्रेडिंग कम्पनी, 3, कासीपुर रोड, कलकत्ता-2 अपने मुख्यालय जो 205, रविन्द्र सरनी, कलकत्ता-7 में है के सहित, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं-35017/237/82-पी० एफ-2]

S.O. 959.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shree Bihari Ji Trading Company, 3, Cossipore Road Calcutta 2 including its Head Office at 205, Rabindra Sarani, Calcutta-7, have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(237)/82-PF II]

का० आ० 960.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुद्रण शिल्पी 18 हेम चन्द्र नस्कर रोड (पी-20 सी०आई०टी० रोड) कलकत्ता-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/238/82-पी० एफ-2]

S.O. 960.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mudranshilpi 18, Hem Chandra Naskar Road (P-20 CIT Road Calcutta-10 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(238)/82-PF II]

का०आ० 961.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्लीपको स्टील्स लिमिटेड 261/276/277/1 जी० टी० रोड एन सालकीया (हावड़ा 711106 तथा इसका मुख्य कार्यालय 33/1 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35017/257/82 पी० एफ 2]

S.O. 961.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Klipco Steels (Private) Limited, 261/276/277/1 G T Road (N) Salkia, Hawrah-711106 including its Head Office at 33/1, Netaji Subhash Road, Calcutta 700001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment,

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S 35017(257)/82 PF II]

का० आ० 962.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बगारिया कमर्शियल कारपोरेशन 17 गणेश चन्द्र एवेन्यु, कलकत्ता 700013 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/258/82 पी० एफ० II]

S.O. 962.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bagaria Commercial Corporation 17 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(258)/82-PF II]

का०आ० 963.—केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्लो वेल फेन इण्डस्ट्रीज कमरा नं० 41 12-बी नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता 700001 तथा इसकी फैक्ट्री, 232/1-बी ए०पी०सी० रोड कलकत्ता--700004 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एम० 35017/259/82 पी०एफ० 2]

S.O. 963.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Blow-Well Fan Industries, Room No 41 12-B, Netaji Subhash Road, Calcutta 700001 including its factory at 232/1-B A P C Road, Calcutta 4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1951 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(259)/82 PF III]

का०आ० 964.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साहा रबड़ प्रोडेक्टस, 66, देवेन्द्र चन्द्रा रोड, कलकत्ता-700015 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं० एफ० 35017/260/82 पी०एफ० 3]

S.O. 964.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Saha Rubber Products, 66, Debendra Chandra Dey Road, Calcutta-700015, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(260)/82-PF. II]

का०आ० 965.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री राम टिम्बर इण्डस्ट्रीज, 532, डाईमन्ड हरबर रोड, बेहाला, कलकत्ता, 34, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस 35017/261/82 पी० एफ०-2]

S.O. 965.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Ram Timber Industries, 532, Diamond Harbour Road, Behala, Calcutta-34, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(261)/82-PF. II]

का०आ० 966.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शान्ता एण्ड सन्स, कम्पनी बिल्डिंग 19, पोल्लौक स्ट्रीट कलकत्ता 700001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किये जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस 35017/282/82 पी०एफ० 2]

S.O. 966.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shanta & Sons, 'Kampani Building', 19, Pollock Street, Calcutta-700001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(282)/82-PF. II]

का०आ० 967.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सी० ई० सी० इस्टर्न (प्राइवेट) लिमिटेड, 12 दरगा रोड कलकत्ता-700017 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35017/283/82 पी० एफ 2]

S.O. 967.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs C.E.C. Eastern (Private) Limited, 12, Darga Road, Calcutta-700017, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(283)/82-PF. II]

का०आ० 968.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईस्टर्न सर्विसेज एण्ड सप्लाइस, 62/एफ अलीपोर रोड, कलकत्ता-700027 तथा इसका वेयरहाऊस, पी० 1. ट्रांसपोर्ट डी पो रोड, कलकत्ता-700027 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35017/284/82 पी० एफ० 2]

S.O. 968.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Eastern Services and Supplies, 62/F, Alipore Road, Calcutta-700027 including its Warehouse at P-1, Transport Depot Road, Calcutta-700027, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(284)/82-PF. II]

का॰ आ॰ 969.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के॰ एस॰ एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड, 84, छत्ता रोड, कलकत्ता 700027 तथा इसका मुख्य कार्यालय, 105, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता 700016 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं॰ एस 35017/285/82 पी॰ एफ 2]

S.O. 669.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. S. Associates Private Limited, 84, Chatta Road, Calcutta-700027 including Head Office at 105, Park Street, Calcutta-700016, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(285)/82-PF. II]

का॰ आ॰ 970.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रासेनसेन्टर, 16, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरी मंजिल कलकत्ता-700001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं॰ एस-35017/286/82-पी॰ एफ॰ 2]

S.O. 970.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Prasencentre, 16, India Exchange Place, 3rd Floor, Calcutta-700001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(286)/82-PF. II]

का॰ आ॰ 971.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स, अवोमेक कमर्शियल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, 2 ए एण्ड 2 बी,) "अपना घर" 7 ब्राईट स्ट्रीट, कलकत्ता-700019 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस-35017/287/82-पी॰ एफ॰ 2]

S.O. 971.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Avomec Commercial (India) Private Limited, 2-A, & 2-B, "Aapanghar", 7, Bright Street, Calcutta-700019, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to to the said establishment.

[No. S.35017 (287)/82-PF. II]

का॰ आ॰ 972.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डालमिया इंजिनियर्स, प्राइवेट लिमिटेड सूट न॰ 1, पहली मंजिल, "स्टीफन हाउस" 4, बी॰ बी॰ डी॰ बाग, ईस्ट, कलकत्ता-700001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं॰ एस-35017/288/82-पी॰ एफ॰ 2]

S.O. 972.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dalmiya Engineers Private Limited, Suit No. 1, Ist Floor, "Stephen House," 4, B.B.D. Bag, East, Calcutta-700001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35017(288)/82-PF.II]

का॰ आ॰ 973.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एडकम इंडिया, 7-ए, सरकार हैट लेन, कलकत्ता-700061 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं॰ एस-35017/289/82-पी॰ एफ॰ 2]

S.O. 973.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Adcom India, 7-A Sarkar Hat, Lane, Calcutta-700061, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35017(289)/82-PF.II]

का० आ० 974.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी० एक्स० पी० एक्स पो० प्राईवेट लिमिटेड, 24, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001 तथा इसकी फैक्ट्री 4/1, पंडितया रोड, कलकत्ता-29 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/190/82-पी० एफ० 2]

S.O. 974.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs V. S. P. Expo (Private) Limited, 24, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001 including its factory at 4/1, Panditya Road, Calcutta-700029 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35017 (290)/82 PF. II]

का० आ० 975.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान स्टाव मेन्यूफेक्चुरिंग कम्पनी, 2, पगलाडांगा रोड, कलकत्ता-700015 तथा इसका कार्यालय 15, केनल ईस्ट, रोड, कलकत्ता-700067 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/291/82-पी० एफ० 2]

S.O. 975.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindusthan Stave Manufacturing Company, 2, Pagladanga Road, Calcutta-700025 including its office at 15, Canal East Road, Calcutta-700067, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S.35017 (291)/82-PF. II]

का० आ० 976.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ग्रेव्यूर प्रिन्टर्स एण्ड कनवर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 3 वूडबर्न रोड, कलकत्ता-700020 तथा इसका पंजीकृत कार्यालय, 2, गनेश चन्द्र अवेन्यू, कलकत्ता-13, और फैक्ट्री, 3, राशमनी बाजार रोड, कलकत्ता-700010 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35017/192/82-पी० एफ० 2]

S.O. 976.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gravure Printers and Converters Private Limited, 3, Woodburn Road, Calcutta-700020 including its Regd. Office at 2, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013 and the Factory at 3, Rashmoni Bazar Road, Calcutta-700010, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(292)/82-PF. II]

का० आ० 977.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वारसन्मम 139 डी/4 आनन्द पालित रोड कलकत्ता-700014 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/193/82-पी० एफ०]

S.O. 977.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Varsams, 139/D/4, Ananda Palit Road, Calcutta-700014. have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(293)/82-PF. II]

का० आ० 978.—केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्लेक काकटस (प्राइवेट) लिमिटेड, 26/डी, पार्क लेन, कलकत्ता-700016 तथा इसका यूनिट "अभिशेक", 12 दरगा रोड, कलकत्ता-700017 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/294/82-पी० एफ० 2]

S.O. 978.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Black Kactus (Private) Limited, 26/D, Park Lane, Calcutta-700016 including its unit at "Abhishek" 12, Darga Road, Calcutta-17 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(294)/82-PF. II]

का० आ० 979.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि न्यू तेराई एसोसिएशन लिमिटेड, 26, बरटोला स्ट्रीट, कलकत्ता-700007 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस 35017/295/82-पी० एफ० 2]

S.O. 979.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The New Terai Association Limited, 26, Burtolla Street, Calcutta-700007 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35017(295)/82-PF. II]

का० आ० 980.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशिश रेफेक्ट्रीस सेल्स डीवीजन, 83/1, बेन्टिक स्ट्रीट, पोस्ट बोक्स सं० 2253, कलकत्ता -700001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/296/82-पी० एफ० 2]

S.O. 980.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ashish Refractories Sales Division, 83/1, Bentinch Street, Post Box No. 2253, Calcutta-700001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(296)/82-PF. II]

का० आ० 981.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कम्पनी ब्रदर्स, 'कम्पनी बिल्डिंग' 19, पोल्लोक स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० -35017/29-एस/82-पी०एफ० 2]

S.O. 981.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kampani Brothers, 'Kampani Building', 19, Pollock Street, Calcutta-700001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(297)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1983

का० आ० 982.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेस्ट बंगाल हैन्डीक्राफ्ट, डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 3 डेकर्स लेन, कलकत्ता-69, जिसके अंतर्गत (1) मंजूषा बंगाल एम्पोरियम, 83, एम० जी० रोड, बंगलोर-1, (2) मंजूषा, बंगाल एम्पोरियम, 26-डी, हिल कार्ट रोड, दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल), (3) मंजूषा, बंगाल एम्पोरियम, दमदम एयरपोर्ट, कलकत्ता (4), मंजूषा बंगाल एम्पोरियम, हावड़ा सब वे हावड़ा और सेन्ट्रल स्टोरस 55, कनाल ईस्ट रोड, कलकत्ता, स्थित उसकी शाखायें भी है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/66/79-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O. 982.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The West Bengal Handicraft Development Corporation Limited, 3, Dacres Lane, Calcutta-69 including its branches at (1) Manjusha, Bengal Emporium, 83, M. G. Road, Bangalore-1, (2) Manjusha, Bengal Emporium, 26-D, Hill Cart Road, Darjeeling (West Bengal), (3) Manjusha, Bengal Emporium, Dum Dum Airport Calcutta, (4) Manjusha, Bengal Emporium, Howrah Sub-Way, Howrah, and Central Stores, 55, Canal East Road, Calcutta, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(66)/82-PF. II]

का० आ० 983.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उषा म्युचुअल बैनिफिट सोसाइटी लिमिटेड, 7, दुर्गा चरण, डाक्टर लेन, कलकत्ता-14 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/169/82-पी० एफ० 2]

S.O. 983.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Usha Mutual Benefit Society Limited, 2 Durga Charan Doctor Lane, Calcutta-14, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(169)/82-PF. II]

का० आ० 984.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लोकनाथ आयरन इंडस्ट्रीज, मजेरहटी लेन नारायणपल्ली, कलकत्ता-49 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/172/82-पी० एफ० 2]

S.O. 984.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lokenath Iron Industries, Majerhati Lane Narayan Pally, Calcutta-49, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(172)/82-PF. II]

का० आ० 985.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मदर डेयरी, डाकघर चाकुंडी वाया चांदीतलला, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/173/82-पी० एफ० 2]

S.O. 985.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mother Dairy, Post Office Chakundi, Via Chanditala, District Hooghly, (West Bengal), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35017(173)/82-PF. II]

का० आ० 986.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बालीगंज फाइनांशियर्स एंड पॉलिमेकेनिक इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 203, शरत बोस रोड, कलकत्ता-29 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/174/82-पी० एफ० 2]

S.O. 986.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ballygunj Financiers and Polymecanique Industries (Private) Limited, 203, Sarat Bose Road, Calcutta-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(174)/82-PF. II]

का० आ० 987.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जुमैक स्पेयर्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन, 3, प्रिंसेप स्ट्रीट, कलकत्ता 72 जिसके अन्तर्गत 277 बी० टी० रोड कलकत्ता-36 स्थित इसका कारखाना भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस०-35017/175/82-पी० एफ० 2]

S.O. 987.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jumac Spares Manufacturing Corporation, 3, Princep Street, Calcutta-72 including its Factory at 277, B. T. Road, Calcutta-36, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(175)/82-PF. II]

का० आ० 988.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० एण्ड ए कंपनी, 76, आचार्य जे० सी० बोस मार्ग, कलकत्ता-14, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/176/82-पी० एफ० 2]

S.O. 988.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P and A Company, 76, Acharya J. C. Bose Road, Calcutta-14, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(176)/82-PF. II]

का० आ० 989.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अपर्णा ट्रेडिंग कारपोरेशन (ए) डि० कलकत्ता-11, क्लाईव वेयर हाउस, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/177/82-पी० एफ० 2]

S.O. 989.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Aparna Trading Corporation (A) Department Calcutta, 11, Clive Ware House, Strand Road, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(177)/82-PF. II]

का० आ० 990.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रेसिसैक इंजीनियरिंग कम्पनी, पी-6 जोगेन्द्र गार्डन, राजडांगा, पोस्ट आफिस हल्टु, 24-परगनाज (पश्चिमी बंगाल) जिसके अंतर्गत 264/1, बी० बी० चटर्जी रोड, कस्बा कलकत्ता-42 स्थित इसका कार्यालय है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/178/82-पी० एफ० 2]

S.O. 990.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Precivac Engineering Company, P-6, Jogendra Garden, Raidanga, Post Office Haltu, 24-Parganas (West Bengal), including its Office at 264/1, B. B. Chatterjee Road, Kasba, Calcutta-42, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(178)/82-PF. II]

का० आ० 991.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एक्सकोन (पायोनियर) प्राइवेट लिमिटेड, 5, फेंसी लेन, तीसरी मंजिल, कलकत्ता-1, जिसके अन्तर्गत पन्डुआ (कामरपारा) जिला हुगली स्थित इसका कारखाना भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/179/82-पी० एफ० 2]

S.O. 991.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Excon (Pioneer) Private Limited, 5, Fancy Lane, 3rd Floor, Calcutta-1, including its factory at Pandu, (Kamarpara), District Hooghly, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ((19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(179)/82-PF. II]

का० आ० 992.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्द स्टील प्रोसैसर्स, 216, जी० टी० रोड (उत्तर) घुसुरी, हावड़ा-711107 (पश्चिमी बंगाल) जिसके अन्तर्गत मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, कलकत्ता-7, स्थित इसका कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/180/82-पी० एफ० 2]

S.O. 992.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hind Steel Processors, 216, G. T. Road (North), Ghusuri, Howrah-711107, (West Bengal) including its Office at Madan Mohan Burman Street, Calcutta-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneius Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(180)/82-PF. II]

का० आ० 993.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पाल क्रेन सर्विस, 138, अंकुर रोड, हावड़ा (पश्चिमी बंगाल), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/181/82-पी० एफ० 2]

S.O 993.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Paul Crane Service, 138, Andul Road, Howrah, (West Bengal) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(181)/82-PF II]

का० आ० 994 – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टैकना डाइंग एंड ब्लीचिंग वर्क्स, 21-ए, दमदम रोड, कलकत्ता-30 जिसके अन्तर्गत 195/1 महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-7 स्थित इसका मुख्य कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/182/82-पी० एफ० 2]

S O 994—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Techno Dyeing and Bleaching Works, 21-A, Dum Dum Road, Calcutta 30 including its Head Office 195/1, Mahatma Gandhi Road, Calcutta 7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(182)/82-PF II]

का० आ० 995 –केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओंकार इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/183/82-पी० एफ० 2]

S O. 995,—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Onkar Industries (Private) Limited, 18, Netaji Subhash oad, Calcutta 1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(183)/82-PF II]

का० आ० 996—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी० आर० फलोर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 20 कवि भारत चौ० रोड, कलकत्ता-28 जिसके अन्तर्गत 185-बी, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-4, स्थित इसका शोरूम और कार्यालय तथा 10, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट ,कलकत्ता-1 स्थित इसका लेखा कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/184/82-पी० एफ० 2]

S O 996—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D. R. Floors (Private) Limited, 20, Kavi Bharat Ch Road, Calcutta 28, including its Showroom and Office at 185-B, Raja Dinendra Street, Calcutta-4 and its Accounts Office at 10, Old Post Office Street Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(184)/82-PF II]

का० आ० 997—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनाईटेड इंजीनियरिंग वर्क्स, पी-18, जोगेन्द्र गार्डन राजडांगा, पोस्ट आफिस हल्टु, कलकत्ता-79, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/185/82-पी० एफ० 2]

S.O. 997—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs United Engineering Works, P-18, Jogendra Garden Rajdanga, Post Office Haltu, Calcutta-78, have agreed that the provisions Office Haltu, Calcutta-78, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35017(185)/82 PF. II]

का० आ० 998—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विक्रांत स्पेशल मशीन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 8/5-एफ, गढ़ियाहाट रोड (मलिन पार्क) कलकत्ता-19 जिसके अंतर्गत 63, श्याम नगर रोड, कलकत्ता-55, स्थित इसका कारखाना भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/186/82-पी० एफ० 2]

S.O. 998.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vikrant Special Machines (Private) Limited, 8/5-F, Gariahat Road, (Merlin Park), Calcutta-19 including its factory 63, Shyam Nagar Road, Calcutta-55, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(186)/82-PF. II]

का० आ० 999.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडिया फोर्जिंग्स कंपनी, 6, गदाधर भट्ट रोड भट्टानगर, लिलुआ हावड़ा, जिसके अन्तर्गत 4, ब्लेक बर्न लेन (तिरहटी बाजार) कलकत्ता-12 स्थित उसका प्रशासनिक कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/192/82-पी० एफ० 2]

S.O. 999.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs India Forgings Company 6, Godadhar Bhatta Road, Bhattanagar, Liluah, Howrah including its Administrative Office at 4, Black Burn Lane, (Tirahatti Bazar), Calcutta-12, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(192)/82-PF. II]

का० आ० 1000.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यमुना टिम्बर इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 8 एंड 9 बेन्टींक स्ट्रीट, कलकत्ता-1, जिसके अन्तर्गत 15 माइलपोस्ट, जी० एस० रोड डाकघर बुर्नीहाट, जिला पूर्वी खासी हिल्स (मेघालय) स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/194/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1000.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yamuna Timber Industries (Private) Limited, 8 and 9, Bentinck Street, Calcutta-1 including its branch at 15th Milepost, G. S. Road, Post Office Burnihat, District East Khasi Hills (Meghalaya), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(194)/82-PF. II]

का० आ० 1001.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनिपेक टिम्बर (प्राइवेट) लिमिटेड, 8 और 9, बेन्टींक स्ट्रीट कलकत्ता-1, जिसके अन्तर्गत 15, माइलपोस्ट, जी० एस० रोड, डाकघर बुर्नीहाट जिला पूर्वी खासी हिल्स (मेघालय) स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/195/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1001.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Unipack Timber (Private) Limited, 8 and 9, Bentinck Street, Calcutta-1 including its branch at 15th Milepost, G. S. Road, Post Office Burnihat, District East Khasi Hills (Meghalaya), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(195)/82-PF. II]

का० आ० 1002.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बर्दवान ग्रामीण बैंक, कोर्ट कम्पाउन्ड, पी० ओ० एण्ड जिला बर्दवान 713101 तथा इसकी (1) सिवराम मार्केट, बी० सी० रोड (समीप रूप महल), बर्दवान (2) राय पेरा, जी० टी० रोड, खानयान, हुगली (3) गांव व डाकघर पाराज, जिला बर्दवान (4) गांव धनचूरा डाकखाना घोषापारा, जिला हुगली (5) डाकखाना रवाना जंकशन, बर्दवान (एम०फ०म० गलर्स 72) (6) मोसग्राम रेलवे बाजार, डाकखाना मोसग्राम, जिला बर्दवान (7) गांव व डाकखाना गुरुलिया, जिला बर्दवान (8) गांव व डाकखाना अग्राहटी, जिला बर्दवान (9) डाकखाना गोस्वामी मालीपारा, बारास्ता पुरनाम (हुगली) (10) गांव पत्सुल, डाकखाना सुगन्ध्या, जिला हुगली (11) ग्राम व डाकखाना मसीग्राम, जिला बर्दवान (12) गांव व डाकखाना श्रीखन्डा, जिला बर्दवान (13) गांव वाडदेवपुर, डाकखाना ब्राह्मणपारा जिला हुगली (14) गांव मोबिना, डाकखाना जिना गोविन्दपुर, जिला हुगली (15) गांव व डाकखाना कोहर, (बारास्ता सतगेछिया) जिला बर्दवान (16) गांव व डाकखाना सिहो, जिला बर्दवान (17) गांव व डाकखाना कासिमनगर, जिला बर्दवान और (18) जी० टी० रोड, डाकखाना शिमलागढ़ जिला हुगली स्थित शाखाओं सहित स्थापनाओं से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/1/83-पी०एफ 2]

S.O. 1002.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bardhaman Gramin Bank, Court Compound, Post Office and District Burdwan 713101 including its branches at (1) Sibram Market, B. C. Road (Near Rupmahal), Burdwan, (2) Roy Para, G. T. Road, Khanyan, Hooghly, (3) Village a nd Post Office Paraj, District Burdwan, (4) Village Inchura, Post Office Dhobapara, District Hooghly, (5) Post Office Khana Junction, Burdwan, (N. Ph. No. Galsi 72), (6) Mosagram Railway Bazar, Post Office Mosagram, District Burdwan, (7) Village and Post Office Churulia, District Burdwan, (8) Village and Post Office Adrahati, Distdict Burdwan, (9) Post Office Goswami Malipara, Via Pujnan (Hooghly), (10) Village Patul, Post Office Bagandhya, District Hooghly, (11) Village and Post Office, Nasigram, District Burdwan, (12) Village and Post Office Srikhanda, District Burdwan, (13) Village Basudebpur, Post Office Braminpara, District Hooghly, (14) Village Modina, Post Office Gobindapur, District Hooghly, (15) Village and Post Office Bohar, (Via-Satgechia), District Burdwan, (16 Village and Post Office Singi, District Burwan, (17) Village Village and Post Office Kasemnagar, District Burdwan and (18) G.T. Road, Post Office Simlagarh, District Hooghly, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(1)/83-PF.II]

का० आ० 1003.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बेनलोन इण्डस्ट्रीज, प्लाट डी 9, 21वी रोड, एम० आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई-93 जिसके अन्तर्गत 109, सर विठल दास चैम्बर्स, मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई-23 स्थित इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35018/86/82 पी०एफ० 2]

S.O. 1003.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Benelon Industries, Plot D-9, 21st Road, MIDC, Industrial Area, Andheri East, Bombay-93 including its Registered Office at 109, Sir Vithaldas Chamber, Bombay Samachar Marg, Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(86)/82-PF-II]

का०आ० 1004.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एपेक्स ट्रेवल्स एण्ड टूर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 107, दलमल टावर पहली मंजिल नारीमन पाइंट, मुम्बई 121 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35018/88/82 पी०एफ० 2]

S.O. 1004.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Apex Travels and Tours (Private) Limited, 107, Dalamal Tower, 1st Floor, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(88)/82-PF. II]

का०आ० 1005.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नागपुर पल्वेराइजर्स एंड मिनरल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बी-28 एम आई०डी०सी० एरिया, नागपुर-16, जिसमें उसका उसी परिसर में स्थित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35018/89/82-पी०एफ० 2]

S.O. 1005.—Whereas it a ppears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nagpur Pulverisers and Minerals (Private) Limited, B-28, MIDC Area, Nagpur-16 including its Registered Office in the same premises, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(89)/82-PF-II]

का०आ० 1006.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (4) के अनुसरण में निर्देश देती है कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 494 तारीख 27-1-1982 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "मैसर्स रिलाएन्स सर्विसेज, 13, रामगोपाल इन्डस्ट्रियल इस्टेट, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, मुलुन्द (पश्चिमी) मुम्बई-80" शब्दों और अंकों के स्थान पर "रिलाएन्स सर्विसेज, 13, रामगोपाल इन्डस्ट्रियस एस्टेट, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, मुलुन्द (पश्चिमी) मुम्बई-80 जिसके अन्तर्गत 44, जमनादास इन्डस्ट्रियल इस्टेट, मुलुन्द (पश्चिमी) मुम्बई-80 स्थित उसका कार्यालय भी है," शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं० एस-35018/99/81-भ०नि. 2]

S.O. 1006.—In pursuance of sub-section (4) of Section 1 of the Employees Provident Funds and Miscellanous Provisions Act 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 494 dated the 27-1-1982, namely :—

In the said notification, for the words and figures "Messrs Reliance Services, 13, Ramgopal Industrial Esta'e, Dr. Rajendra Prasad Road, Mulund (West), Bombay-80" the following words and figures shall be substituted "Reliance Services, 13, Ramgopal Industrial Estate, Dr. Rajendra Prasad Road, Mulund (West) Bombay-80 including its Office at 44, Jamnadas Industrial Estate, Mulund (West), Bombay-80."

[No. S. 35018/99/81-PF-II]

का०आ० 1007.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वोल्टास इम्पलाईज कोपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, डा० आम्बेडकर रोड, चिन्चपोकली, बम्बई-400033 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35018/1/83-पी०एफ० 2]

S.O. 1007.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Voltas Employees' Co-operative Credit Society Limited, Voltas Limited, Dr. Ambed-Kar Road, Chinchpokli, Bombay-400033, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(1)/83-PF.II]

का०आ० 1008.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रघुवंशी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, 397, लाहन मेमन स्ट्रीट, बम्बई-400002 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/2/83-पी०एफ० 2]

S.O. 1008.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raghuvanshi Cooperative Bank Limited, 397, Saeikh Mamon Street, Bombay-400002, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(2)/83-PF. II]

का०आ० 1009.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्लोन कान्टेनरस, 2/3, सतगुरु नानीक इंडस्ट्रीयल एस्टेट, वेस्टरन एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (इस्ट), मुम्बई-400063 तथा इसका कार्यालय, 213, औद्योग मंदिर नं० 1, 7/सी, पितामबर लेन, महीम (वेस्ट) मुम्बई-400016 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35018/3/83-पी०एफ० 2]

S.O. 1009.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Blown Containers, 2/3 Satguru Nanik Industrial Estate, Western Express Highway, Goregaon (East), Bombay-400063 including its office at 213, Udyog Mandir No. 1, 7|C, Pitamber Lane, Mahim (West), Bombay-400016, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(3)/83-PF-II]

का० आ० 1010.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कृष्क भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, रेड रोज हाउस, 49-50 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली, जिसके अंतर्गत (1) दूसरी मंजिल, राजेश्वरी एपार्टमेंटस, तिमालियावाद, नानपुरा, सूरत-1 (2) 1/5, ब्रडीज फ्लेटस, सोराब भरुचा मार्ग, कोलाबा, मुम्बई-5 और (3) तीसरी मंजिल, मिस्त्री चेम्बर्स, कामा होटल के पास, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/345/82-पी०एफ० 2]

S.O. 1010.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Krishak Bharati Co-operative Limited, Red Rose House, 49-50, Nehru Place, New Delhi-19 including its Branches at (1) 1st Floor, Rajeshwari Apartmeht, Timaliyawad, Nanpura Suart-1 (2) 1|5, Brady's Flats, Sorab Bharucha Road, Colaba, Bombay-5 and (3) 2nd Floor, Mistry Chambers Near Cama Hotel, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35019(345)/82-PF-II]

का० आ० 1011.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स किलपोक बेनीफिट सोसाइटी लिमिटेड, सं० 20, ओर्मस रोड, किलपोक, मद्रास-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/346/82-पी०एफ० 2]

S.O. 1011.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kilpauk Benefit Society Limited; No. 20, Ormes Road, Kilpauk, Madras-10, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(346)/82-PF-II]

का०आ० 1012.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी स्पेक्ट्रा इंजीनियरिंग कारपोरेशन, 44/3, आर० टी० संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद-38 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/347/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1012.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Spectra Engineering Corporation, 44/3 RT, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad-38, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(347)/82 PF-II]

का० आ० 1013.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोपाल इण्डस्ट्रीज एण्ड कम्पनी, डाकघर कुमारधूबी, जिला धनबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/348/82-पी०एफ० 2]

S.O. 1013.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gopal Industries and Company, Post Office Kumardhubi, District Dhanbad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(348)/82-PF-II]

का०आ० 1014.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बिहार एयर प्रोडक्टस लिमिटेड, फेज-V, ट्यो काम्पलेक्स, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर जिसके अंतर्गत (1) फेज V, ट्यो काम्पलेक्स, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, गम्हारिया, सिंहभूम (2) अवतार बिल्डिंग बिस्तुपुर, जमशेदपुर और (3) 108, पुरुलिया रोड, रांची स्थित उनकी शाखाएं भी हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/353/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1014.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bihar Air Products Limited, Phase V, Tayo Complex, Adityapur Industrial Area, Jamshedpur including its branches at (1) Phase V Tayo Complex, Adityapur Industrial Area Gambharia, Singhburn, (2) Avtar Building, Bistupur, Jamshedpur and and (3) 108, Purulia Road, Ranchi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19of should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(353)/82-PF-II]

का० आ० 1015.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वोल्हरो लिमिटेड, 115, पार्क लेन, पटनचेरु, मेडाक जिला, आंध्र प्रदेश, इसके अंतर्गत (1) 19, ग्राहम मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई और (2) 115, पार्क लेन, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश स्थित इसकी शाखाएं भी हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/366/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1015.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Volrho Limited, 115, Park Lane, Patancheru, Medak District, Andhra Pradesh including its Branches at (1) 19, Graham Road, Ballard Estate, Bombay and 115, Park Lane, Secundrabad-3, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees'

Provident Funds andMiscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(366)/82-PF. II]

का० आ० 1016.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैरीन एंड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड, परिश्रम भवनम् बशीर बाग, हैदराबाद, इसके अंतर्गत ए०पी०आई०ई० आटोनगर, विशाखापटनम-530012 स्थित इसका कारखाना भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/376/82-पी०एफ० 2]

S.O. 1016.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Marine and Communication Electronics India Limited, Parisrama Bhavanam, Bashir Bagh, Hyderabad including its factory at A.P.I.E. Autonagar, Visakhapatnam-530012, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(376)/82-PF. II]

का० आ० 1017.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दाधा एस्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड, 108, मीनिअप्पा नैकन स्ट्रीट, मद्रास-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/377/82-पी०एफ-2]

S.O. 1017.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dadha Estates (Private) Limited, 108, Myniappa Naicken Street, Madras-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(377)/82-PF. II]

का० आ० 1018.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सलेम ट्रेडिंग कंपनी, 198, लिंघी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 इसके अंतर्गत (1) त्रिची मार्ग, नमक्कल और (2) 69 सी० सी० मार्ग, सलेम स्थित इसकी शाखाएं भी हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/378/82-पी०एफ० 2]

S.O. 1018.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to establishment known as Messrs Salem Trading Company, 198, Linghi Chetty Street, Madras-1 including its Branches at (1) Trichy Road, Namakkal, and (2) 69 CC Road, Salem, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(378)/82-PF. II]

का० आ० 1019.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मालाबार ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रा० लि०, 8/363, नवरत्ना हाउस, मंथुरा रोड, कोचीन-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/483/82-पी०एफ० 2]

S.O. 1019.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Malabar Trading Corporation (Private) Limited, VIII/363, Navaratna House, Manthra Road, Cochin-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(483)/82-PF. II]

का० आ० 1020 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० आर० फाउन्ड्री, इलाइथोटम रोड, कोयम्बटूर-641004 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/230/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1020.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. R. Foundry, Ellaithottam Road, Coimbatore-641004, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(230)/82-PF. II]

का०आ० 1021.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्डस्ट्रियल इन्क इन्डस्ट्रीज, 12बी चैयरमैन ए० आर० ए० रोड, इन्डस्ट्रीयल बिल्डिंग, रेलवे कालोनी, शिवाकाशी (तमिलनाडु) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/278/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1021.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Industrial Ink Industries, 12-B, Chairman A.R.A. Road, Industrial Building, Rail-Way Colony, Sivakasi (Tamil Nadu), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fnuds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(278)/82-PF. II]

का० आ० 1022 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नटराजा राइस मिल्स, नं० 4327, ऊटाकारा स्ट्रीट, ईस्ट गेट, तंजावुर, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/279/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1022.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nataraja Rice Mills, No. 4327, Ottakara Street, East Gate, Thanjavur, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(279)/82-PF II]

का० आ० 1023. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पेपर सेल्स सेंटर, 3620-21 नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/305/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1023.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Paper Sales Centre, 3620-21, Netaji Subhash Marg, New Delhi-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(305)/82-PF-II]

का० आ० 1024. —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेविन इंडस्ट्रीस, 4, पुरुषावालकम हाई रोड, मद्रास-7, जिसके अन्तर्गत 27, मेट्टू स्ट्रीट, विल्लीवाकम, मद्रास स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/313/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1024.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishmest known as Messrs Ravin Industries, 4, Purasawalkam High Road, Madras-7 including its branch at 27, Mettu Street, Villivakkam, Madras-49, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35019(313)/82-PF. II]

का० आ० 1025 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० वी० एम० ज्वेलरी, 38, आरकोट रोड, वडापलानी, सालिग्राम, मद्रास-26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/314/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1025.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. V. M.

Rajeswari, 38, Arcot Road, Vadapalami, Saligramam, Madras-26, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(314)/82-PF. II]

का० आ० 1026.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरटिव होलसेल स्टोरस लिमिटड, मादीकेरी कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/315/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1026.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Coorg District Central Co-operative Wholesale Stores Limited, Madikeri, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(315)/82-PF. II]

का० आ० 1027.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवभारत पैकिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, 3-1-299 नीमबोली अड्डा हैदराबाद-27 जिसके अन्तर्गत उसकी (1) 27-23-69, गोपाल रेड्डी रोड, विजयवाड़ा और (2) 26-1-97, बोडारा रोड, विशाखापत्तनम पर स्थित शाखाएं भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/316/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1027.—Wheresa it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Navabharat Packaging (Private) Limited, 3-1-299, Nimboli Adda, Hyderabad-27 including its branches at (1) 27-23-69, Gopal Reddy Road, Vijayawada and (2) 26-1-97, Bowdara Road, Visakhapatnam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(316)/82-PF. II]

का० आ० 1028.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हरविंदर इलैक्ट्रोनिक्स, 59/1, नई मार्केट, लिबर्टी सिनेमा के निकट, नई दिल्ली-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/317/82-पी० एफ० 2]

S.O .1028.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harvinder Electronics, 59/1, New Market, Near Liberty Cinema, New Delhi-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(317)/82-PF-II]

का० आ० 1029 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नीता ट्रेडिंग कम्पनी, बी-72/3, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-52, जिसके अन्तर्गत 5332 गांधी मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली-6 स्थित इसका मुख्य कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/318/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1029.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Necta Trading Company B-72/3, Wazirpur Industrial Area, Delhi-52 including its Head Office at 5332, Gandhi Market, Sadar Bazar, New Delhi-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(318)/82-PF-II]

का० आ० 1030 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लोटस एस्टेट, पट्टीवीरन पट्टी पोस्ट आफिस ,मदुरै जिला, तमिलनाड, नामक स्थापन से सम्बद्ध निरोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/319/82-पी० एफ०-2]

S.O. 1030.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lotus Estate, Patti-Veeranpatti Post Office, Madurai District (Tamil Nadu) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(319)/82-PF-II]

का० आ० 1031.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजश्री पेपर इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र 1-8-583, आजमाबाद, हैदराबाद -20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/320/82-पी० एफ-2]

S.O. 1031.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajasri Paper Industries, Industrial Area, 1-8-583, Azamabad, Hyderabad-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(320)/82-PF-II]

का० आ० 1032.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ यूनियन हैदराबाद सर्किल, हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/321/82-पी० एफ-2]

S.O. 1032.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs State Bank of India Staff Union, Hyderabad Circle, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(321)/82-PF.II]

का० आ० 1033.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोयाप्पर इस्टेट, सिरुमलाई हिल्स, पट्टीवीरनपट्टी पोस्ट, मदुरै जिला, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/322/82-पी० एफ०-2]

S.O. 1033.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Royapper Estate, Sirumalai Hills, Pattiveeranpatti Post, Madurai District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(322)/82-PF.II]

का० आ० 1034.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पैक सेफ इंडस्ट्रीज ब्रुक्स इस्टेट, पेरियपालयथम्मन कोइल स्ट्रीट क्रोमपेट, मद्रास-44 नामक, स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/324/82-पी०एफ०-2]

S.O. 1034.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pack Safe Industries Brookes Estate, Periyapalayathamman Koil Street, Chromepet, Madras-44, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(324)/82-PF.II]

का० आ० 1035.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० पी० रेयान्स लिमिटेड, कमलापुरम, वारंगल जिला, आंध्रप्रदेश जिसके अंतर्गत 1-2-597/15 गगन महल, हैदराबाद स्थित उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और पांचवी मंजिल, सांची, 17, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 स्थित उसका दिल्ली कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/325/82-पी० एफ०-2]

S.O. 1035.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. P. Rayons Limited, Kamalapuram, Warangal District, Andhra Pradesh, including its Registered Office at 1-2-597/15, Gaganmahal, Hyderabad and Delhi Office, 5th Floor, Sanchi, 17, Nehru Place, New Delhi-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(325)/82-PF.II]

का० आ० 1036.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओवरसीज मैरिन प्रोडक्ट्स, रेड क्रास बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 52, मोन्टीथ रोड, एगमोर, मद्रास-8 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/330/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1036.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Overseas Marine Products, Red Cross Building, 2nd Floor, 52, Monteith Road, Egmore, Madras-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(330)/82-PF.II]

का० आ० 1037.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स श्री थण्डापानी राइस मिल, पलंगनाथम, मदुरई-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/331/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1037.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Thandapani Rice Mill, Palanganatham, Madurai-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(331)/82-PF.II]

का० आ० 1038.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वर्मा इन्टरप्राइजेज, पद्मविलासम रोड, फोर्ट त्रिवेन्द्रम, केरल जिसके अंतर्गत (1) पी० के० पेट्रोल पम्प, कोदियार और (2) फ्यूल सेन्टर, फोर्ट, त्रिवेन्द्रम स्थित उसकी शाखाएं भी हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/332/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1038.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Verma Enterprises, Padmavilasam Road, Fort, Trivendrum, Kerala, including its Branches at (1) P.K.P. Petrol Pump, Kawdiar and (2) Fuel Centre, Fort, Trivendrum, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(332)/82-PF.II]

का० आ० 1039.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जया इन्डस्ट्रीज, 2-1-392/1/3, यूनिवर्सिटी रोड, नालाकुन्ता हैदराबाद-44 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019/333/82-पी० एफ० 2]

S.O. 1039.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jaya Industries, 2-1-392/1/3, University Road, Nallakunta, Hyderabad-44, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(333)/82-PF.II]

का. आ. 1040.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे.एस. इलैक्ट्रिकल, ए-6, नरायना औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-28 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/334/82-पी. एफ. 2]

S.O. 1040.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs J. S. Electricals, A-6, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-28, have agdeed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(334)/82-PF.II]

का. आ. 1041 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईस्टर्न एक्सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, सी-2 कम्युनिटी सेन्टर, नरायना विहार, नई दिल्ली-28 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/335/82-पी.एफ. 2]

S.O. 1041.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Eastern Export Services (India) Private Limited, C-2, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(335)/82-PF II]

का. आ. 1042 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रीतू ट्रेडिंग कारपोरेशन, बी-62/4, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2 नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/336/82-पी.एफ. 2]

S.O. 1042.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ritu Trading Corporation, B-62/4, Narayana Industrial Area, Phase-II, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(336)/82-PF II]

का. आ. 1043 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केशोराम रोशन लाल अहूजा (प्राइवेट) लिमिटेड, ई-48/6, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस 2, नई दिल्ली, जिसके अंतर्गत 1080, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006, स्थित उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/337/82-पी.एफ. 2]

S.O. 1043.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kesho Ram Roshan Lal Ahuja (Private) Limited, E-48/6, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi including its Registered Office at 1080, Kashmere Gate, Delhi 6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(337)/82-PF.II]

का. आ. 1044 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है के मैसर्स एशियन आर्ट प्रिंटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, देश बंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/338/82-पी.एफ. 2]

S O. 1044.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Asian Art Printers (Private) Limited, Desh Bandhu Gupta Road, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(338)/82-PF.II]

का. आ. 1045 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी नागमल्लेश्वर राव लक्ष्मी बस बाडी बिल्डिंग वर्क्स के स्वामी, विजय-नगरम् (हैदराबाद) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/339/82-पी. एफ.-2]

S.O. 1045.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. Nagamalleswara Rao, Owners of Lakshmi Bus Body Building Works, Vizianagaram (Hyderabad) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(339)/82-PF.II]

का. आ. 1046 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फेंसी मैटल वर्क्स, 74, पेरूमल चेट्टियार स्ट्रीट, करैकुडी-1, तमिलनाडु नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/341/82-पी. एफ. 2]

S.O. 1046.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fancy Metal Works, 74, Perumal Chettiar Street, Karaikudi-1, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(341)/82-PF.II]

का. आ. 1047 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वपन कुमार जाना, जोधा, झिरपानी, राउरकेला-2, सुन्दरगढ़, उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एस-35019/342/82-पी. एफ. 2]

S.O 1047.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Swapan Kumar Jana, Jodha, Jhirpani, Rourkela-2, Sundargarh, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and MiscellaneousProvisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(342)/82-PF.II]

का. आ. 1048 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अलाद्दीन अन्सारी, ठेकेदार, आनन्द भवन मार्ग, राउरकेला-1, सुन्दरगढ़, उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/343/82-पी.एफ. 2]

S.O. 1048.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Alauddin Ansari, Contractor, Anand Bhavan Road, Rourkela-1 Sundergarh, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(343)/82-PF.II]

का. आ. 1049 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. एच. खान, आनन्द भवन मार्ग, राउरकेला-1, सुन्दरगढ़, उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/344/82-पी. एफ.-2]

S.O. 1049—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. H. Khan, Anand Bhavan Road, Rourkela-1, Sundergarh, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(344)/82-PF.II]

का. आ. 1050 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीराम फिनर्स, पोस्ट बोक्स नं. 1, मेलगमपट्टी गांव, दिन्दीगुल रोड, बाटलागुन्डु, मदुरई-624202, तमिलनाडु राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/1/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1050.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shriram Fibres, Post [illegible] Village, Dindigul Road, Batlagundu, [illegible] Nadu State), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(1)/83-PF.II]

का. आ. 1051.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनाइटिड मर्केन्टाइल एजेन्सीज, 135, थाम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-60001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/2/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1051.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs United Mercantile Agencies, 135, Thambu Chetty Street, Madras-600001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(2)/83-PF.II]

का. आ. 1052.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओरियन्टल एक्सपोर्ट ट्रेड कम्पनी, पाटामाटा, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/3/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1052.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Oriental Export Trade Company, Patamata, Vijayawada, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(3)/82-PF.II]

का. आ. 1053.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मनिल एन्टर प्राइजिज, 6/2, 5वां क्रास, ओ.टी.सी. रोड, बंगलौर-53, कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/4/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1053.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manil Enterprises, 6/2, 5th Cross, O.T.C. Road, Bangalore-53, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(4)/83-PF.II]

का. आ. 1054.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोमथी संकर ट्रेडिंग कम्पनी, यार्न एण्ड क्लाथ मर्चेन्टस, वैस्ट न्यू स्ट्रीट, अम्बासमद्रम-627401, जिला-तिरूनेलवेली, तमिलनाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं एस-35019/5/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1054.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gomathi Sankar Trading Company, Yarn & Cloth Merchants, West New Street, Ambasamudram-627401, Tirunelveli District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(5)/83-P.F.II]

का. आ. 1055.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हाई-डिजाइन, सं. 4, केसरिन स्ट्रीट, पाण्डीचेरी-605001, तमिल नाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम,

1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करत हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस-35019/6/83-पी. एफ. 2]

S O. 1055.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hidesign, No 4, Caserene Street, Pondicherry-605001, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(6)/83 PF II]

का. आ. 1056 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट डेवेलोप्मेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, धर्मपुरी-636705 तमिल नाडु नामक स्थापन से सहबद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करत हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस-35019/7/83-पी. एफ. 2]

S O. 1056.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dharmapuri District Development Corporation Limited, Dharmapuri-636705 (Tamil Nadu), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(7)/83 PF II]

का. आ. 1057 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुमार एण्ड कम्पनी, 6-15-7-ए, ईस्ट कोस्ट पाइट कालोनी, विशाखापट्टनम, आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स एस-35019/8/83-पी. एफ. 2]

S O 1057—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kumar and Company, 6-15-7A, East Coast Point Colony, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35019(8)/83 PF II]

का. आ. 1058 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मद्रास इलैक्ट्रीकल एजेन्सीज, 10, मूकर नल्लामुथू स्ट्रीट, मद्रास-600001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस-35019/9/83-पी. एफ. 2]

S.O. 1058—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madras Electrical Agencies, 10, Mooker Nallamuthu Street, Madras-600001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(9)/83-PF II]

का. आ. 1059 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मी चेन्नाकेसव स्वामी मशीन स्लेट फैक्ट्री, मार्कपुर, जिला प्रकाशन, आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस-35019/10/83-पी. एफ. 2]

S O 1059—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lakshmi Chennakesawa Swamy Machine Slate Factory, Markapur, Prakasham District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35019(10)/83-PF II]

का. आ. 1060 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रूरल डेवलोप्मेंट सर्विस, रूहैना, 2-13, तारनाका, सिकन्दराबाद-500017 आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम,

1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती हैं ।

[सं. एस-35019/11/83-पी. एफ. 2]

S.O. 1060.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rural Development Advisory Service, Ruhaina, 2-13, Tarnaka, Secunderabad-500017, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(11)/83-PF.II]

का. आ. 1061 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वारालक्ष्मी कैटलफीडस कम्पनी, पाटामाटा, विजयवाडा-620006, आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/12/83-पी. एफ.-2]

S.O. 1061.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Varalakshmi Cattlefeeds, Company, Patamata, Vijayawada-520006, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(12)/83-PF.II]

का. आ. 1062 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टैन्डर्ड स्प्रिंग्स एण्ड सीट मैटल्स, प्रथम मंजिल, 4/399, अवनाशी रोड, पी. एन. पालायाम, कोयम्बटूर-37, तमिल नाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती हैं ।

[सं. एस-35019/13/83-पी. एफ. 2]

S.O. 1062.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Standard Springs and Sheet Metals, 1st Floor, 4/399, Adanashi Road, P. N. Palayam, Coimbatore-37, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(13)/83-PF.II]

का. आ. 1063 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रीमिनेन्ट एयरकन्डीशनिंग एण्ड रेफ्रीजेरेशन इंजीनियर्स, 100, नंगमबक्कम हाई रोड, मद्रास-600034 जिसके अन्तर्गत उसकी 75, चूलाई हाई रोड, वेपारी, मद्रास-7 स्थित उनकी फैक्टरी भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/14/83-पी. एफ. 2]

S.O. 1063.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Preeminent, Airconditioning and Refrigeration Engineering, 100, Nungambakkam High Road, Madras-600034 including its factory at 75, Choolai High Road, Vepary, Madras-7, have agreed that the pdovisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(14)/83-PF.II]

का. आ. 1064 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी. रामाथुलासम्मा ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रेक्टर, मदुक्कारई-641105, तमिल नाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/16/83-पी. एफ. 2]

S.O. 1064.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B. Ramathulasamma, Transport Contractor, Madukkarai-641105, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Pdovident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(16)83-PF.II]

का. आ. 1065 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है मैसर्स संकर इलैक्ट्रो प्लेटर्स, यूनिट जी, एन्फील्ड इंडिया कम्पलैक्स, सिंगमपुनारी, जिला रामनाड, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/17/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1065.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sankar Electro Platers, Unit G, Enfield India Complex, Singampunari, Ramnad District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establisment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(17)/83-PF.II]

का. आ. 1066 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है मैसर्स साहनी पैरिस रोन प्राइवेट लिमिटेड ए-5, उप्पल इण्डस्ट्रियल इस्टेट, हैदराबाद-39 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं., एस-35019/18/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1066.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sahney Paris Rhone (Private) Limited, A-5, Uppal Industrial Estate, Hyderabad-39, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(18)/83-PF.II]

का. आ. 1067 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पैनिनसुलर केबल्स एण्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/19/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1067.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Peninsular Cables and Products Private Limited, Industrial Estate, Anantapur, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(19)/83-PF.II]

का. आ. 1068 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजय दुर्गा औफसेट प्रिन्टर्स, 100-फीट रोड, ओटोनगर, विजयवाडा-7, आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एम-35019/20/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1068.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vijay Durga Offset Printers, 100 Feet Road, Autonagar, Vijayawada-7, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(20)/83-PF.II]

का. आ. 1069 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामजी लैमिनेट्स, सं. 3, रेलवे फीडर रोड, चोलापुरम साउथ-626139, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/21/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1069.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ramji Laminates, No. 3, Railway Feeder Road, Cholapuram South-626139, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Pdovisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(21)/83-PF.II]

का. आ. 1070 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुदर्शन केरामिक्स, पालामानेर, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/22/83-पी.एफ 2]

S.O. 1070.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sudarsana Ceramics Palamaner, Chittoor District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(22)/83-PF.II]

का. आ. 1071 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आनन्द ट्रेडिंग कम्पनी, नवरात्रा हाउस, 8/363 मन्थरा रोड, कोचीन-682002, जिला अरनाकुलम, केरल राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/23/83-पी.एफ. 2]

S.O. 1071.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anand Trading Company, Navaratra House, VIII/363, Manthra Road, Cochin-682002, Ernakulam District, Kerala State, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(23)/83-PF.II]

का.आ. 1072.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईस्टर्न क्रोम टेन्निंग कारपोरेशन, सोलूर, अम्बर-635802, तमिल नाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/24/83-पी. एफ. 2]

S.O. 1072.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Eastern Chrome Tanning Corporation, Solur, Ambur-635802, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(24)/83-PF.II]

का. आ. 1073 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है मैसर्स एल.एस.पी. रिफाइनरीज, पोस्ट बोक्स नं. 905, 297, सुरामंगलाम् मेन रोड, पल्लापट्टी, सालम-636009, तमिल नाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/25/83-पी. एफ. 2]

S.O. 1073.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs L.S.P. Refineries P.B. No. 905, 297—Suramangalam Main Road, Pallapati Sulem-636009, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(25)/83-PF.II]

का. आ. 1074 .—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मरकाजी मक्तबा इस्लामी, 1358, चितली कबर, दिल्ली-110006 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019/26/83-पी एफ.-2]

ए.के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 1074.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Markazi Maktaba Islami, 1353, Chitli Gabar, Delhi-110006, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(26)/83-PF. II]

New Delhi, the 29th January, 1983

CORRIGENDUM

S.O.1075.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 386, dated the 16th January, 1982 published at page 428 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30th January, 1982 in line 4, for 'Filcco' read 'Filco'.

[No. S. 35018(16)/81-PF. II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1983

का०आ० 1076.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, । दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार इन्द्रप्रस्थ-इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

"लगभग 1.73 हैक्ट० (4.286 एकड़) का क्षेत्र जो क्षेत्र एफ-11 (इंजीनियरिंग कालेज) में पड़ता है और जो "कुतब होटल कामप्लेक्स" के नाम से प्रसिद्ध है तथा 30.48 मीटर (100 फुट) चौड़े मार्ग के दक्षिण में स्थित है, का भूमि उपयोग "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं" (सांस्थानिक) से बदल कर "व्यावसायिक" (होटल) में किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के नक्शे निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे ।

[सं० एफ० 10(7)/76-एम०पी०]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 12th February, 1983

S.O. 1076.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address :—

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 1.73 hects. (4.286 acres) falling in Zone F-11 (Engineering College) known as 'Qutab Hotel Complex' and located in the south of 30.48 mtrs. (100 ft. wide) road, is proposed to be changed from 'Public and Semi-Public Facilities' (Institutional) to 'Commercial' (Hotel)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[F. 10(7)/76-M.P.]

का. आ. 1077 .—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें :—

संशोधन :

धारा-ए (मुख्य योजना के मूल पाठ के क्षेत्रीय विनियम अध्याय-2) में लिखित पैरा-5 जो "उपयोग क्षेत्रों में आवश्यकताओं से सम्बन्धित व्यवस्थाएं" के शीर्षक के अन्तर्गत है, तथा जिसमें क्षेत्रीय व उप-खण्ड सम्बन्धी विनियमों का वर्णन है ।

1. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 55 पर बाई ओर के नोट (3) जिसे अधिसूचना संख्या के-12014/6/75-यू०डी०1 डी०डी० 2ए (आयातन-3) दिनांक 29-10-82 द्वारा संशोधित किया गया था, के बाद उसमें निम्नलिखित नोट (4) जोड़ा जाना है :—

"(4) धनता की गणना हेतु बरसाती मंजिल को आवासीय इकाई के रूप में माना जाएगा ।"

2. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ -57 पर दाई ओर (डी) भूखण्ड का अभिमुख, के ऊपर पैरा (1) के उप-पैरा (सी) के अन्तिम पैरा की पहली एवं तीसरी पंक्तियों में क्रमशः 25 तथा 500 की संख्याओं के स्थान पर अब क्रमशः 50 तथा 1000 किया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इल्स्टेट, नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों सहित मुख्य योजना की प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी ।

[सं० एफ० 3(154)/67-एम०पी०]

नाथू राम सचिव,

S.O. 1077.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion to the proposed modifica-

tions may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days, from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

In paragraph (5), entitled 'Provision Regarding requirements in use zones' occuring in Section (A), (Zoing Regulations-Chapter II of the text of Master Plan), dealing with the zoning and sub-division regulations.

1. At page 55, left hand side of the Master Plan for Delhi, after note (3) amended vide notification No. K-12014/6/75-UDI/DDIIA (Col. III) dated 29-10-82, the following note (4), shall be inserted namely :

(4) "For the purpose of density calculation, Barsati Floor shall be reckoned as a dwelling unit".

2. "At page-57, right hand side of the Master Plan for Delhi, last para of sub-para (c) of para (i) above (d) frontage of plots, the figures of 25 and 500 occuring in the first and third line respectively are proposed to be substituted by 50 and 1000 respectively".

A copy of the Master Plan incorporating the proopsed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate New Delhi on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(154)/67-M.P.]

NATHU RAM, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983